MERIKHETI

मेरी खेती

Page No. 01-46 दिसंबर 2022

- खेत खलियान
- सब्ज़ी
- फल
- मशीनरी
- मौसमी व अन्य कृषि सुझाव
- सरकारी नीतियां
- किसान समाचार

श्री छेदालाल पाठक
(संरक्षक मार्गदर्शक)

डॉ. एमसी शर्मा,
सेवानिवृत्त निदेशक एवं
कुलपति आईवीआरआई इज्जतनगर

प्रो. ए.पी. सिंह
पूर्व कुलपति वेटनरी
विश्वविद्यालय मथुरा

डॉ.एस.के.गर्ग
कुलपति राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ
वेटनरी एंड एनिमल साइंस

डॉ.ओमवीर सिंह
निदेशक बीज प्रमाणीकरण
(सेवानिवृत्त) उत्तर प्रदेश

डॉ. उदय भान सिंह
डीन कृषि महाविद्यालय कुम्हेर
भरतपुर राजस्थान

श्री सुधीर अग्रवाल
(प्रगतिशील किसान)

दिलीप यादव
(शिक्षक,मेडीसेवी)

तेजपाल सिंह
(प्रगतिशील किसान)

कृष्ण पाठक
(शिक्षक,मेडीसेवी)

बागवानी किसानों के लिए समस्या बनती जलवायु परिवर्तन, कैसे बचाएं अपनी उपज

औद्योगिक क्रांति के बाद से पूरे विश्व भर में ग्लोबलवार्मिंग (GLOBAL WARMING) और जलवायु परिवर्तन (CLIMATE CHANGE) केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (ECOSYSTEM) के लिए एक समस्या बनकर उभरा है।

एक समय जिस स्थान पर अच्छी बारिश होती थी आज वहां हर वर्ष सूखा पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण जलवायु में परिवर्तन ही है। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर रहने वाले हर प्रजाति को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ता है, इसी नुकसान की वजह से पिछले कुछ वर्षों से फलों के लिए बागवानी खेती करने वाले किसान भाइयों को उपज में काफी कमी देखने को मिली है। उत्तरी भारत के राज्यों में फल उगाने वाले किसान अब नई वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से कुछ उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत में लगभग 7 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में फल उगाए जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 93 मिलियन टन फल प्राप्त होते हैं।भारतीय बागवानी कृषि विश्व भर के उत्पाद में लगभग 10% हिस्सेदारी निभाती है। आम, केला और अमरूद तथा अनार, अंगूर और पपीता जैसे प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।

वैश्विक तापमान में परिवर्तन और बारिश के पैटर्न में हुए बदलाव की वजह से फलदार पौधों में निम्न नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिले हैं :

तापमान में वृद्धि होने के कारण किसी भी पौधे पर लगने वाले फलों की परिपक्वता का समय कम हो जाता है। इसकी वजह से वह जल्दी तैयार हो जाते हैं और इन्हें बाजार में जल्दी बेचना पड़ता है, इससे फलों के भंडारण की संभावना कम हो जाती है और उन्हें तुरंत भेजना पड़ता है। इस वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते और उनका मुनाफा कम हो जाता है।

इसके अलावा किसी स्थान पर अधिक वर्षा या सूखा पड़ने पर फसल की उत्पादकता पूरी तरीके से कम होने के साथ ही वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है, जिस कारण फसल की गुणवत्ता पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिला है।

अधिक कार्बन-डाइऑक्साइड की वजह से फलों में स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे इन फलों के सेवन से रक्तचाप और शुगर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है।

अधिक ग्लूकोज संचित करने वजह से इन फलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है।

इसके अलावा विश्वत रेखा (EQUATORIAL AREA) के आसपास वाले क्षेत्रों में आसमान में अधिक समय तक बादल छाए रहने की वजह से वहां पर उगाए जाने वाले आम और अमरूद के फलों में एस्कोरबिक अम्ल (ASCORBIC ACID) की मात्रा घट जाती है, जिस वजह से फल में पाई जाने वाली मिठास कम हो जाती है और फुल पूरी तरह से फीका लगता है। इस कारण उसकी बाजारू मांग में भी कमी देखने को मिलती है।

बदली हुई जलवायु परिस्थितियां नए प्रकार के रोगों को जन्म दे रही है, तापमान में बढ़ोतरी होने से कई सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया पौधों की जड़ों और तने को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा इन बैक्टीरिया की वर्द्धि दर भी तेज हो जाती है, जो बाद में सीधे फलों को ही खाने लगते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो लागत को बढ़ाकर आर्थिक दबाव पैदा करते हैं।

हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक विधियों की मदद से इसे कम भले ही किया जा सकता है।

गर्मी के मौसम में पेड़ों की कटाई-छंटाई कम करनी चाहिए और पेड़ के तने और उसकी मोटी शाखाओं को सफेद रंग से पुताई कर देने पर सूरज से आने वाली किरण का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे फल के पकने में लगने वाला समय अधिक हो जाता है और किसान को अच्छी उपज के साथ ही अच्छा मुनाफा हो पाता है।

अधिक गर्मी पड़ने से बाग के क्षेत्र में नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी को बरकरार बनाए रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्र की नमी की जांच करनी चाहिए और बाग की नियमित और उचित सीमित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए।

यदि आप के बाग में पिछले सीजन के कुछ पौधे बचे हुए हैं और उनसे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें काटकर उनकी पलवार बना देनी चाहिए, जिससे बाग के क्षेत्र के तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद का इस्तेमाल करने से पौधों में नमी बनी रहती है और उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। इससे रासायनिक उर्वरक खरीदने का खर्चा भी बच जाता है।

अधिक ठंड पड़ने वाले क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए पतझड़ के समय पौधों के नीचे गिरी हुई सूखी टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा कर जलाने से भी फायदा हो सकता है।

इसके अलावा पत्तियों को जलाने से होने वाले धुआं की वजह से कई प्रकार के छोटे कीट और फल मक्खी पौधों से दूर भाग जाते हैं, इससे आपकी फलों की निरन्तर सुरक्षा भी हो पाती है।

फलों की छोटी पौध को हमेशा पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए लगाना चाहिए, इससे सूरज की किरणों का कम प्रभाव पड़ता है।

दिलीप यादव
मेरी खेती

खेत खलियान

कानपूर आईआईटी द्वारा विकसित कम जल खपत में अधिक पैदावार करने वाला गेंहू का बीज

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur; Indian Institute of Technology) द्वारा गेहूं की नवीनतम किस्म को विकसित किया है, जिसकी बुआई करने के उपरांत 35 दिनों तक पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।

उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं बिहार समेत ज्यादातर राज्य धान की कटाई करने के उपरांत गेहूं की बुआई करते हैं। दरअसल, अभी कई राज्यों में गेहूं की बुआई प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके लिए किसान बाजार से उम्दा किस्म के गेहूं के बीज की खरीद कर रहे हैं ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा कर सकें। लेकिन कुछ किसान अभी तक धान की कटाई भी नहीं कर पाए हैं। अब किसानों के लिए एक ऐसे गेहूं की उम्दा किस्म बाजार में आ चुकी है, जो कि कम जल संचय करने के बावजूद भी अच्छी पैदावार करती है। फसल का उत्पादन बेहतरीन होता है।

इस गेंहू की किस्म की मुख्य विशेषता क्या हैं ?

आईआईटी कानपुर के द्वारा गेहूं की नवीन एवं उम्दा किस्म को विकसित करने के साथ साथ किसानों को अत्यधिक जल की आपूर्ति में खर्च होने से भी बेहद राहत दिलाई है, क्योंकि गेंहू की इस किस्म में बुवाई के उपरांत 35 दिनों तक पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह गेहूं की किस्म, गर्मी एवं गर्म हवाओं से भी प्रभावित नहीं होती है, साथ ही इन गेंहू को झुलसने या सूखने का भी कोई खतरा नहीं होता। किसानों को गेंहू में पानी लगाने के लिए काफी समय का अंतराल तो मिलेगा ही, साथ ही जल की आवश्यकता भी कम होने के कारण उनकी लागत में कमी आयेगी।

इस किस्म के गेंहु में कितने दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती ?

आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी एलसीबी फर्टिलाइजर (LCB Fertilizers) गेहूं का नैनो कोटेड पार्टिकल सीड तैयार कर चुका है, जिसकी विशेषता है कि इसकी बुवाई करने के उपरांत 35 दिनों तक फसल की सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एलसीबी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि अभी तक जो उनके द्वारा रिसर्च हुई है वह कभी भी निष्फल नहीं रही है। शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि गेहूं के बीज में नैनो पार्टिकल एवं सुपर एब्जार्बेंट पॉलिमर की कोटिंग हुई है, जिसके तहत गेहूं पर लगा पॉलिमर 268 गुना ज्यादा पानी संचय करता है। अधिक जल संचय के कारण ही गेहूं की फसल में 35 दिनों तक सिंचाई की कोई आवश्यता नहीं होती है।

इस गेंहू की किस्म को तैयार होने में कितना समय लगता है ?

उपरोक्त में जैसा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित ज्यादातर जनपदों में धान की कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है। अब गेहूं की बुवाई करते वक्त वहाँ के किसान इस गेंहू की किस्म के बीज को प्रयोग करें तो उनको जलपूर्ति के लिए करने वाले खर्च में बेहद बचत होगी। इस बीज की खासियत है कि यह 78 डिग्री तापमान को झेलने के बाद भी ज्यों की त्यों खड़े रहेंगे। साथ ही, इस किस्म के गेंहू की फसल 120 से 150 दिन में मात्र दो सिंचाई होने के बाद पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है।

1 एकड़ में 55 टन, इस फसल की खेती करने वाले किसान हो जाएंगे मालामाल

भारत में गन्ने की खेती काफी मात्रा में होती है। गन्ना की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने गन्ने की एक नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म से किसानों को काफी फायदा होगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस किस्म से गन्ने का उत्पादन किया जाये, तो पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा उत्पादन होगा। इस खबर से गन्ने की खेती करने वाले किसानो के बीच काफी खुशी की लहर है। खास बात यह है कि गन्ने की इस नई किस्म का नाम Co86032 है, यह कीट प्रतिरोधी है। इस नई गन्ने की खेती करने वाले किसानों के बीच काफी उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) राज्य की केरल मिशन परियोजना ने गन्ने की किस्म Co86032 को परखा है। Co86032 की खासियत यह है कि इसे सिंचाई की कम जरूरत पड़ेगी, यानी गन्ने की Co86032 किस्म कम पानी में तैयार हो जाती है। साथ ही यह कीटों के हमले के खिलाफ लड़ने में ज्यादा लाभ दायक है, क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक मात्रा मे पाई जाती है, साथ ही इससे अधिक उपज किसानों को मिलेगा। वहीं, परखे हुए अधिकारियों ने बताया कि सस्टेनेबल गन्ना पहल (एसएसआई) के जरिए साल 2021 में एक पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया था। दरअसल, एसएसआई गन्ने की खेती की एक ऐसी विधि है जो कम संसाधन, कम बीज, कम पानी एवं कम से कम खाद का प्रयोग होता है।

एसएसआई का उद्देश्य कम संसाधन कम लागत मे खेती के उपज को बढ़ाना है

कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक केरल के मरयूर में पारंपरिक रूप से गन्ने के ठूंठ का उपयोग करके Co86032 किस्म की खेती की जाती थी। लेकिन पहली बार गन्ने की पौध का इस्तेमाल खेती के लिए किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने गन्ने की खेती के लिए एसएसआई पद्धति पहले ही लागू कर दी है। नई एसएसआई खेती पद्धति का उद्देश्य किसानों की कम लागत पर अच्छी उपज बढ़ाना है।

5,000 पौधे की ही जरूरत पड़ेगी

मरयूर के एक किसान विजयन की जमीन पर पहले इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। इस प्रोजेक्ट की सफलता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक एकड़ भूमि में 55 टन गन्ना प्राप्त हुआ है। ऐसे एक एकड़ में औसत उत्पादन 40 टन होता है और इसे प्राप्त करने के लिए 30,000 गन्ना स्टंप की आवश्यकता होती है। हालांकि, यदि आप रोपाई के दौरान पौध का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको केवल 5,000 पौधे की ही जरूरत पड़ेगी। विजयन ने बताया कि फसल की अच्छी उपज को देखते हुए अब हमारे क्षेत्र के कई किसानों ने एसएसआई विधि से गन्ने की खेती करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

स्वाद में बेजोड़ मरयूर गुड़

प्रति एकड़ गन्ने के स्टंप की कीमत 18,000 रुपये है, जबकि पौधे की लागत 7,500 रुपये से भी कम है। अधिकारियों के अनुसार, एक महीने पुराने गन्ने के पौधे शुरू में कर्नाटक में एक एसएसआई नर्सरी से लाए गए और चयनित किसानों को वितरण किया गया। मरयूर में पौधे पैदा करने के लिए एक लघु उद्योग नर्सरी स्थापित की गई है। मरयूर और कंथलूर पंचायत के किसान बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करते हैं। मरयूर गुड़ अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कि सुझाई इस वैज्ञानिक तकनीक से करें करेले की बेमौसमी खेती

करेले की खेती करने वाले किसान भाई यह तो जानते ही हैं कि इसकी फसल का उत्पादन गर्मियों के मौसम में किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जागरूक होती जनसंख्या भारतीय बाजार में करेले की मांग को पूरे वर्ष भर बनाए रखती है। इसीलिए अब विश्व भर के वैज्ञानिकों के साथ भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने भी पॉली-हाउस तकनीकी की मदद से बिना मौसम के ही फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कमर कस ली है।

करेला (Karela; Bitter Gourd or Bitter Melon) एक व्यावसायिक फसल है जो किसान को बेहतर आय देने के अलावा कई स्वास्थ्यवर्धक फायदे भी उपलब्ध करवाती है।

पॉली-हाउस तकनीकी की मदद से अब सर्दियों के मौसम में भी करेले की वैज्ञानिक खेती की जा सकती है।

कैसे करें करेले के लिए पॉलीहाउस में भूमि की तैयारी ?

एक बार पॉलीहाउस को सेट-अप करने के बाद उसमें बड़ी और थोड़ी ऊंचाई वाली क्यारियां बनाकर उन्हें पूरी तरीके से समतल कर देना चाहिए।
जैविक खाद का इस्तेमाल कर इन क्यारियों में डाली गई मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाया जाना चाहिए, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट खाद को भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
रासायनिक उर्वरकों पर विश्वास रखने वाले किसान भाई फार्मेल्डिहाइड का छिड़काव कर क्यारियों को पुनः पॉलिथीन से ढककर कम से कम 2 सप्ताह तक छोड़ देना चाहिए।
इस प्रक्रिया की मदद से खेत की मिट्टी में पाए जाने वाले कई सूक्ष्म कीटों को नष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार तैयार मिट्टी भविष्य में करेले के बेहतर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पॉलीहाउस की जलवायु को कैसे करें निर्धारित ?

किसी भी पॉली-हाउस के अंदर फसल की आवश्यकता अनुसार तापमान को कम या अधिक किया जा सकता है।

करेले की खेती में रात के समय तापमान को 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखना चाहिए, जबकि दिन में इसे 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखना चाहिए।

इसके अलावा किसी भी फसल की बेहतर वृद्धि के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है, पॉली-हाउस के अंदर आद्रता को कम से कम 30% रखना चाहिए।

ऊपर बताई गई जानकारी से आर्द्रता या तापमान का स्तर कम होने पर फसल की वृद्धि दर पूरी तरीके से रुक सकती है और फलों का आकार अनियमित होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।

कैसे करें करेले के बीज की रोपाई और दो पौध के मध्य की दूरी का निर्धारण :

यदि कोई किसान भाई मैदानी क्षेत्र वाले इलाकों में सर्दियों के समय में करेले की फसल का उत्पादन करना चाहता है तो, बीज का रोपण सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के शुरुआती दिनों में किया जा सकता है।

करेले की दो पौध के मध्य कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी बनाकर रखनी चाहिए और दो अलग-अलग कतारों के 60 से 70 सेंटीमीटर दूरी रखना अनिवार्य है।

करेले की फसल के बड़ी होने के समय रखें इन बातों का ध्यान :

एक बार बीज के रोपण हो जाने के बाद पौध 15 से 20 दिनों में बड़ी होनी शुरू हो जाती है। करेले की खेती करने वाले किसान भाई जानते होंगे कि फसल के बड़े होने के समय शाखाओं की कटाई-छंटाई करना अनिवार्य होता है।

सब्ज़ी

शुरुआती दिनों में एक या दो शाखाओं को काट कर हटा दिया जाना चाहिए, इसके अलावा शाखाओं को काटते समय पोषक तत्वों वाली शाखाओं को काटने से बचना चाहिए और केवल पुरानी शाखा को ही काटना चाहिए।

उसके बाद किसी पौध के मुख्य तने और अलग-अलग शाखाओं को रस्सी की सहायता से उसके निचले हिस्से में बांधकर छत की दिशा में ले जाकर बांध दिया जाता है।

पौधे के तने और ऊपर के हिस्से को छत से बांधने के लिए किसी कठोर तार का इस्तेमाल करना चाहिए अन्यथा बड़े होने पर पौधे का वजन अधिक होने से रस्सी के टूटने का खतरा बना रहता है।

पौधे के चारों तरफ रस्सी बांधते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि हाल ही में पल्वित हुए छोटे फूल और तने को नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं तो उत्पादन में भारी कमी देखने को मिल सकती है।

पॉलीहाउस में कैसे करें सिंचाई का बेहतर प्रबंधन :

आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान युवा किसान पॉलीहाउस में उत्पादन के लिए बून्द-बून्द सिंचाई विधि (Drip irrigation) को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।

शुरुआत के दिनों में करेले के पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही पानी दिया जाना चाहिए, अधिक पानी देने पर उसमें कई प्रकार के रोग लगने की संभावना होती है।

डंपिंग ऑफ (Damping off) रोग भी पानी के अधिक इस्तेमाल से ही होता है।

कैसे करें करेले के उत्पादन में उर्वरकों का बेहतर तरीके से प्रबंधन :

शुरुआती दिनों में जैविक खाद का इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी की जांच करवा कर कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों का ही उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए।

यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त है तो यूरिया और डीएपी खाद का इस्तेमाल ना करें, किसी भी मिट्टी में पहले से उपलब्ध पोषक तत्व को बाहर से उर्वरक के रूप में डालने से उगने वाली फसल की उत्पादकता तो कम होती ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी काफी नुकसान होता है।

तैयार हुए करेले के फलों को तोड़ने की विधि :

एक बार बीज बुवाई के बाद लगभग 60 से 70 दिनों में करेला लगना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से पक कर तैयार हुए करेले जल्दी ही लाल रंग के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत तोड़ना आवश्यक होता है।

फलों को तोड़ने के लिए चाकू या कैंची का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फलों को खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पौधे का भी नुकसान हो सकता है।

करेले के फल जब कोमल और हरे रंग के होते हैं तभी तोड़ना अच्छा होता है, नहीं तो इन्हें मंडी में पहुंचाने के दौरान परिवहन में ही यह पककर लाल हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से स्वादहीन हो जाते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई इस पॉलीहाउस तकनीक का इस्तेमाल कर किसान भाई प्रति हज़ार वर्गमीटर पॉलीहाउस में 100 क्विंटल तक करेले की सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं

आशा करते हैं merikheti.com के द्वारा किसान भाइयों को इस तकनीक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आप भी भविष्य में ऊपर दी गई जानकारी का सही फायदा उठाकर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे।

खीरा की यह किस्म जिससे किसान सालों तक कम लागत में भी उपजा पाएंगे खीरा

हम लोग सलाद में सबसे महत्वपूर्ण खीरा (cucumber ; kheera) को मानते हैं, इसके अलावा भी आजकल खीरा का उपयोग बहुत बढ़ गया है। देश ही नहीं विदेश में भी खीरा की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके लिए खीरा निर्यात के मामलों पर भी काफी ऊपर है। अब देखा जा रहा है, कुछ दिनों से किसान बिना सीजन में खीरा को उगाने के लिए परेशान हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको जानकर आप काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि किसान को अब खीरा उगाने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आईसीएआर (ICAR) के वैज्ञानिकों ने अब ऐसे खीरे की किस्म को विकसित किया है, जिसमें ना ही किसी मौसम की बाधा आती है, नहीं बीज की टेंशन। आईसीएआर के वैज्ञानिकों के अनुसार यह बीज रहित खीरा (seedless cucumber) जिसका नाम डीपी-6 (DP-6) है, वह साल में 4 बार उग सकता है। इस खीरे की किस्म डीपी-6 बुवाई के 45 दिन बाद फलों का प्रोडक्शन करने लगता है। इतना ही नहीं जब एक बार फलना शुरू करता है, तो 3 से 4 महीने तक लगातार बीज रहित खीरा का फलन होते रहता है। आपको बता दें कि यह किस्म आईसीएआर आईएआरआई, पूसा इंस्टीट्यूट के सफल प्रयास से किसानों को मिला है।

वैज्ञानिकों के कई सालों का सफल प्रयास

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीज रहित खीरा की किस्म कई सालों के मेहनत का परिणाम है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका छिलका भी काफी पतला होता है, जिससे इसका उपयोग करने वाले बिना छीले भी इस डीपी 6 नामक खीरा को खा सकते हैं। आपको यह भी जान कर काफी आश्चर्य होगा कि इस डीपी 6 नामक खीरे के नस्ल में कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं है। यह किस्म बिना परागण के ही बहुत अच्छा पैदावार दें सकती है। लेकिन इस बेमौसमी किस्म के खीरे को लेकर एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है की इसको खुले में लगाने से कीट-रोग लगने की संभावना काफी ज्यादा है। किसानों के मन में यह भी प्रश्न है की इसको या तो पॉलीहाउस या संरक्षित ढांचे में ही उगाया जायेगा।

क्या है खासियत

आपको बता दें कि किसी भी खीरे के बेल की हर गांठ पे मादा पुष्प निकलते हैं, लेकिन यह जान कर आपको काफी खुशी होंगी की इस डीपी-6 किस्म के बेल पर जितने ही मादा पुष्प निकलेंगे उतना ही फल का उत्पादन होगा। आपको ये बता दें कि 100 वर्गमीटर खेत में डीपी-6 किस्म के खीरे की तकरीबन 400 पौधे लगाए जा सकते हैं, जिसके हर एक पौधों से लगभग 4 किलो तक खीरे का उत्पादन हो सकता है।

कितना है लागत व कैसे करें खेती

वैज्ञानिकों के मुताबिक यह डीपी -6 किस्म के खीरे का उत्पादन कमर्शियल जगहों जैसे होटल या फिर घर में आसानी से किया जा सकता। आपको बता दें कि इस डीपी-6 किस्म का खीरे जिसे आईसीएआर-आईएआरआई पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, वह समान खीरे के किस्म के बीज से लगभग 15 रुपए अधिक कीमत में मिलेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार किसान भी इस किस्म के खीरे की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो वो भी इस बीज को लगा सकते हैं। लेकिन इस अच्छे बीज के लिए किसानों को दिल्ली स्थित पूसा इंस्टीट्यूट के सब्जी विज्ञान केंद्र से जाकर लाना होगा।

आपको यह भी बता दें की किसानों को इस डीपी-6 किस्म के खीरे की संरक्षित खेती के लिए, केंद्र सरकार के संरक्षित खेती योजना का लाभ लेकर, अच्छा उत्पादन कर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इस किस्म के खीरे की खेती में किसान को कम लागत में भी अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपको यह जान कर भी हैरानी होगी की किसान के इस डीपी-6 किस्म के खीरे के खेती के लिए एक एकड़ में तकरीबन 20 हजार रुपए लगाने पड़ेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों पर रहने वाले किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सुझाई विदेशी सब्जी उत्पादन की नई तकनीक, बेहतर मुनाफा कमाने के लिए जरूर जानें

मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव और इंटरनेट के सहयोग से वैश्विक खेती के बारे में मिलने वाली जानकारी की मदद से अब भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान भी कई प्रकार की दुर्लभ सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं।

अब भारतीय ग्रामीण किसान भी कुछ ऐसी सब्जियां उगा रहे हैं जिन की शुरुआत भारत में ना होकर विदेश में हुई थी, इन सब्जियों को विदेशी सब्जियां भी कहा जाता है। बेहतर स्वाद और सरलता से पकने के लिए मशहूर विदेशी सब्जियां की मांग धीरे-धीरे बाजारों में भी बढ़ रही है।

पिछले कुछ समय से शहरी क्षेत्रों में सुपर मार्केट चैन की वजह से अब विदेशी सब्जियां जैसे लाल पत्ता गोभी, चाइनीस पत्ता गोभी, सेलेरी, ब्रोकली और जुकीनी तथा बेबी कॉर्न एवं बेबी गाजर की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है।

कम कैलोरी क्षमता वाली विदेशी सब्जियां कई प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है साथ ही इनके निरन्तर सेवन से बेहतर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की पूर्ति की जा सकती है।

विदेशी सब्जियों के उत्पादन के लिए आवश्यक जलवायु :-

ऊपर बताई गई लगभग सभी विदेशी सब्जियों के लिए ठंडा और नमी वाला मौसम सर्वोत्तम होता है। 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान इन सब्जियों की बेहतर वृद्धि के लिए लाभदायक होता है।

अधिक सर्दी और पाले को सहन करने की क्षमता रखने वाली विदेशी सब्जियां दोमट मृदा में बेहतर उत्पादन देती है।

विदेशी सब्जियों को उगाने के लिए कैसे करें खेत की तैयारी :-

शुरुआत में खेत को समतल बनाने के लिए दो से तीन बार जुताई करके छोटे-छोटे आकार की क्यारियों में बांट लेना चाहिए।

फसल को कई प्रकार के मृदा जनित रोग जैसे कि आर्द्रगलन और कीटों से होने वाले रोग से बचाने के लिए सौर तापीकरण विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा कुछ रासायनिक उर्वरक जैसे केप्टोन और फॉर्मेलिन का प्रयोग कर भी बीज को उपचारित किया जा सकता है।

वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद का इस्तेमाल फसल की बेहतर वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैविक खाद का इस्तेमाल बुवाई से पहले ही खेत में बिखराव करके करना चाहिए।
यदि अधिक ढलाई वाली जमीन के साथ ही किसी स्थान की मृदा ठोस हो तो ऊपर की सतह पर बालू मिट्टी का छिड़काव कर भी क्यारियां बनाई जा सकती है। एक बार फसल की बुवाई करने के बाद क्यारियों को पारदर्शी पॉलिथीन से ढक देना चाहिए।

किसान भाइयों को बेहतर पौधशाला के निर्माण के दौरान कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए जैसे की विदेशी सब्जियों के बीज आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें उगाने के लिए एकदम सटीक जलवायुवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तापमान में थोड़ा भी बदलाव होने पर इनसे उगने वाले पौधे की गुणवत्ता पूरी तरीके से खराब हो सकती है।

प्रो-ट्रे (Pro-Tray) पौधशाला विधि की मदद से मृदा रहित नर्सरी भी तैयार की जा सकती है, इस विधि में अनुपजाऊ मृदा के स्थान पर नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अलावा वरमीक्यूलाइट तथा परलाइट का मिश्रण बनाकर बेहतर पोषक तत्वों वाला एक गाढ़ा घोल तैयार किया जा सकता है।

प्रो-ट्रे विधि से तैयार नर्सरी की छोटी पौध में मृदा जनित कीटों और कई प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा पहुंचाए जाने वाले नुकसान की कम संभावना होती है, इसलिए अधिक उपज प्राप्त होना अनुमानित होता है।

पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले किसान भाई कैसे करें उत्पादन के लिए विदेशी सब्जियों का चयन :-

वर्तमान में चल रही बाजार मांग और बेहतर उत्पादन देने वाली सब्जियों का चयन करना किसानों के लिए मुनाफा दायक हो सकता है।

वर्तमान में भारतीय बाजार में लोकप्रिय और अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में उगाई जा सकने वाली सब्जियां जैसे कि सेलेरी, स्विस चार्ड तथा लाल पत्ता गोभी और चाइनीस पत्ता गोभी के अलावा ब्रोकली जैसी सब्जियां प्रमुख है।

यदि कोई किसान भाई गर्मियों के समय में पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चेरी टमाटर, बेबीकॉर्न और शिमला मिर्च उगाना चाहता है तो इन की बुवाई अप्रैल महीने की शुरुआत में की जा सकती है।

विदेशी सब्जियों में कैसे करें कीट एवं रोग का बेहतर प्रबंधन :-

वर्तमान में सुझाई गई वैज्ञानिक तकनीकों के तहत ग्रीन हाउस तकनीक का इस्तेमाल कर कीट और रोगों से बचा जा सकता है।

ग्रीन हाउस विधि से मृदा और बीजजनित रोग जैसे किडंपिंग ऑफ तथा ब्लैक रोट आदि से बचा जा सकता है।

इन रोगों की रोकथाम के लिए डाईथेन- एम नामक रसायन का इस्तेमाल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर किया जा सकता है।

विदेशी सब्जियों की कटाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां :-

कुछ पत्तेदार विदेशी सब्जियां की कटाई की शुरुआत पौधरोपण के 50 दिनों के अंतर्गत कर लेनी चाहिए। इससे अधिक समय होने पर पत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आती है और सब्जी का स्वाद भी धीरे-धीरे खत्म होता जाता है।

सुबह के समय सब्जी के पत्तियों की तुड़ाई करना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय पत्तियों के पर्ण में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है और उन्हें तोड़ने के बाद लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।
एक बार पत्तियों की तुड़ाई करने के बाद पौधे की पुनः वृद्धि के लिए बेहतर जैविक खाद का प्रयोग कर मृदा में मिला देना चाहिए। चेरी टमाटर और शिमला मिर्च जैसी विदेशी सब्जियों के उत्पादन के दौरान परिवहन के समय को कम रखना चाहिए, क्योंकि परिवहन में लगने वाले समय के दौरान इनका रंग हरे से लाल हो जाता है, इसलिए इनकी तुड़ाई उसी समय करनी चाहिए जब फल परिपक्व होने शुरू हो जाए, नहीं तो सब्जी की बिक्री में गिरावट हो सकती है।

आशा करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य में रहने वाले किसान भाइयों को Merikheti.com के द्वारा उपलब्ध करवाई गई 'वैज्ञानिक विधि से विदेशी सब्जी उत्पादन' की यह जानकारी पसंद आई होगी और आप भी भविष्य में बेहतर पौधशाला निर्माण और उर्वरकों के सही प्रबंधन की मदद से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे।

फल

केले की खेती करने वाले किसान दें ध्यान, नही तो बढ़ सकती है मुसीबत: वैज्ञानिक

विगत कुछ सालों से किसान केले की खेती (Banana Farming) पर काफी ध्यान दे रहे हैं, क्यूंकि केले की खेती ने किसानों की आय बढ़ा दी है। आपको बता दें की केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी अभी काफी ध्यान दी हुई है, इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी बनायी गयी हैं। इसके तहत किसानों को कम दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है,और सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे किसानों का भी ध्यान काफी बढ़ा है केले की खेती पर।

वैज्ञानिकों के अनुसार केले की खेती के साथ साथ अभी किसान एक मिक्स्ड क्रोप्पिंग (Mixed Cropping) या सहफसली खेती या मिश्रित खेती कर दुगुना लाभ ले रहे हैं। मिक्स्ड क्रोप्पिंग में किसान एक ही खेत में एक ही समय में दो फसल उगा कर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में केले में लगने वाले अलग अलग तरह के रोग किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आज कल केले में होने वाली बीमारी जिसका नाम थ्रोट चॉकिंग (गला घुटना) है, ने तमाम किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है।

गौरतलब हो की उत्तर भारत के बिहार एवं उत्तरप्रदेश में केला ज्यादातर सितम्बर के महीने में लगया जाता है। सितम्बर में रोपाई के बाद केला में इस बिमारी का विकराल रूप देखने को मिलता है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा की यह बीमारी केले के लम्बे प्रजाति के अपेक्षा बौने प्रजाति में सामान्यतः देखने को मिलती है।
पुरे भारत में केले की खेती की जाती है। किसानों के जानकारी के लिए थ्रोट चॉकिंग (गला घोंटना; throat choking) नामक बीमारी में केले का फल का गुच्छा कुछ सामान्य तरीके से न निकल कर, असमान्य तरीके से तने को फाड़ते हुए निकलने लगता है।

वरिष्ट फल वैज्ञानिकों के अनुसार, किसान को इस समय इस बीमारी से बचने के लिए केले की लम्बी प्रजाति के किस्मों का चयन करना चाहिए, क्यूंकि लम्बे प्रजाति में यह बीमारी कम पायी जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो लम्बे प्रजाति के किस्म जैसे, चंपा, चीनी चंपा, मालभोग, कोठिय, बत्तिसा, अल्पान का प्रयोग करें और समय पर केले की रोपाई भी करें।

किसान और क्या दें ध्यान

किसानों को केले के खेत में कम से कम जलजमाव हो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए केले के खेत में जल निकासी का उत्तम प्रबंध भी करना चाहिए। केले के खेती में बेहतर खाद और उर्वरक का प्रयोग भी करना चाहिए, विशेषतः गर्मी के मौसम में किसानों को केले के खेत में ससमय सिंचाई भी करनी चाहिए, जिससे इसकी पैदावार अच्छी हो।
किसानों का कहना है की अभी जिस तरह ये बिमारी फैल रही है, उस पर सरकार को विशेष ध्यान देकर किसानों को इससे निजात दिलाना चाहिए। अन्यथा किसान को इससे काफी नुक्सान का सामना करना पड़ेगा, थ्रोट चॉकिंग (गला घोंटना) नामक बिमारी से केले की पैदावार में काफी कमी आई है जो की किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

सिंघाड़ा काफी मशहूर एवं प्रचलित फसल है, इसकी अपने बाजार में अच्छी खासी मांग और उपयोगिता है। सिंघाड़ा उत्पादक किसान इसकी उत्तम पैदावार करके बेहतर मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि सिंघाड़े का उपयोग भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। सिंघाड़े को कुछ दिनों धूप में सुखाने के उपरांत इसके अंदर के फल को पीसकर आटा निर्मित होता है, जिसको लोग उपवास के दौरान प्रयोग करते हैं। शीतकाल के दौरान सिंघाड़े की मांग आसमान छूने लगती है, इससे न केवल किसान को लाभ होता है, बल्कि अन्य ठेली व रेहड़ी वाले भी इसको विक्रय कर मुनाफा कमाते हैं।

सिंघाड़ा काफी मशहूर एवं प्रचलित फसल है, इसकी अपने बाजार में अच्छी खासी मांग और उपयोगिता है। सिंघाड़ा उत्पादक किसान इसकी उत्तम पैदावार करके बेहतर मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसकी एक वजह यह भी है कि सिंघाड़े का उपयोग भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। सिंघाड़े को कुछ दिनों धूप में सुखाने के उपरांत इसके अंदर के फल को पीसकर आटा निर्मित होता है, जिसको लोग उपवास के दौरान प्रयोग करते हैं। शीतकाल के दौरान सिंघाड़े की मांग आसमान छूने लगती है, इससे न केवल किसान को लाभ होता है, बल्कि अन्य ठेली व रेहड़ी वाले भी इसको विक्रय कर मुनाफा कमाते हैं।

सिंघाड़े की उम्दा किस्मों के प्रकार एवं खेती का प्रबंधन

सिंघाड़े की मुख्यतया दो किस्म पायी जाती हैं, जिसमे पहली किस्म को लाल छिलके व दूसरी को हरे छिलके के नाम से जाना जाता है। लाल छिलके में सबसे प्रसिद्ध किस्म VRWC1 एवं VRWC 2 हैं, लेकिन हरे छिलके वाली किस्म VRWC 3 की अपेक्षा में लाल छिलके की किस्म को किसान कम पसंद करते हैं। जिसकी मुख्य वजह यह है कि लाल किस्म के सिंघाड़े की किस्में शीघ्रता से खराब हो जाती हैं और इसी कारण से बाजार में इसकी मांग काफी कम होती है। जबकि हरे छिलके वाली सिंघाड़े की बाजार में अत्यधिक मांग होती है, साथ ही यह काफी समय तक खराब भी नहीं होती। सिंघाड़े की फसल की तैयारी के लिए किसानों को सर्वप्रथम उम्दा एवं अच्छे बीजों को जनवरी एवं फरवरी माह में जल के अंदर डाल कर उनकी बेल अंकुरित होने तक संजोकर रखना होगा। साथ ही किसान सिंघाड़े की रोपाई मई जून के महीने में करें, क्योंकि इसकी फसल का वातानुकूलित समय वही होता है। सिंगाड़े की खेती एक स्थिर जलीय स्थान पर ही संभव होती है, फसल लगभग १ से २ फीट जल के अंदर निरंतर रहनी आवश्यक है।

सिंघाड़े के कुछ महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं।

सिंघाड़े से व्रत में उपभोग करने हेतु आटा निर्मित होता है।

सिंघाड़ा खाने में भी अत्यंत स्वादिष्ट लगता है।

सिंघाड़े के प्रयोग से शरीर में विघमान खुश्की भी दूर हो जाती है, साथ ही पीड़ाजनक शारीरिक स्थानों पर यह एक सफल औषधी का कार्य करता है।

सिंघाड़ा महिलाओं को पीरियड्स के समय होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभाता ही है, साथ ही गर्भवती होने के समय गर्भपात जैसे भय को खत्म करने की भी क्षमता रखता है।

सिंघाड़ा के इस्तेमाल से कई सारे रोगों से निजात मिल सकती है, जैसे की अस्थमा, बवासीर इत्यादि।

सिंघाड़े में केल्सियम प्रचूर माला में होता है, जो कि हड्डियों की मजबूती एवं आँखों के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ ही शारीरिक ऊर्जा भी प्रदान करता है।

सिंघाड़े की खेती करके किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सिंघाड़े की प्रसिद्धि से बाजार में इसकी खूब मांग है, जिसके चलते इसका अच्छा भाव बाजार में मिल जाता है।

महाराष्ट्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती ने बदली लोगों की किस्मत, अब गन्ना-अंगूर छोड़कर यही उगा रहे हैं किसान

इन दिनों कई राज्यों में मौसम का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर अब बरसात कम होने लगी है, इससे सीधे तौर पर किसान प्रभावित होते हैं। कम बरसात के कारण मिट्टी में नमी की कमी हो जाती हैं जिससे फसलों कि बुवाई कम होती है और किसानों का मुनाफा भी कम हो जाता है। इन समस्याओं को देखते हुए अब किसान वैकल्पिक खेती की तरफ ध्यान देने लगे हैं, जो किसानों के लिए अनुकूल हो और जिसमें किसानों को अच्छी खासी आमदनी भी हो।

ऐसी ही एक खेती है जिसे हम ड्रैगन फ्रूट (Dragon Fruit; पिताया फल; pitaya or pitahaya) की खेती के नाम से जानते हैं। इस खेती में महाराष्ट्र के सांगली जिले के किसानों की रुचि दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र का सांगली जिला देश में सूखा प्रभावित इलाकों में से एक है। यहां पर बेहद कम मात्र में बरसात होती है जो किसानों के लिए मुसीबत का सबब है। यहां के किसान पानी की कम उपलब्धता के बावजूद परंपरागत गन्ना–अंगूर की खेती कर रहे हैं।

अब कुछ दिनों से यहां के किसानों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया है। इस खेती में पानी कम जरूरत होती है, इसके साथ ही अन्य फसलों की तरह इसमें देखभाल की भी उतनी जरूरत नहीं होती। सांगली में पिछले कई सालों से कुछ किसान कम संसाधनों के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती करके अच्छा खास लाभ काम रहे हैं।

सांगली जिले के किसानों ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में पहली बार में अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा निवेश होता है। लेकिन उस हिसाब से इसमें उत्पादन भी ज्यादा होता है, जिससे लागत बहुत जल्दी वसूल हो जाती हैं। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट के भाव भी अन्य फसलों की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। पहली बार के बाद इसमें उतने ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती।

सांगली जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले कई किसानों ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में गन्ने की खेती की अपेक्षा मुनाफा ज्यादा होता है।

अगर किसान गन्ने की खेती करके 1 लाख रुपये कमा पाते थे तो वहीं अब वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करके 8 से 9 लाख रुपये तक कमा लेते हैं। इसके साथ ही पानी की कम जरूरत के साथ ही खेती की लागत में कमी के कारण ड्रैगन फ्रूट की खेती में दिमागी टेंशन भी कम होती है। इसके साथ ही इस फसल में ओलावृष्टि बारिश या सूखा से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता।

यह फल ज्यादातर विदेशों में निर्यात किया जाता है। वहां पर इस फल की उचित कीमत मिलती है। सांगली जिले के कई किसानों ने बताया की वो पिछले कुछ सालों से अपने उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुबई को निर्यात करते हैं। विदेशों के साथ ही भारत में भी ड्रैगन फ्रूट का चलन काफी बढ़ गया है, जिससे भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, जयपुर और गुवाहाटी में यह फल लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है और इस फल की काफी डिमांड रहती है।

सिंघाड़े की खेती की जिज्ञासा रखने वाले लोगों के लिए सिंघाड़े सम्बंधित जानकारी

सिंघाड़ा (Singhada; Water chestnut; सिंघारा, वॉटर चेस्टनट, वाटर कैलट्रॉप, सिंगडा) एक सुप्रसिद्ध फल है, जिसको ज्यादातर लोग बेहद पसंद करते हैं। इस मौसम में, उत्तर भारत में सिंघाड़ा प्रायः हर जगह बाजार में उपलब्ध रहता है। यह मौसमी फल होने के साथ साथ बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है।

सिंघाड़े का उपयोग सामान्य रूप से खाने के साथ ही फलहार एवं व्रत में उपयोग होने वाले आटे के रूप में भी होता है। सिंघाड़ा थोड़ा मीठा एवं स्वादिष्ट फल है, इसी वजह से लोग सिघाड़े को बेहद पसंद करते हैं, साथ ही बाजार में भी इसकी खूब मांग होती है।

सिंघाड़ा नवंबर दिसम्बर के सीजन में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी बुवाई जून जुलाई के समय होती है। इसकी पैदावार किसी तालाब पोखर जैसे अड़िग जलीय स्थानों पर ही होती है, मगर इसका उत्पादन जलभराव के लिए गड्ढा खोदकर भी किया जा सकता है। सिंघाड़े की खेती करने वाले किसान इस विधि से भी सिंघाड़ा उत्पादन करते हैं। सिंघाड़े की फसल को पूर्ण रूप से तैयार होने में ५ से ६ माह का समय लगता है, जून जुलाई में सिंघाड़े की रोपाई के उपरांत नवंबर दिसम्बर में इसकी फसल तैयार होकर बाजार में आ जाती है।

फूल

पारंपरिक खेती की जगह इस फूल की खेती किसानों को कर सकता है मालामाल

हाल के दिनों में आपको देखने को मिलता होगा कि पारंपरिक खेती से किसान अपना रुख बदल रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक खेती में किसानों को लागत के अनुसार मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। विगत कुछ दिनों में आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा कि किसान फूलों की खेती की तरफ अपना रुझान दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फूलों की खेती में पारंपरिक खेती से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा भी फूलों की खेती करने के पीछे किसानों की मंशा ये भी है कि आए दिन फूलों की मांग पूरे देश में काफी बढ़ गयी है। गौरतलब हो कि पूरे भारत में लगभग 2 लाख मैट्रिक टन फूल का उत्पादन किया जाता है। फूलों में भी आजकल जिस फूल की खेती सबसे ज्यादा की जा रही है वो है गुलाब (Gulab; Rose)। गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, आपको बता दें कि इसका कारण यह नहीं है की सिर्फ इसको सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। अपितु इसका बहुत सारा औषधीय प्रयोग भी है, जैसे कि गुलाब जल, गुलाब इत्र आदि।

आपको यह जान कर भी हैरानी होगी कि किसान इस फूल को एक बार लगा कर इससे लगभग 10 साल तक फूलों का उत्पादन कर पैसा कमा सकते हैं।

आपको बताते चलें कि गुलाब की खेती के लिए किसान को किसी खास तरह की मिट्टी की बाध्यता नहीं है। किसान इसे किसी भी तरह के मिट्टी में उपजा कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन अगर किसान बलुई या दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो फसल और भी अच्छी होगी। लेकिन अगर मिट्टी की उपज अच्छी हो या फिर इसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो तो उपज और भी अच्छी होती है। लेकिन किसान एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर बात करें गुलाब के खेती के लिए जलवायु का तो इसके लिए जलवायु समशीतोष्ण किस्म का होना चाहिए। किसानों को यह भी ध्यान रखना होगा कि गुलाब की खेती के लिए गर्म जलवायु काफी नुकसानदेह हो सकता है, जिससे किसानों को नुकसान भी हो सकता है। आपको बता दें कि किसानों को गुलाब की खेती के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से नीचे का तापमान अच्छी उपज दे सकता है।

गौरतलब हो की पूरे भारत में गुलाब के किस्म की बात करें तो लगभग 20 हजार से ज्यादा है। लेकिन जिस किस्म का प्रयोग किसान आमतौर पर करते हैं, उनमें मोहनी, प्रेमा, डेलही प्रिंसेज नूरजहां आदि शामिल हैं।

कैसे करें सूरजमुखी की खेती? जानें सबसे आसान तरीका

रबी का सीजन शुरू हो चुका है, सीजन के शुरू होने के साथ ही रबी की फसलों की बुवाई भी बड़ी मात्रा में शुरू हो चुकी है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरजमुखी या सूर्यमुखी (Sunflower) की खेती की सम्पूर्ण जानकारी ताकि किसान भाई इस बार रबी के सीजन में सूरजमुखी की खेती करके ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें।

अभी भारत में मांग के हिसाब से सूरजमुखी का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए भारत सरकार को घरेलू आपूर्ति के लिए विदेशों से सूरजमुखी आयत करना पड़ता है, ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। भारत में इसकी खेती सबसे पहले साल साल 1969 में उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी, जिसके बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होने पर देश भर में इसकी खेती की जाने लगी। फिलहाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब के किसान सूरजमुखी की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं।

अगर आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में हर साल लगभग 15 लाख हेक्टेयर पर सूरजमुखी की खेती की जाती है, साथ ही देश के किसान इसकी खेती से 90 लाख टन की पैदावार लेते हैं। अगर सूरजमुखी की खेती में औसत पैदावार की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 7 क्विंटल सूरजमुखी के बीजों का उत्पादन होता है। सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसकी खेती सर्दी के सीजन में की जाए तो अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है।

सूरजमुखी की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करें

खेत तैयार करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें, यदि खेत की मिट्टी ज्यादा अम्लीय या ज्यादा क्षारीय है तो उस जमीन में सूरजमुखी की खेती करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों से उर्वरक के इस्तेमाल की सलाह जरूर लें ताकि जरुरत के हिसाब से खेत की मिट्टी में पर्याप्त उर्वरक इस्तेमाल किये जा सकें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खेत से पानी की निकासी का सम्पूर्ण प्रबंध होना चाहिए। इसके बाद गहरी जुताई करें और खेत को समतल करके बुवाई के लिए तैयार कर लें।

सूरजमुखी की खेती के लिए बाजार में उपलब्ध उन्नत किस्में

ऐसे तो बाजार में सूरजमुखी के बीजों की कई किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन अधिक और अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिये किसान कंपोजिट और हाइब्रिड किस्मों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करने पर सूरजमुखी की खेती 90 से 100 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है, और उसके बीजों में तेल का प्रतिशत भी 40 से 50 फीसदी के बीच होता है।

अगर बेस्ट किस्मों की बात करें तो किसान भाई सूरजमुखी की बीएसएस-1, केबीएसएस-1, ज्वालामुखी, एमएसएफएच-19 और सूर्या किस्मों का चयन कर सकते हैं।

सूरजमुखी की बुवाई कैसे करें

सूरजमुखी की बुवाई रबी सीजन की शुरुआत में की जाती है। अगर माह की बात करें तो अक्टूबर का तीसरा और चौथा सप्ताह इसके लिए बेहतर माना गया है। इसकी बुवाई से पहले बीजों का उपचार कर लें ताकि बुवाई के समय किसानों के पास बेस्ट किस्म के बीज उपलब्ध हों। सूरजमुखी के बीजों की बुवाई छिड़काव और कतार विधि दोनों से की जा सकती है। लेकिन भारत में कतार विधि, छिड़काव विधि की अपेक्षा बेहतर मानी गई है।

कतार विधि का प्रयोग करने से खेती के प्रबंधन में आसानी रहती है। इसके लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि लाइनों के बीच 4-5 सेमी और बीजों के बीच 25-30 सेमी का फासला रखना चाहिए।

सूरजमुखी की खेती में खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करें

जैविक खाद एवं उर्वरक किसी भी खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए सूरजमुखी की खेती में भी इन चीजों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। सूरजमुखी के बीजों का क्वालिटी प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए 6 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। इसके साथ विशेषज्ञ 130 से 160 किग्रा यूरिया, 375 किग्रा एसएसपी और 66 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं।

सूरजमुखी की खेती में सिंचाई किस प्रकार से करें

सुरजमुखी की खेती में सामान्य सिंचाई की दरकार होती है। इसकी खेती में 3 से 4 सिंचाईयां पर्याप्त होती हैं। इस खेती में यह सुनिश्चित करना बेहद अनिवार्य है कि खेत में नमी बनी रहे, ताकि पौधे बेहचर ढंग से पनप पाएं। सूरजमुखी की फसल में पहली सिंचाई 30-35 दिन के अंतराल में करनी होती है। इसके बाद हर तीसरे सप्ताह इस फसल में पानी देते रहें। इस फसल में फूल आने के बाद भी हल्की सिंचाई की दरकार होती है।

यह एक फूल वाली खेती है इसलिए इसमें कीटों का हमला होना सामान्य बात है। इस फसल में एफिड्स, जैसिड्स, हरी सुंडी व हेड बोरर जैसे कीट तुरंत हमला बोलते हैं। जिससे सूरजमुखी के पौधों को रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू, हेड राट, राइजोपस हेड राट जैसे रोग घेर लेते हैं।

इसके अलावा इस खेती में पक्षियों का हमला भी आम बात है। फूलों में बीज आने के बाद पक्षी भी बीज चुन लेते हैं, ऐसे में किसानों को विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए ताकि वो इन परेशानियों से निपट पाएं।

बुवाई के लगभग 100 दिनों बाद सूरजमुखी की खेती पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके फूल बड़े होकर पूरी तरह से पीले हो जाते है। फूलों की पंखुड़ियां झड़ने के बाद किसान इस खेती की कटाई कर सकते हैं। कटाई करने के बाद इन फूलों को 4 से 5 दिन तक तेज धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद मशीन की सहायता से या पीट-पीटकर फूलों के बीजों को अलग कर लिया जाता हैं। अगर पैदावार की बात करें तो अच्छी परिस्थियों में किसान भाई उन्नत किस्मों और आधुनिक खेती के साथ एक हेक्टेयर में 18 क्विंटल तक सूरजमुखी के बीजों की पैदावार ले सकते हैं। सामान्य परिस्थियों में यह पैदावार 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है।

हाल ही में भारत सरकार ने सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी कर दी है। इस लिहाज से अब सूरजमुखी की खेती करके किसान भाई पहले की अपेक्षा ज्यादा कमाई कर सकते हैं। सरकार ने रबी सीजन के लिए सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 209 रूपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की है। इस हिसाब से अब किसान भाइयों के लिए सूरजमुखी के बीजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

मशीनरी

एक शानदार ट्रैक्टर है मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महा शक्ति ट्रैक्टर

मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महा शक्ति ट्रैक्टर (Massey Fergusion 241 DI Maha Shakti Tractor) आधुनिक तकनीक के साथ आने वाला एक शानदार ट्रैक्टर है। जिस प्रकार से कम्पनी ने इस ट्रैक्टर को डिजाइन किया है, उस हिसाब से इस ट्रैक्टर ने खुद की खेती बाड़ी के कार्यों में अपनी उपयोगिता को साबित करके दिखाया है। इस ट्रैक्टर को जिन किसानों ने इस्तेमाल किया है उनकी खेती की लागत में कमी आई है, साथ ही उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महा शक्ति ट्रैक्टर के फीचर्स और माइलेज अन्य ट्रैक्टरों के फीचर्स और माइलेज से बेहतर है। मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महा शक्ति ट्रैक्टर एक शानदार ट्रैक्टर है जो 42 एचपी के इंजन के साथ आता है। साथ ही यह 35.7 पीटीओ एचपी के साथ आता है जो इसे अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा बेहतर बनाता है। इसके साथ ही यदि ट्रैक्टर की शक्ति की बात करें तो यह ट्रैक्टर 2500 सीसी इंजन के साथ आता है। इसके साथ ही इसमें 3 सिलिंडर इंजन दिया जाता है। अगर इस ट्रैक्टर में आरपीएम की बात करें तो यह 2100 इंजन रेटेड आरपीएम उत्पन्न करता है। जिसके कारण यह ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ होता है। इस ट्रैक्टर में 15 से 20 प्रतिशत तक का टार्क बैकअप प्राप्त होता है।

मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महाशक्ति ट्रैक्टर के अन्य फीचर्स

मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महा शक्ति ट्रैक्टर को कम्पनी ने बाजार में ड्यूल क्लच के साथ उतारा है। इसके साथ ही इस ट्रैक्टर में मल्टी डिस्क तेल में डूबे ब्रेक हैं। जो फिसलन के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं साथ ही ये ब्रेक ट्रैक्टर में उचित पकड़ बनाए रखने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके गियरबॉक्स में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर होते हैं जिससे गियर्स की शिफ्टिंग बेहद आसान हो जाती है। इस ट्रैक्टर में कुशल जल शीतलन प्रणाली दी गई है जिसके द्वारा ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखने में मदद मिलती है। इस ट्रैक्टर में 47 लीटर की क्षमता का डीजल टैंक है, जिसमें पर्याप्त ईंधन आ जाता है। इसके साथ ही अगर इसके भार उठाने की क्षमता की बात करें तो यह 1700 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। यह एक टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, जिसका कुल वजन लगभग 1875 किग्रा है। इस ट्रैक्टर में चार्जिंग स्लॉट, एडजस्टेबल सीट्स, ऑटोमैटिक डेप्थ कंट्रोलर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई ट्रैक्टर की कीमत कितनी है

मैसी फर्ग्यूसन 241 डीआई महा शक्ति ट्रैक्टर बेहद किफायती ट्रैक्टर माना जाता है। इसकी कीमत बाजार में 6.05 से 6.60 लाख रूपये तक है। यह कीमत समय के साथ थोड़ी ऊपर या नीचे भी हो सकती है। इसके अलावा ट्रैक्टर की कीमत टैक्स, स्थान आदि पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं।

अगर ट्रैक्टर की ऑन रोड कीमत की बात करें तो ऑन रोड कीमत अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग-अलग होती है, यह वहां पर लगने वाले टैक्स और रियायतों पर निर्भर करता है। ऑन रोड कीमत की सटीक जानकारी के लिए किसान भाई मैसी फर्ग्यूसन की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

सोनालिका ने अक्टूबर'22 में 20,000 ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी की दर्ज

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सोनालिका ट्रैक्टर्स (Sonalika Tractors) के बहु-आयामी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, कंपनी ने अक्टूबर में 20,000 ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी की है, जिसमें बिलिंग वृद्धि महीने के दौरान उद्योग की वृद्धि से लगभग दोगुनी है। नई दिल्ली, 4 नवंबर, 2022: भारत के नंबर 1 ट्रैक्टर निर्यात ब्रांड, सोनालिका ट्रैक्टर्स ने नए दृढ़ता से प्रदर्शन के साथ वित्त वर्ष '23 के सबसे बड़े त्योहारी सीजन में जोरदार कदम रखा है। कंपनी ने इस साल अक्टूबर में 16% बिलिंग वृद्धि के साथ 20,000 ट्रैक्टरों की अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी हासिल की है, जो उद्योग की अनुमानित 7% वृद्धि से लगभग दोगुना है। ट्रैक्टर उद्योग के बाजार ने नवरात्रि से गति पकड़ी और अक्टूबर माह के दौरान सकारात्मक रही, खासकर इस महीने दिवाली के त्यौहार तक। भारत के अग्रणी ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक, सोनालिका ट्रैक्टर्स ने अपने लोकप्रिय 'हैवी ड्यूटी धमाका' (Heavy Duty Dhamaka) अभियान के तहत उपभोक्ता ऑफर्स (offers) की एक व्यापक श्रृंखला का विस्तार किया। इस ऑफर का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिला। नई उपलब्धि पर अपने विचार साझा करते हुए, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक, श्री रमन मित्तल ने कहा, "हमें इस अक्टूबर में एक और मील का पत्थर बनाने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जिसमें 20,000 ट्रैक्टरों की हमारी अब तक की सबसे अधिक डिलीवरी 16% से अधिक बिलिंग वृद्धि के साथ है। उद्योग की अनुमानित 7% वृद्धि से दोगुना। ऐसा प्रदर्शन वास्तव में हमारे लिए खास है क्योंकि हमने जिस लक्ष्य के लिए योजना बनाई थी, हमने इसे 100% हासिल किया। सभी कार्यक्षेत्रों में टीम के प्रत्येक सदस्य ने अंतिम दिन तक एक असाधारण अभियान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी रणनीतियों और व्यापार को फिर से संगठित करने की पहल के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023 में हमारे लिए एक शानदार उत्सव का मौसम आया है। हम नए उत्पादों को लॉन्च करना जारी रखेंगे जो आने वाले वर्षों में किसानों की उत्पादकता और आय में तेजी से वृद्धि करेंगे।"

मौसमी व अन्य कृषि सुझाव

किसान अगर इन तीनों पेड़ों की खेती करते हैं तो हो सकते हैं करोड़पति

पारंपरिक खेती से परेशान किसान अब अपना रहे हैं, कमाने का दूसरा तरीका। गौरतलब हो की हाल के कुछ दिनों में पारंपरिक खेती का हाल बेहद खराब हो गया है। जिसके कारण किसान कमाने के लिए दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान अब पारंपरिक खेती के अलावा कम लागत में ज्यादा मुनाफे कमाने के लिए पेड़ की खेती अधिक कर रहे हैं। लेकिन गौरतलब हो की पेड़ की खेती के किसान को धैर्य रखने की जरूरत है, अगर किसान धैर्य के साथ पेड़ की खेती करते हैं तो उनको काम लागत में ज्यादा मुनाफे हो सकता है।

पेड़ की खेती में भी आज कल किसानों के बीच ये तीन पेड़ काफी लोकप्रिय है, जिसके खेती कर किसान अच्छा मुनाफे कमा रहे है। किसान आजकल महोगनी, सागवान और गम्हार जैसे पेड़ों की खेती कर काम लागत में अच्छा मुनाफे कमा रहे है। आपको बता दें कि इन लकड़ियों का बाजार में भी काफी मांग है, जिससे कि अच्छे-अच्छे फर्नीचर और लकड़ी का सामान बनाया जाता है। बाजार में अच्छे कीमत होने के कारण किसान इन खेती पर काफी ध्यान दे रहे हैं आपको बता दें कि किसान अगर इसमें 8 से 10 साल तक धैर्य के साथ संयम पूर्वक खेती करते हैं तो इसमें एक पेड़ उनको करोड़ों रुपए का मुनाफा दे सकता है।

सागवान

गौरतलब हो कि सागवान (sagwan) अभी के दिनों में काफी लोकप्रिय होते दिख रहा है, जिससे किसान इसकी खेती (Sagwan Ki Kheti; Sagwan Farming) पर काफी ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि सागवान उगाने में ज्यादा दिमाग नहीं लगता है और यही खूबी उसको बाजार में काफी लोकप्रिय बना रही है। सागवान की लकड़ी का उपयोग आजकल रेल के डब्बे को बनाने में उपयोग किया जाता है, इतना ही नहीं इस से आजकल प्लाईवुड भी बन रहा है जो कि काफी महंगा बिक रहा है। आपको यह भी बताते चलें कि सागवान की लकड़ी के अलावा इसके पत्ते और छाल का भी काफी महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक उपयोग है। आपको बता दें कि इनके छाल और पत्तों का उपयोग कई तरह के एनर्जी देने वाली दवाओं को बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि किसान 1 एकड़ में सागवान के 120 पेड़ लगा सकते हैं। 8 से 10 साल बाद जब पेड़ कटाई की स्थिति में आ जाता है तो उस वक्त एक पेड़ की कीमत लगभग ₹40000 तक होती है। अगर इस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 1 एकड़ में किसान अगर सागवान की खेती करते हैं, तो उसका मुनाफा करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है।

महोगनी

महोगनी (Mahogany) की खेती किसानों को करोड़पति बना सकती है। आपको बता दें कि इस पेड़ की लंबाई 200 फिट तक हो सकती है, जो किसानों को काफी अच्छा मुनाफा देती है। आपको यह भी बताते चले कि इस पेड़ का उपयोग जहाज बहुत सारे गहने, सजावट और मूर्तियां को बनाने में किया जाता है।

अगर किसान इस पेड़ को लगाने के बाद 12 साल तक संयम बरतकर इसका ध्यान रखें, तो वह किसानों को करोड़पति बना सकता है। आपको बता दें कि अभी इस महोगनी के पेड़ की कीमत बाजार में 2500 रुपए प्रति क्यूबिक फिट है। आपको यह भी बताते चलें कि सागवान की लकड़ी के अलावा इसके पत्ते, फूल और छाल का काफी औषधीय प्रयोग भी है, जिसके कारण बाजार में छाल, पत्ती और फूल का भी अच्छी खासी कीमत किसानों को मिल जाती है।

सफेदा या गमहार

अब बात करते हैं सफेदा या गमहार या नीलगिरी (Nilgiri; यूकेलिप्टस; Eucalyptus) की खेती की तो इसकी खेती काफी आसानी से किसानों के द्वारा किया जा सकता है। इस के पेड़ को तैयार होने में तकरीबन 5 साल का वक्त लगता है, जिसके बाद इसका एक पेड़ 400 किलो लकड़ी के आसपास देता है, जिसमें प्रति किलो लकड़ी की कीमत ₹7 के आसपास है। इसके लकड़ी का प्रयोग इंधन और फर्नीचर के रूप में काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। 5 साल में तैयार होने के बाद यह पेड़ किसानों को लाखों रुपए का मुनाफा देते हैं।

रबी सीजन में प्याज उत्पादन करने वाले किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

महाराष्ट्र भारत में प्याज उत्पादन के मामले में विशिष्ट राज्य है,क्योंकि महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन काफी किया जाता है। बतादें कि वर्ष में तीन बार प्याज की फसल उगाई जाती है। प्रदेश के सोलापुर, नासिक, पुणे, धुले व अहमदनगर जनपद में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन होता है। प्रदेश में फिलहाल रबी सीजन के प्याज की पैदावार की तैयारी चालू है। महाराष्ट्र में किसान अधिकतर प्याज की खेती करते हैं। साथ ही, महाराष्ट्र राज्य में देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक जनपद के लासलगांव में स्थित है। सामान्य रूप से अधिकतर प्रदेशों द्वारा वर्ष में एक ही बार प्याज का उत्पादन किया जाता है। परंतु महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, प्रदेश में एक वर्ष के दौरान रबी सीजन, खरीफ, खरीफ के बाद इस तरह प्याज का तीन बार उत्पादन है। महाराष्ट्र राज्य के किसान अधिकतर प्याज का उत्पादन करते हैं और इस पर ही आश्रित रहते हैं हालाँकि सर्वाधिक प्याज उत्पादन रबी सीजन में ही प्राप्त होता है। प्याज के द्वितीय सीजन की बुआई अक्टूबर-नवंबर माह के मध्य में होती है।

इसकी फसल जनवरी से मार्च के मध्य तैयार हो जाती है। प्याज का फसल का तीसरा समय रबी सीजन में होता है। रबी सीजन की बुवाई दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है, और इसकी फसल की पैदावार मार्च से मई के मध्य ली जाती है। महाराष्ट्र में प्याज की कुल पैदावार का ६० प्रतिशत उत्पादन रबी सीजन के दौरान होता है।

ज्यादातर प्याज की खेती कौन से जिलों में होती है

महाराष्ट्र राज्य के नासिक, पुणे, सोलापुर, जलगाँव, धुले, अहमदनगर, सतारा जनपद में ज्यादा खेती होती है। बतादें कि मराठवाड़ा के कुछ जनपदों में भी प्याज उत्पादन किया जाता है। इसमें भी प्याज उत्पादन के मामले में नासिक जनपद अपनी अलग पहचान रखता है, इसकी मुख्य वजह देश के कुल प्याज उत्पादन का ३७ % महाराष्ट्र राज्य करता है जबकि १० % उत्पादन केवल नासिक जनपद में किया जाता है।

प्याज उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी व भूमि सही होती है

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्याज के उत्पादन हेतु कई प्रकार की मिट्टी का उपयोग हो सकता है। प्याज की अच्छी पैदावार लेने के लिए चिकनी, गार, रेतीली, भूरी एवं दोमट मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए। प्याज की खेती से बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए भूमि के जल निकासी हेतु अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। प्याज उत्पादन से पूर्व जमीन तैयार करने हेतु सर्वप्रथम तीन से चार बार जुताई हो एवं रुड़ी खाद के इस्तेमाल से जैविक तत्वों की मात्रा में बढ़ोत्तरी करें। इसके बाद खेत को छोटे-छोटे भाग में बाँट दें। भूमि की सतह से १५ सेमी उंचाई पर 1.2 मीटर चौड़ी पट्टी पर बुवाई होनी चाहिये।

वैज्ञानिक विधि से करें बेहतर पौधशाला प्रबंधन

बेहतर पौधशाला प्रबंधन के फायदे और उत्पादन से बढ़ेगी आय

किसान भाइयों को यह बात पता ही है कि किसी भी फसल के बेहतर उत्पादन के लिए एक स्वस्थ पौध का होना अनिवार्य है। केवल बेहतर बीज से तैयार हुई स्वस्थ और गुणकारी पौध समय पर गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन कर सकती है।

कुछ सब्जी जैसे कि बैंगन, मिर्च, टमाटर तथा पत्तागोभी जैसी फसलों में स्वस्थ पौधरोपण के बिना किसी भी हालत में बेहतर उत्पादन नहीं हो सकता है और किसी भी स्वस्थ पौध को तैयार करने के लिए एक बेहतर पौधशाला (nursery; paudhshala) की आवश्यकता होती है।

कैसे तैयार करें बेहतर पौधशाला ?:

कृषि क्षेत्र में काम कर रहे कृषि वैज्ञानिक समय-समय पर पौधशाला के बेहतर प्रबंधन के लिए एडवाइजरी जारी करते हैं।

पौधशाला के क्षेत्र की भूमि को हमेशा मुलायम और आसानी से पानी सोखने के लायक बनाया जाना चाहिए।

नई तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले किसान भाई दोमट मिट्टी का इस्तेमाल कर फसल पर पड़ने वाले अम्लीयता और क्षारीयता के प्रभाव से होने वाले नुकसान को कम करने में भी सफल हुए हैं। दोमट मिट्टी के प्रयोग से मृदा में जल धारण की क्षमता बढ़ने के साथ ही जैविक कार्बन की मात्रा भी बढ़ती है।

कैसे करें बेहतर शोधन मृदा ? :

वर्तमान में पौधशाला में इस्तेमाल की जाने वाली मृदा को बेहतर उत्पादन और रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए 'मृदा सौरीकरण विधि' (मृदा सूर्यीकरण; Soil Solarization; सॉयल सोलराइजेशन) का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विधि में पौधशाला की मृदा को सूर्य के प्रकाश की मदद से बेहतर उपज वाली बनाया जाता है।

सबसे पहले पौध उगाने के लिए काम में आने वाली मिट्टी की बड़ी-बड़ी क्यारियां बनाकर, जुताई करने के बाद सीमित मात्रा में सिंचाई करते हुए, मृदा की नमी को बरकरार रखने से बेहतर उपज प्राप्त होती है।
पॉलिथीन की चादर से ढक कर मिट्टी को दबा कर अंदर की हवा और नमी को ट्रैप करके करके रखा जाना चाहिए, इस विधि की बेहतर सफलता के लिए पॉलिथीन की परत को अगले 7 से 10 सप्ताह तक वैसे ही लगा रहने देना चाहिए। अधिक समय तक पॉलिथीन लगी रहने से उसके अंदर के क्षेत्र में स्थित मृदा का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे मृदा में उपलब्ध कई हानिकारक बैक्टीरिया स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और पौधशाला को भविष्य में होने वाले रोगों से आसानी से बचाया जा सकता है।
इसके अलावा दक्षिणी भारत के राज्य और तटीय क्षेत्रों में 'जैविक विधि' की मदद से भी मृदा शोधन किया जाता है। इस विधि का इस्तेमाल मुख्यतः मृदा में उगने वाली फसल में होने वाले आर्द्र-गलन रोग से बचाने के लिए किया जाता है। इस विधि में 'ट्राइकोडरमा' की अलग-अलग प्रजातियों का बीज के बेहतर उपचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

कंपोस्ट और उचित कार्बनिक खाद की मात्रा वाले जैविक पदार्थों का उपयोग मृदा के शोधन को और बेहतर बना देता है।

वर्तमान में कई किसान भाई जैव पदार्थों का इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसे पदार्थों के प्रयोग से पहले ध्यान रखना चाहिए कि उस पदार्थ में जीवित और सक्रिय बीजाणु पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए।
जैविक पदार्थों के प्रयोग के बाद पौधशाला को ऊपर से ढक देना चाहिए क्योंकि मृदा को बारिश एवं धूप से बचाने की आवश्यकता होती है।
जैविक विधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए किसानों की लागत में भी कमी देखने को मिलती है।

इसके अलावा 'रासायनिक विधि' की मदद से भी मृदा शोधन किया जाता है, जिसमें फार्मएल्डिहाइड और फॉर्मलीन जैसे रसायनिक उर्वरकों का एक घोल तैयार किया जाता है, जिसे समय-समय पर मृदा के ऊपर अच्छी तरह छिड़का जाता है।

इस विधि में भी पॉलिथीन की चादर का इस्तेमाल करके वाष्पीकरण और नमी को ट्रैप किया जाता है।

पौधशाला प्रबंधन से किसानों को होने वाले लाभ :

खुले खेत की तुलना में पौधशाला में किसी भी फसल की पौध जल्दी तैयार होती है और उसकी गुणवत्ता बेहतर होने के साथ ही उपज भी अधिक प्राप्त होने की संभावना होती है।

इसके अलावा पौधशाला में फसल उगाना आर्थिक रूप से कम खर्चीला होता है, इससे किसानों को होने वाला मुनाफा अधिक हो सकता है।

पौधशाला प्रबंधन का एक और फायदा यह भी है कि इसमें बीज की बुवाई करने से लेकर अंकुरण तक पौधे के विकास के लिए आवश्यक जलवायु और तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, इससे फसल में होने वाले रोगों से भी बचा जा सकता है।

पौधशाला की मदद से घर पर ही पौध तैयार करने से भूमि की जुताई में होने वाले खर्चे को कम किया जा सकता है, साथ ही श्रम पर होने वाला खर्चा भी बचाया जा सकता है। इसीलिए कृषि वैज्ञानिकों की राय में छोटे और सीमांत किसानों को खुले खेत की तुलना में पौधशाला विधि की मदद से ही फसल उत्पादन करना चाहिए।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में पौधशाला विधि से खेती करने वाले किसानों की राय में उन्हें पूरी फसल से होने वाले मुनाफे से भी ज्यादा फायदा केवल पौधशाला में तैयार नर्सरी से ही हो जाता है। कई सब्जी की फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार संकर किस्म के बीज बाजार में काफी महंगे बिकते हैं, इसलिए पौधशाला में ही नर्सरी की मदद से बुवाई कर बीजों को भी बचाया जा सकता है। पौधशाला प्रणाली में किसानों को किसी भी प्रकार के बीजों को चुनने की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि इस विधि में बीज उपचार के माध्यम से सस्ते बीजों को भी बेहतर उत्पादन लायक बनाया जा सकता है।

रासायनिक उर्वरकों का ज्ञान रखने वाले कई किसान भाई फफूंद नाशक और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर बीजों का बेहतर उपचार कर नर्सरी से होने वाली उपज को बढ़ाने में सफल हुए हैं।

आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को पौधशाला प्रणाली की मदद से क्यारियां बनाने और बेहतर उपज वाली मृदा और बीज उपचार के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिल गई होगी और Merikheti.com द्वारा उपलब्ध करवाई गई इस जानकारी से, आप भी भविष्य में वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई गुणवत्ता युक्त सब्जी उत्पादन की बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे।

बागवानी किसानों के लिए समस्या बनती जलवायु परिवर्तन, कैसे बचाएं अपनी उपज

औद्योगिक क्रांति के बाद से पूरे विश्व भर में ग्लोबलवार्मिंग (Global warming) और जलवायु परिवर्तन (Climate change) केवल मानव जाति के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए एक समस्या बनकर उभरा है।

एक समय जिस स्थान पर अच्छी बारिश होती थी आज वहां हर वर्ष सूखा पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण जलवायु में परिवर्तन ही है। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर रहने वाले हर प्रजाति को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ता है, इसी नुकसान की वजह से पिछले कुछ वर्षों से फलों के लिए बागवानी खेती करने वाले किसान भाइयों को उपज में काफी कमी देखने को मिली है। उत्तरी भारत के राज्यों में फल उगाने वाले किसान अब नई वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से कुछ उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 में भारत में लगभग 7 मिलियन हेक्टर क्षेत्र में फल उगाए जाते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 93 मिलियन टन फल प्राप्त होते हैं।भारतीय बागवानी कृषि विश्व भर के उत्पाद में लगभग 10% हिस्सेदारी निभाती है।

आम, केला और अमरूद तथा अनार, अंगूर और पपीता जैसे प्रमुख फसलों के उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।

जलवायु परिवर्तन से फलदार पौधों को होने वाले नुकसान :

वैश्विक तापमान में परिवर्तन और बारिश के पैटर्न में हुए बदलाव की वजह से फलदार पौधों में निम्न नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिले हैं :

1- तापमान में वृद्धि होने के कारण किसी भी पौधे पर लगने वाले फलों की परिपक्वता का समय कम हो जाता है। इसकी वजह से वह जल्दी तैयार हो जाते हैं और इन्हें बाजार में जल्दी बेचना पड़ता है, इससे फलों के भंडारण की संभावना कम हो जाती है और उन्हें तुरंत भेजना पड़ता है। इस वजह से किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते और उनका मुनाफा कम हो जाता है।

2- अधिक कार्बन-डाइऑक्साइड की वजह से फलों में स्टार्च और ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे इन फलों के सेवन से रक्तचाप और शुगर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है।
3- अधिक ग्लूकोज संचित करने वजह से इन फलों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है।
4- इसके अलावा विश्वत रेखा (Equatorial area) के आसपास वाले क्षेत्रों में आसमान में अधिक समय तक बादल छाए रहने की वजह से वहां पर उगाए जाने वाले आम और अमरूद के फलों में एस्कोरबिक अम्ल (Ascorbic acid) की मात्रा घट जाती है, जिस वजह से फल में पाई जाने वाली मिठास कम हो जाती है और फुल पूरी तरह से फीका लगता है। इस कारण उसकी बाजारू मांग में भी कमी देखने को मिलती है।
5- बदली हुई जलवायु परिस्थितियां नए प्रकार के रोगों को जन्म दे रही है, तापमान में बढ़ोतरी होने से कई सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया पौधों की जड़ों और तने को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके अलावा इन बैक्टीरिया की वर्द्धि दर भी तेज हो जाती है, जो बाद में सीधे फलों को ही खाने लगते हैं। इन रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो लागत को बढ़ाकर आर्थिक दबाव पैदा करते हैं।

ऊपर बताए गए नुकसान को ध्यान में रखते हुए अब कृषि वैज्ञानिक इनके निदान के लिए प्रयास कर रहे हैं।

फलदार पौधों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के कुछ उपाय :

हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक विधियों की मदद से इसे कम भले ही किया जा सकता है।
1- गर्मी के मौसम में पेड़ों की कटाई-छंटाई कम करनी चाहिए और पेड़ के तने और उसकी मोटी शाखाओं को सफेद रंग से पुताई कर देने पर सूरज से आने वाली किरण का प्रभाव कम पड़ता है, जिससे फल के पकने में लगने वाला समय अधिक हो जाता है और किसान को अच्छी उपज के साथ ही अच्छा मुनाफा हो पाता है।
2- अधिक गर्मी पड़ने से बाग के क्षेत्र में नमी की मात्रा कम हो जाती है। नमी को बरकरार बनाए रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्र की नमी की जांच करनी चाहिए और बाग की नियमित और उचित सीमित मात्रा में सिंचाई करनी चाहिए।
3- यदि आप के बाग में पिछले सीजन के कुछ पौधे बचे हुए हैं और उनसे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें काटकर उनकी पलवार बना देनी चाहिए, जिससे बाग के क्षेत्र के तापमान को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
4- रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैविक खाद का इस्तेमाल करने से पौधों में नमी बनी रहती है और उन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। इससे रासायनिक उर्वरक खरीदने का खर्चा भी बच जाता है।
5- अधिक ठंड पड़ने वाले क्षेत्रों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए पतझड़ के समय पौधों के नीचे गिरी हुई सूखी टहनियों और पत्तियों को इकट्ठा कर जलाने से भी फायदा हो सकता है।
6- इसके अलावा पत्तियों को जलाने से होने वाले धुआं की वजह से कई प्रकार के छोटे कीट और फल मक्खी पौधों से दूर भाग जाते हैं, इससे आपकी फलों की निरन्तर सुरक्षा भी हो पाती है।
7- फलों की छोटी पौध को हमेशा पश्चिम और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करते हुए लगाना चाहिए, इससे सूरज की किरणों का कम प्रभाव पड़ता है।

पिछले 3 वर्षों से उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में उगने वाले 'अल्फांसो आम' की उपज में काफी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में उगने वाले 'अवधपुरी केला' तथा उत्तर प्रदेश में उगने वाले 'इलाहाबाद सफेदा अमरूद' और जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में लगने वाले 'लाला अम्बरी सेब' की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही इनके स्वाद में पायी जाने वाली मिठास भी कम होती जा रही है।

आशा करते हैं कि Merikheti.com के द्वारा बागवानी फलों का उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव और उनसे बचने के उपायों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आप भी बागवानी फलों की खेती करते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए और ऊपर बताई गई जानकारी का फायदा उठाकर अपने बाग की उपज को वापस पहले की स्तर पर ले जाकर अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे।

सरकारी नीतियां

किसानों की फसल को बचाने के लिए शेडनेट पर मिलेगा 75% तक का अनुदान

सर्दियों में फसल को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए खेत में शेडनेट (shade net) लगायें। शेडनेट की सहायता से किसान कई एकड़ फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। किसान अपनी फसल की देख रेख को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं, आंधी, तूफान और असमय बारिश के कारण फसलों में काफी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है, जिसके चलते किसान बहुत असमंजस और नुकसान होने के भय में जीते हैं। सर्दियों में फसल को प्रतिकूल मौसम एवं कीटों से अच्छा खासा नुकसान होता है।

किसानों को अच्छी तरह फसल करने के लिए नई नई फसलीय तकनीक उपलब्ध हैं, जिनको किसान तक पहुँचाने के लिए सरकार किसानों को अनुदान मुहैय्या कराती है, इससे किसानों को इसे खरीदने में आसानी होती है। बिहार सरकार के माध्यम से शेड फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को शेड नेट खरीदने पर ७५ फीसद तक अनुदान प्रदान कर रही है, जिससे किसान १००० से ४००० मीटर तक अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए शेड नेट अनुदान पर खरीद सकते हैं।

शेड नेट से किसानों को क्या लाभ मिलता है ?

शेड़ नेट की सहायता से किसान अपनी फसल को मौसम की चपेट से लेकर कीट व रोगों से बचाते हैं, शेड नेट से खाद्य सब्जियों फल फ्रूट इत्यादि की देखभाल अच्छी तरह होती है। शेड नेट के जरिये किसान फसल की ओर से बिल्कुल निश्चिंत होकर रह सकते हैं, फसल को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तरीके से करने के लिए किसान शेड फार्मिंग (shade farming) की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। शेड फार्मिंग बहुत ही फायदेमंद होती है किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए।

शेड नेट अनुदान पर खरीदने के लिए कहाँ आवेदन करें ?

बिहार सरकार द्वारा शेड नेट ७५ प्रतिशत अनुदान पर खरीदने के लिए ७१० रूपये का प्रति वर्ग मीटर व्यय बताया है। बिहार में प्रत्येक किसान १००० से ४००० वर्ग मीटर तक अपनी फसल को बचाने के लिए ७५ % अनुदान पर शेड नेट खरीद सकते हैं। जिसके लिए आर्थिक रूप से असमर्थ किसान horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें एवं योजना का लाभ उठाने के साथ साथ फसल को सुरक्षित रखने का इंतजाम भी करलें। यदि फसल सुरक्षित होगी तो पैदावार स्वतः ही बढ़ेगी, जिसका लाभ या मुनाफा प्रत्यक्ष रूप से किसान को होगा।

बिहार सरकार द्वारा शेड नेट के लिए दिए जाने वाले अनुदान से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

किसानों के उत्पादन को अच्छा करने के मकसद से, बिहार सरकार द्वारा शेड फार्मिंग तकनीक को अपनाने के लिए शेड नेट पर ७५% तक का अनुदान दिया जाना बेहद सराहनीय कार्य है। इससे किसानों की फसल का उत्पादन किसी भी प्राकृतिक आपदा अथवा रोग इत्यादि से प्रभावित नहीं होगा। किसानों को बेहतर उत्पादन करने से काफी सहूलियत मिलेगी। इस वजह से उनकी आर्थिक स्तिथि एवं जीवनशैली में भी बेहतर सुधार आएगा।

रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर 80 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है ये राज्य सरकार, यहां करें आवेदन

रबी का सीजन प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में खेतों की जुताई की जा रही है ताकि खेतों को बुवाई के लिए तैयार किया जा सके। बहुत सारे खेतों में अब भी पराली की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण खेतों को पुनः तैयार करने में परेशानी आ रही है। खेतों से फसल अवशेषों को निपटाना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है, इसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी होती है। अगर किसान एक बार पराली का प्रबंधन कर भी ले, तो इसके बाद भी खेत से बची-कुची ठूंठ को निकालने में भी किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यदि आज की आधुनिक खेती की बात करें तो बाजार में ऐसी कई मशीनें मौजूद है जो इस समस्या का समाधान चुटकियों में कर देंगी। इन मशीनों के प्रयोग से अवशेष प्रबंधन के साथ-साथ खेतों की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोत्तरी होगी।

ऐसी ही एक मशीन आजकल बाजार में आ रही है जिसे रोटरी हार्वेस्टर मशीन कहा जाता है। यह मशीन फसल के अवशेषों को नष्ट करके खेत में ही फैला देती है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। इस मशीन के फायदों को देखते हुए बिहार सरकार ने मशीन की खरीद पर किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के लिए कहा है।

क्या है रोटरी हार्वेस्टर मशीन

इस मशीन को रोटरी मल्चर भी कहा जाता है, यह मशीन बेहद आसानी से खेत में बचे हुए अनावश्यक अवशेषों को नष्ट करके खेत में फैला देती है, जिसके कारण खेत में पर्याप्त नमी बरकरार रहती है। इसके साथ ही खेत में फैले हुए अवशेष डीकंपोज होकर खाद में तब्दील हो जाते हैं। अवशेषों के प्रबंधन की बात करें तो यह मशीन खेत में उम्दा प्रदर्शन करती है।

रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर बिहार सरकार कितनी देती है सब्सिडी

अगर रोटरी हार्वेस्टर मशीन की बात करें तो उस मशीन पर बिहार सरकार किसानों को 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करती है। यह सब्सिडी बिहार का कृषि विभाग 'कृषि यंत्रीकरण योजना' के अंतर्गत किसानों को उपलब्ध करवाता है।

बिहार सरकार के द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि बिहार का सामन्य वर्ग का किसान रोटरी हार्वेस्टर मशीन लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसे बिहार सरकार मशीन की खरीद पर 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी या अधिकतम 1,10,000 रुपये प्रदान करेगी।

इसके साथ ही यदि बिहार का एससी-एसटी, ओबीसी और अन्य वर्ग का किसान रोटरी हार्वेस्टर मशीन खरीदना चाहता है, तो आवेदन करने के बाद सरकार उसे रोटरी मल्चर पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और रूपये में अधिकतम 1,20,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी।

रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार के आदेश के अनुसार रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को बिहार का निवासी होना जरूरी है। साथ ही उसके पास कृषि योग्य भूमि भी होनी चाहिए। ऐसे किसान जो रोटरी हार्वेस्टर मशीन पर सब्सिडी प्राप्त चाहते हैं, वो बिहार कृषि विभाग के पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। किसानों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागजात, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर अपने साथ रखना चाहिए। इनकी डीटेल आवेदन भरते समय किसान से मांगी जाएगी।

इसके अलावा यदि किसान कृषि यंत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कृषि विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18003456214 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मखाना की खेती करके किसान हो सकते हैं मालामाल मिल रहा है 75% सब्सिडी

मखाना (Fox nuts) की खेती करने के लिए बिहार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरी दुनिया में मखाने का 90% उत्पादन सिर्फ बिहार में होता है।

बिहार सरकार मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, आप अगर मखाने की खेती करना चाहते हैं तो इन योजनाओं का लाभ लेकर आप मखाने की खेती कर बेहतर मुनाफा अर्जित कर सकते है। बिहार में सबसे ज्यादा मखाने की खेती मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिलों में की जाती है। यहां के किसान मखाने की खेती करके बढ़िया मुनाफा अर्जित करते हैं। बिहार सरकार मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर शानदार प्रयास कर रही है और किसानों को प्रेरित भी कर रही है, जिससे किसान मखाने की खेती में पहले से ज्यादा रूचि ले रहे हैं।

कुछ समय पहले मिथिलांचल की मखाना को जियो टैग मिला था। इसके बाद से राज्य सरकार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर दे रही है। राज्य सरकार के द्वारा मखाना विकास योजना भी चलाई गई है, जिसके अंतर्गत मखाना उपजाने वाले किसानों को 75% की सब्सिडी दी जा रही है। मखाना उपजाने के लिए 75 % सब्सिडी का राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने से किसानों को आर्थिक बल और सहयोग मिल रहा है, जिससे किसान मखाने की खेती कर बंपर लाभ कमा रहे है। अगर आप भी मखाने की खेती कर अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ ले सकते है।

इस योजना का लाभ ले करके आप अपना खुद का एग्री बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बिहार के किसान मखाने की खेती के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, जिससे किसानों को बंपर फायदा हो रहा है और किसान खुश नजर आ रहे हैं।

क्या है मखाना विकास योजना

बिहार कृषि विभाग के द्वारा मखाने की क्वालिटी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मखाना विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत मखाने के उच्चतम क्वालिटी के बीजों का उत्पादन और क्षमता के विकास करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य तौर पर इस योजना का लाभ लेने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष तौर पर कटिहार, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा,अररिया,पश्चिमी चंपारण मधेपुरा, सीतामढ़ी और मधुबनी को कवर किया जा रहा है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और मखाने की खेती कर 75% की सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बिहार सरकार के कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल state.bihar.gov.in/krishi/ पर जाकर इस योजना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार प्रयासरत है और मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार लोगों को जागरुक भी कर रही है।

साबौर मखाना-1 और स्वर्ण वैदेही प्रभेद मखाने को उच्चतम क्वालिटी का मखाना माना जाता है। राज्य सरकार अब इन्हीं दो उच्चतम क्वालिटी के मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है।

बिहार राज्य सरकार के मापदंडों के अनुसार इन दोनों किस्मों के मखाने की खेती करने के लिए ₹97000 की अधिकतम लागत बताई गई है। जिसमें 75 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार खुद दे रही है, यानी ₹72750 तक का अनुदान इन दोनों किस्मों के मखाने की खेती करने के लिए दिया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा गाइडलाइंस में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप यह सब्सिडी की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। खेती के साथ-साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मखाने की प्रोसेसिंग करने के लिए यानी उद्योग लगाने के लिए किसान और व्यक्तिगत निवेशकों को 15% की सब्सिडी मिल रही है।

मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (FPO/FPC) से भी करीब २५% के अनुदान का प्रावधान पहले से ही है। खेती के साथ-साथ किसान को एग्री बिजनेस से जोड़ने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

किसानों को खेती करने के साथ-साथ उन्हें एग्रीबिजनेस से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार किसानों को लगतार प्रेरित कर रही है। बिहार सरकार किसानों के भविष्य को संवारने को लेकर संकल्पित है, पिछले दिनों में जिस तरह से कृषि विभाग के द्वारा एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने को लेकर घोषणा करना और योजनाओं को धरातल पर लागू कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण देने से साफ जाहिर होता है, कि आने वाले समय में किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और बेहतर मुनाफा अर्जित कर के खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे।

अब मात्र 3% ब्याज के साथ किसानों को मिलेगा 2 करोड़ रुपये तक का लोन

किसान अच्छा उत्पादन करने के बाद भी अभी काफी परेशान चल रहे हैं क्योंकि आज की दुनिया में देखा जा रहा है कि किसानों की फसल, रखरखाव की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण खराब हो जाती है। उनको मेहनत करके उपजाने के बाद भी बाजार में सही कीमत नहीं मिल पाता, जिससे की उनको हर समय घाटे का सौदा करना पड़ता है। आए दिन यह भी देखा जाता है कि जिस समय अनाज का उत्पादन होता है उस समय किसानों को रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कम दाम में भी इन्हें बाजार में बेच देना पड़ता है। लेकिन अब किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, जिससे कि किसानों को काफी सहूलियत मिलेंगे।

इस नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी (National Agriculture Infra Financing Facility) स्कीम में भारत सरकार ने किसानों के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का प्रावधान रखा है, आपको बता दें कि इस योजना में 7 साल के अंदर लोन चुकता करने के लिए बैंक गारंटी के रूप में सरकार की तरफ से भी सुविधा प्रदान किया जाएगा। उतना ही नहीं अब इस योजना के तहत किसानों को सात वर्ष तक ब्याज में 3% की छूट भी दिया जा रहा है, जिससे किसान सहूलियत के साथ बैंक का पैसा वापस कर सकेंगे।

नेशनल एग्रीकल्चर इन्फ्रा फाइनेंसिंग फैसिलिटी योजना में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है और लोन आवेदन की प्रक्रिया का हिंदी में वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें : https://agriinfra.dac.gov.in/Content/video/Agri_pro_Hindi_6.mp4

आपको यह भी बताते चलें की अब किसान इस योजना के लाभ मिलने के कारण वेयरहाउस से लेकर कोल्ड चेन कोल्ड स्टोर लॉजिस्टिक यूनिट्स की स्थापना कर सकेंगे और इसका फायदा यह होगा कि किसान अपनी उपज को सुरक्षित कुछ दिन बाद भी बाजारों में बेच सकेंगे।

गौरतलब हो कि पिछले दिनों किसानों का पूरी उपज बाजार में नहीं बिकने से किसान काफी परेशान होते थे और लंबे समय तक अपने अनाज को स्टोर करके भी नहीं रख सकते थे। लेकिन इस योजना के आने के बाद किसानों में काफी खुशी है, क्योंकि अब किसानों के उपज अच्छे मुनाफ़े के साथ लंबे समय के बाद भी बाजार में बिक सकता है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि इस योजना की अवधि 10 वर्ष की है जो कि 2020 से शुरू होकर 2029 तक चलेगी। इस योजना में किसानों को ₹2,00,00,000 तक तत्कालीन 3% सालाना ब्याज दर में छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इस योजना के तहत ऋण के लिए कवरेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान, पैक्स, लाइबिलिटी ग्रुप, कृषि उद्यमी भी शामिल हैं।

कम लागत में किसान इस पशु को पालकर हो सकते हैं मालामाल, सरकार दे रही है 50% सब्सिडी

किसान पारंपरिक खेती से परेशान होकर अब पशुपालन की तरफ रुख कर रहे हैं। पारंपरिक खेती में किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार पशुपालन के लिये बहुत सारी सुविधाएँ व सब्सिडी भी दे रही है, जिससे किसानों को पशु पालन करना और भी आसान हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि जिन किसानों के पास भूमि काफी कम है, वहाँ पशुपालन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों को यह पता नहीं है कि कौन से पशु को पालने में उनको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पारंपरिक पशुपालन के अलावा इन पशुओं को पालने से आपको मिल सकता है बेहतर मुनाफा।

भेड़ पालन क्यों हो रहा है लोकप्रिय

देशभर में गाय, भैंस, बकरी के अलावा अभी जो सबसे ज्यादा पशु पालन हो रहा है, वह है भेड़ (sheep) पालन। आए दिन भेड़ पालन (Sheep rearing) में किसान काफी रुचि ले रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि भेड़ पालने में खर्च भी कम लगता है और मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाता है। किसानों में भेड़ पालन लोकप्रिय होने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसके खाने के लिए चारा की उपलब्धता भी काफी आसान है। अधिकांश भेड़ हरी पत्तियाँ व घास का सेवन करती हैं, जिससे किसानों को कम लागत में भी उसके लिए चारा उपलब्ध कराना आसान होता है।

किसानों के बीच इसका लोकप्रिय होने का सबसे मुख्य कारण यह है, कि उसके हर एक चीज़ का प्रयोग नए नए उत्पाद को बनाने में किया जाता है। जैसे उसके बालों का प्रयोग ऊन (wool) बनाने में किया जाता है, वहीं उसके चमड़े का प्रयोग बहुत सारे उत्पादों को बनाने के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं इसके अलावा भी भेड़ों के दूध की बाजार में अच्छी कीमत किसानों को मिल जाती है, जिससे किसान की आय पहले की तुलना में और भी अधिक बढ़ जाता है।

सरकार दे रही है सब्सिडी

गौरतलब हो कि भेड़ पालन के लिए केंद्र सरकार के तरफ से भी अनेकों प्रकार की सब्सिडी किसानों के लिए उपलब्ध है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत केंद्र सरकार भेड़ पालन पर 50% तक की सब्सिडी की सुविधा किसानों को दे रही है। इतना ही नहीं इसके अलावा भी विभिन्न राज्य सरकारे अपने राज्य में भेड़ पालन के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे अभी भेड़ पालन किसानों के बीच काफी लोकप्रिय बना हुआ है।

कम लागत में शुरू करें व्यवसाय

आपको यह भी बता दें कि किसान लगभग ₹1,00,000 से भी व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि बाजार में एक भेड़ की कीमत लगभग ₹8000 के आसपास है। भेड़ की ऊन (wool) की बनी हुई कपड़े की मांग काफी ज्यादा है, क्योंकि ठंडे प्रदेश में यह काफी उपयोगी होता है। आपको बता दें की इसके बने हुए कपड़े काफी गर्व होता है, जिसको अत्यधिक ठंड में उपयोग किया जाता है। आपको यह भी बता दें की भेड़ के ऊन का कंबल लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके ऊन के अलावा इसका मांस और इसका दूध भी बाजार में अच्छा मूल्य देता है, जिससे किसानों का रुझान इसके तरफ काफी बढ़ रहा है। इतना ही नहीं भेड़ के द्वारा निकला हुआ गोबर भी काफी उर्वरक माना जाता है, जिसको किसान अपने खेतों में प्रयोग कर फसल को भी अच्छा उगा सकते हैं, जिससे भी किसान को काफी लाभ मिलेगा। भेड़ के गोबर की कीमत बाजार में काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें उर्वरक शक्ति अधिक पायी जाती है, जिसका प्रयोग बड़े बड़े किसान अपने खेती के लिए करते हैं।

बागवानी लगाने के लिए बिहार सरकार किसानों को दे रही है 25000 रुपया

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हाल के दिनों में युवाओं का खेती के तरफ काफी रुझान बढ़ा है, जिससे खेती के क्षेत्र में भी काफी नए-नए प्रयोग और नए नए तकनीकी प्रयोग भी हो रहे हैं। इसी नए तकनीक के क्रम में जो आज इस लेख में जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको जानकर आप काफी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अब किसान बिना जमीन के भी अच्छा कमा सकते हैं।

हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में आप देख रहे होंगे कि लोग छत पर काफी तरीके का खेती और बागवानी लगा रहे हैं। इसके लिए सरकार भी काफी सुविधाएं दे रही है, क्योंकि इसमें वैसे किसान भी हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। आपको बता दें कि इस तकनीक के कारण घर की महिलाएं भी अब खेती कर कमाने लगी हैं। जिन किसानों के पास जमीन की समस्याएं थी उनके लिए यह तकनीक वरदान की तरह साबित होते दिख रहा है।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि, सिर्फ किसान ही नहीं इसमें अच्छे खासे बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस तकनीक के कारण वह अपने से उगाए हुए सब्जी का आनंद ले सकें। यह तकनीक खासकर कोरोना जैसी महामारी में लोगों को काफी मदद की है, जिस समय आम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, वह अपने छत पर इस तरीके के तकनीकों का उपयोग कर सब्जियां उगा सकते थे। आपको बता दें कि इस खेती के लिए सरकार भी काफी मदद कर लोगों को सब्सिडी दे रही है। आपको बता दें कि इस तरीके का प्रयोग कर शहरी क्षेत्रों के लोग अपने छत पर सब्जी टमाटर धनिया आदि को उपजा कर काफी मुनाफा कमा सकते हैं।

इस तकनीक का प्रयोग दो तरीके से हो रहा है, पहला तरीका जिसमें लोग अपने घर की छतों पर गमला में मिट्टी के साथ कुछ ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कर आसानी से सब्जी उगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हाइड्रोपोनिक्स तरीके से किसान सब्जी और फल उगा रहे हैं, जिसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस तकनीक में आप सिर्फ पानी का प्रयोग कर फल और सब्जी उगा सकते हैं। आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स तरीके से सब्जी और फल उगाने में जलवायु नियंत्रण जैसे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस तरीके से सब्जी उगाने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इस हाइड्रोपोनिक्स तरीके की खेती में आद्रता ज्यादा से ज्यादा होने पर भी फसल अच्छी होती है।

सरकार भी दे रही है सब्सिडी

इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लोगों को छत पर बागवानी मिशन के तहत ₹५०००० तक लोन तथा ५०% सब्सिडी देने की योजना बनाई है। अगर ठीक से देखा जाए तो इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लोगों को ₹२५००० रुपए देने की योजना बनाई है।

अप्लाई करने का तरीका

जो भी व्यक्ति इस तरीके की खेती करना चाहते हैं वह बिहार सरकार के हॉर्टिकल्चर के वेबसाइट पर जाकर वहां अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि, इस योजना में आवेदन की शुरुआत 26 अक्टूबर से ही कर दी गई है। अगर आप भी चाहते हैं छत पर बागवानी लगाना और पैसा कमाना तो तो जल्द से जल्द करें आवेदन कहीं ए मौका आपके हाथों से निकल ना जाए।

मध्य प्रदेश: सरकार मेहरबान, इन यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी

किसान का औजार ही उसकी जिन्दगी को संवारने का असल हथियार होता है। अगर किसान के पास सही यंत्र हो, सही औजार हो तो वह अपनी खेती और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिससे कि उनकी जिन्दगी खुशहाल हो सके, इसे लेकर राज्य सराकारें और केन्द्र सरकार कई योजनाएं भी चलाती रहती हैं। हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही एक फैसला लिया है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, सरकार ने कृषि से संबंधित कई योजनाओं को प्रोत्साहन देने का फैसला लिया है।

जाहिर है, ऐसे फैसलों से किसानों को बेहतर फ़ायदा मिल सकेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ सकेगी। हालांकि, सरकार ने नरवाई जलाने के सिस्टम को कम करने और ख़त्म करने का भी संकल्प लिया है। लेकिन, सबसे बड़ी खबर यह है कि मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रूपये आवंटित किए गए, वहीं दूसरी तरफ फसल अवशेष के बेहतर मैनेजमेंट के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। यदि किसी किसान को इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो वो dbt.mpdage.org में जाकर योजना से संबंधित नियम कायदे पढ़ सकता है, इसके अलावा किसान उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकता है। जहां पर योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।
सरकार ने पावर ड्रिवेन एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीदारी पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। लघु, सीमान्त, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों को पचास प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के लिए भी 100 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे, जिससे भारी संख्या में मत्स्यजीवी फ़ायदा उठा सकेंगे।

शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत स्कीम भी चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, सबसे पहले 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक लोन दिया जाएगा। इस पैसे से उन्हें वाहन दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल पीडीएस के तहत राशन को सुदूर क्षेत्रों तक भेजने में किया जाएगा।

जाहिर है, इन योजनाओं से आम किसान, बेरोजगार युवा और मत्स्यजीवी समुदाय को काफी फायदा होने जा रहा है। अगर ये सारे स्कीम्स जमीन पर पूरी तरह ईमानदारी से लागू हो जाए, तो इसमें कोइ संदेह नहीं कि किसानों को इसका फ़ायदा न मिले या उनकी जिन्दगी में बदलाव न आए।

इस सरकारी योजना में मिलता है गजब का फायदा, 50% तक का मिलता है किसानों को अनुदान

किसानों को इस योजना से गजब का फायदा मिलता है। जो किसान सिंचाई कि समस्या से परेशान है उनके लिए यह योजना बड़ा ही कारगर साबित होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से किसानों के सिंचाई की समस्या से समाधान निकालने के लिए जोर दिया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में कृषि के मामले में किसानों को बेहतर मुनाफा अर्जित करने के लिए सरकार द्वारा लगता नए-नए योजनाओं को धरातल पर लागू कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

सरकार किसानों के बेहतर भविष्य के लिए चिंतित है। सरकार ने किसानों के सिंचाई को समस्या को देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का नाम खेत तालाब योजना (Khet Talab Yojna; Farm Pond Scheme) है। खेत तालाब योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के समस्या से वंचित कराना है। खेती करने के लिए किसान को जल की आवश्यकता होती है। जल के द्वारा ही उगाए जा रहे फसलों की सिंचाई की जाती है। बहुत सारे किसान सिंचाई के लिए आवश्यक जल का उपयोग ट्यूबवेल और अन्य साधनों से करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए खेत तालाब योजना लाकर के किसानों को सिंचाई की समस्या से उबारने का भरपूर प्रयास कर रही है।

क्या है खेत तालाब योजना

इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में एक छोटे से भाग में तालाब का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बारिश के पानी को एकत्रित किया जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के समस्या से उबारना है। खेतिहर जमीन में तालाब निर्माण के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाता है, अपने जमीन के भूभाग में किसान तालाब का निर्माण करा करके इसमें मछली का पालन भी कर सकते हैं। इससे किसानों को सिंचाई की समस्या से वंचित होने के साथ-साथ ट्यूबवेल में लगने वाली किसानों की लागत भी कम हो जाती है।

सरकार के द्वारा दिया जाता है इतना प्रतिशत का अनुदान

इस योजना का सबसे बेहतर फायदा यह है कि सरकार के द्वारा 50% अनुदान दिया जाता है, यानी आपके लागत का आधा सरकार खुद आपको देती है।
खेतिहर जमीन में तालाब बनाने के लिए लगभग ₹100000 का खर्चा आता है, जिसमें ₹50000 इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा आपको तालाब के निर्माण के लिए मिल सकता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तब।

वही बड़े तालाब के निर्माण के लिए 2 से ढाई लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें आधी रकम सरकार के द्वारा आप को अनुदान के रूप में दिया जाता है। अभी तक उत्तर प्रदेश के सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लगभग दो हजार से ज्यादा तालाबों का निर्माण करवाया है। जिसमें 50 प्रतिशत की राशि सरकार के द्वारा किसानों को तालाब निर्माण के लिए अनुदान के रूप में दिया गया है।

खेत तालाब योजना से किसानों को मिलेंगे ये लाभ :

यह योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। खेत तालाब योजना का किसान अगर लाभ लेते हैं, तो इससे सबसे बेहतर फायदा यह है कि जल संरक्षण को पूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा। किसानों को सच्चाई की समस्या जो उत्पन्न होती है, उसका निवारण अपने ही जमीन में निर्माण कराए गए तालाब के द्वारा आसानी से हो जाएगा। साथ ही साथ किसान को एक बेहतर फायदा यह मिलेगा कि निर्माण कराए गए तालाब में वह मछली का पालन आसानी से कर पाएंगे और उससे भी मुनाफा अर्जित करने में सक्षम हो पाएंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए तत्काल ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य माना गया है।
वहीं दूसरी तरफ अगर आप पहले से ही किसी तालाब योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इस योजना का लाभ आपको प्राप्त नही होगा।
अगर आप एक रजिस्टर्ड किसान है तो इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
अब अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है और सिंचाई की समस्या से वंचित होकर उगाए गए फसलों पर अधिक लाभ कमाना चाहते है, तो आपको जल्द ही इसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त दस्तावेज होना अनिवार्य है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक खाते का विवरण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर और खाते का दस्तावेज होना अनिवार्य माना गया है।
खेत तालाब योजना आवेदन के लिए आप यूपी कृषि विभाग पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेबसाइट पर जाएँ: https://upagripardarshi.gov.in/Index-hi.aspx

पारदर्शी सेवा वेबसाइट के होम पेज पर आप उपर मीनू में " योजनायें > मुद्रा एवं जल सरंक्षण > राज्य प्रायोजित विकल्प " पर क्लिक करें।
तो देर ना करें जल्दी इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें और इस योजना का बेहतर लाभ ले करके अपने आय को खेती के माध्यम से दुगुना करें।

किसान समाचार

इधर गन्ना पहुंचा, उधर भुगतान तैयार

यूपी में गन्ना किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी गन्ना मिलों का भुगतान। कई-कई साल बीत जाते थे फिर भी गन्ना फसलों का मूल्य किसानों को नहीं मिलता था। अब ये सब बीते जमाने की बात हो गई। इधर आपका गन्ना मिल में पहुंचा नहीं कि क्वालिटी चेक करके आपका भुगतान तैयार हो गया।

एक दौर था जब किसान परेशान रहा करते थे, उनकी परेशानी इस बात को लेकर ज्यादा थी कि वो जो गन्ना उपजाते हैं। उसकी कीमत उन्हें नहीं मिलती, मिलती भी है जो छह माह के बाद वह भी आधी-अधूरी। इसको लेकर किसान परेशान रहा करते थे, कई किसानों ने कर्ज लेकर गन्ने की फसल लगाई थी। जब उन्हें भुगतान नहीं मिला तो साहूकार छाती पर चढ़ बैठा। कई किसानों ने अपनी जमीनें बेच दी कई ने अपनी जान दे दी।

अब भुगतान मिलने लगा है

दौर बदल गया सरकार बदल गई, योगी आदित्यनाथ जी जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस समस्या का समाधान खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। चूंकि वह खुद गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहे थे, लिहाजा उन्हें पता था कि समस्या कहां है। देखते ही देखते चीजें बदल गईं, सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान हो चुका है। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने उपलब्ध कराया है, योगी आदित्यनाथ जी के अनुसार कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने सभी चीनी मिलों का संचालन किया।

किसानों को 1.80 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया। एक बार फिर चीनी मिलों में पेराई सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने गोरखपुर जिले के पिपराइच व मुंडेरवा में चीनी मिलों को चलाकर गन्ना किसानों के हित में बड़ी पहल की है। अब तो आप अपना गन्ना लेकर जाएं, उसकी क्वालिटी चेक करवाएं, गन्ने की उधर पेराई खत्म हुई, उधर आपका भुगतान तैयार। अब कोई झंझट नहीं होगी

तीन लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

उत्तर प्रदेश में धान की खरीद भी शुरू हो चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलाधिकारियों को दो टूक निर्देश दे दिया है कि धान खरीद में पूरी तरह से सावधानी बरतें। जितना ज्यादा से ज्यादा धान क्रय केंद्र खोले जा सकते हैं, खोले जाएं। अन्नदाता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तक तीन लाख मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। धान, बाजरा, मक्का सभी फसलों का क्रय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हुए किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि यथाशीघ्र उनके बैंक खातों में अंतरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है।

रबी सीजन की फसलों की बुवाई से पहले जान लें ये बात, नहीं तो पछताओगे

सरकार द्वारा वर्ष २०२३-२४ हेतु रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नक्की किया गया है, जिसके अंतर्गत गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य २१२५ रूपये निर्धारित हुआ है। इसके अतिरिक्त सरसों, जौ, गेहूं, चना, मसूर एवं सनफ्लावर व रेपसीड का भी मूल्य नक्की किया गया है। किसानों को निर्धारित मूल्य से कम भाव नहीं दिया जायेगा।

बतादें कि रबी फसलों की बुवाई होना प्रारंभ हो चुकी है, इससे पूर्व ही केंद्र सरकार द्वारा इन फसलों की एमएसपी निर्धारित कर दी है। एमएसपी को ध्यान में रखकर अधिक मुनाफा देने वाली फसलों का चयन करें। मसूर, सरसों, गेहूं, जौ, चना, एवं रेपसीड तथा सूरजमुखी (कुसुम्भ) का रबी विपणन साल २०२३-२४ के लिए एमएसपी नक्की किया है।

बुवाई से पूर्व ज्ञात रहे कि आपको कौनसी फसल में अधिक मुनाफा होने सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा इस मामले में किसानों को पूर्ण ज्ञापन दिया गया है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य २१२५ रूपये प्रति क्विंटल, जौ का १७३५ रूपये प्रति क्विंटल, चने का ५३३५ रूपये प्रति क्विंटल, मसूर (लेन्टिल) का ६००० रूपये प्रति क्विंटल, सरसों एवं रेपसीड का ५४५० रूपये प्रति क्विंटल तथा सूरजमुखी (कुसुम्भ) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ५६५० रूपये प्रति क्विंटल नक्की हुआ है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही फसलों का भाव दिया जायेगा।

कैसे पहचाने मिलावटी खाद्य पदार्थों को

दिवाली के आते ही खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की शिकायत आना शुरू हो जाती है इसलिए राजस्थान सरकार ने 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' (Shuddh Ke Liye Yuddh Abhiyan) शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत जितने भी खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत आती है, जैसे की दाल, तेल, मसाले, घी एवं अनाज आदि, सभी की अच्छी तरह जाँच की जाएगी। हालाँकि जिला जाँच विभाग ने खाद्य उघोगों से कई हजार टन मिलावटी खाद्यान्न पदार्थों को पकड़ा है। ऐसे में किसी भी पदार्थ पर आँख बंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। त्योहारों पर मिलावट की ये खबरें अब बेहद आम बात हो गयी है, आये दिन किसी न किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट होने की खबर से उपभोक्ताओं के अंदर भय व्याप्त हो चुका है। राजस्थान सरकार का 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' लोगों को मिलावटी जहर खाने से बचाने में बेहद सहायक साबित होगा।

राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मोटे अनाजों की खरीद सुचारु रखी जाएगी

साथ ही, सरसों एवं रेपसीड समूह से संबंधित अन्य तिलहनों जैसे तोरिया का भाव रेपसीड एवं सरसों के साथ उनके सामान्य बाजार भाव अंतराल के आधार पर निर्धारित होंगे। अनाजों एवं मोटे अनाजों के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एवं अन्य नामित राज्य एजेंसियां किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी। राजस्थान सरकार केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से मोटे अनाजों की खरीदारी निरंतर रखेगी। साथ ही, खरीदी गई संपूर्ण माल्रा को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसए) के चलते वितरण करेगी। अनुदान सिर्फ एनएफएसए के अनुरूप लागू की गई माल्रा के लिए ही दी जाएगी।

तिलहन व दलहन इन एजेंसियों द्वारा निरंतर खरीदी जाएगी

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड), लघु कृषक-कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) एवं अन्य नामित केंद्रीय एजेंसियां दलहनों व तिलहनों की खरीद निरंतर रखेंगी। इसके अतिरिक्त ऐसे प्रचलनों में नोडल एजेंसियों के द्वारा नुकसान हो तो, उनकी सम्पूर्ण पूर्ति केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशानुसार की जाएगी। बतादें कि राज्य में रबी विपणन मौसम वर्ष २०२३ -२४ में एमएसपी खरीद हेतु खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को नोडल विभाग बना दिया है। राजस्थान राज्य के ३१९ केंद्रों पर १ नवंबर से उड़द, मूंग एवं सोयाबीन की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार खरीदना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही, मूंगफली की खरीदी १८ नवंबर से प्रारंभ हो जाएगी जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

किसानों को सस्ते दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इतना लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने जा रही है केंद्र सरकार।

सस्ते दर में किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का निर्णय लिया है। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रामागुंडम में आधारशिला रखने और 9500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे किसानों को उर्वरक खरीदने में कम रुपए लगेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार पिछले 8 वर्षों में किसानों को उर्वरक का लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं जिसका मंसूबा यह है कि किसानों को उच्च वैश्विक उर्वरक के लागत में मोच का सामना नहीं करना पड़े।

अगर यह 5 संयत्र चालू हो जाएंगे तो देश के बाहर से आने वाले यूरिया जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से चलकर भारत में आते हैं, उसमे कमी होगी, जिससे जो महत्वपूर्ण लागत है उसमें भी कमी आएगी और किसानों को और कम दाम में यूरिया आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार "भारत यूरिया"नाम के तहत यूरिया का एकल ब्रांड को आगे बढ़ाने की पेशकश हुई है जिससे आने वाले समय में बेहतर लाभ पूरे भारतवर्ष को मिलेगा।

अगर ऐसा होता है तो विशेषज्ञों का कहना है, कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन से भी आगे निकल जाएगा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी प्रथम स्थान पर अपना बाजार बुलंद करते हुए नजर आएगा।

मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा के शासन के दौरान बहुत सारे बुनियादी बदलाव आए हैं। सरकारी प्रक्रिया में सुधार और व्यापार को करने में आसानी के साथ-साथ कृषि जगत को सुदृढ़ करने पर बहुत सारे कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिस पर हमारी पहली नजर है।

₹2000 की यूरिया की बोरी अब मिलेंगे मात्र इतने रुपए में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यूरिया की बोरी की कीमत लगभग ₹2000 हैं। लेकिन हमने पिछले 8 सालों के शासन के दौरान जिस तरह से कार्य किए हैं, और कृषि के महत्व पर जिस तरह से हमने जोड़ दिया है, उससे ₹2000 की यूरिया की बोरी को माल्र अभी ₹270 में उपलब्ध कराया जा रहा है। आने वाले समय में अगर इस तरह से ही कार्य होते रहे तो यह दाम घटकर और नीचे आएगा और किसान आसानी से यूरिया प्राप्त कर पाएंगे।

उर्वरक उपलब्धता के सुधार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग पर लगातार कार्य किया जा रहा है। बंद पड़े 5 बड़े शहरों के खुलने से प्रतिवर्ष लगभग 700000 टन से ज्यादा यूरिया का उत्पादन होगा, पूरे भारतवर्ष में एक ब्रांड यानी भारत ब्रांड के नाम से उर्वरक उपलब्ध हो पाएगा। उर्वरक को सस्ता रखने के लिए 8 सालों में लगभग 10 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं, और इस साल अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है।

सरकार के लाख प्रयासों के बाद बाद भी पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि यूरिया खाद की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे किसानों को समय पर यूरिया खाद मिलने में परेशानी हो रही थी। यूरिया का कारोबार कालाबाजारी करके किसान द्वारा एक बोरी पर 500 से ₹550 प्रति बोरा की दर से कालाबाजारी की जा रही थी, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे थे और चौक चौराहे को जाम कर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार के द्वारा उर्वरक को बढ़ावा देने और कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कठिन से कठिन निर्णय भी लिए जा रहे हैं। जिससे आने वाले समय में किसानों को कम से कम दर में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा और सही समय पर किसानों को यूरिया मिल पाएगा जिससे किसान बेहतर रूप से खेती करने में सक्षम होंगे।

यह सरकार कर रही भूरा तना मधुआ कीटों से प्रभावित फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयास

बिहार के कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार द्वारा बताया गया है कि कृषि विभाग द्वारा भूरा तना मधुआ नामक कीट के प्रकोप से किसानों की धान की तैयार फसल की बर्बादी का आकलन हो रहा है। आकलन उपरांत विभाग के माध्यम से जरुरी कार्रवाई होगी। बिहार के अधिकतर किसान आज भी प्रकृति पर निर्भर हैं। उत्तरी बिहार में जहां बाढ़ के चलते फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मगध क्षेत्र में समय पर बरसात न होने पर किसानों को सुखाड़ का सामना करना पड़ता है।

बिहार सरकार के माध्यम से इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। साथ ही, मुआवजा के रूप में धनराशि भी किसानों को दी जा रही है। लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं के अलावा भूरा तना मधुआ कीट भी किसानों के लिए सिर दर्द बन गया है, क्योंकि यह एकत्रित होकर थोड़े समय में ही फसल को बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं। फिलहाल बिहार के किसानों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृषि मंत्रालय द्वारा स्वयं इसके नियंत्रण के लिए प्रयास किया गया है।

कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान पटना में कहा कि भूरा तना मधुआ कीट (बीपीएच – ब्राउन प्लांट हॉपर; brown plant hopper; या कत्थई फुदका) धान की फसल के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। खास कर इसके आक्रमण का प्रकोप गया, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, लखीसराय एवं औरंगाबाद सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा इससे किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाया गया है। पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक पदाधिकारियों की देखरेख में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

फसल संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रयास हो रहा है

कृषि मंत्री ने बताया है कि पौधा संरक्षण संभाग के माध्यम से भूरा तना मधुआ कीट के नियंत्रण हेतु निर्धारित कीटनाशी का इस्तेमाल कर किसानों द्वारा कटाई के लिये तैयार धान की फसल को हानि से बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। निर्धारित कीटनाशी प्रति एकड़ 225-250 लीटर पानी में मिला कर, छिड़काव तने की ओर करें व प्रभावित क्षेत्र से 10 फीट की दूरी तक चारों ओर छिड़काव करें। ध्यान रखें की छिड़काव के वक्त खेत में अत्यधिक जल-जमाव न हो। उन्होंने कहा है कि इन कीटों द्वारा धान के तनों से रस को चूसने के कारण फसल को भारी क्षति पहुंचती है। इन हल्के-भूरे रंग के कीटों का जीवन चक्र 20-25 दिनों तक का होता है। बड़े और छोटे दोनों प्रकार के कीट पौधों के तने के मुख्य हिस्से पर रहकर रस चूसते हैं। ज्यादा रस निकलने के कारण धान के पौधों में पीलापन आ जाता है, साथ ही जगह-जगह पर चटाईनुमा आकार सा हो जाता है, जिसे 'हॉपर बर्न' (hopper burn) नाम से जाना जाता है।

900 गावों को गोद ले भारत के कृषि विज्ञान केंद्र करेंगे पूसा डीकम्पोज़र व वर्मीकम्पोस्ट को प्रोत्साहित

देश में कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके; Krishi Vigyan Kendra – KVK) द्वारा माइक्रोबियल (सूक्ष्मजीव) आधारित कृषि अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्मीकम्पोस्टिंग (कृमि उर्वरक; केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट (Vermicompost)) को प्रदर्शित एवं इसको प्रोत्साहन देने हेतु ९०० गांवों को गोद लिया है। गत एक महीने में स्वछता अभियान के चलते २२ हजार से ज्यादा किसानों के समक्ष कृषि अवशेषों (पराली आदि) के सूक्ष्मजीव आधारित डीकंपोजर एवं कृषि अवशेषों व अन्य जैविक कचरे को कृमि उर्वरक में परिवर्तन से संबंधित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। किसानों के साथ – साथ ३००० स्कूली बच्चों में वर्मी कम्पोस्टिंग (vermicomposting) के सम्बंध में जागरूकता पैदा की गई।

वर्मी कम्पोस्ट क्या होता है ?

मृदा के स्वास्थ्य एवं फसल की पैदावार में सुधार के लिए बेहतर रूप से अपघटन के उपरांत प्रयोग किए जाने पर फसल अवशेष कीमती जैविक पदार्थ हैं। ज्यादातर फसल अवशेषों की प्राकृतिक उर्वरक बनने की प्रक्रिया की दीर्घ अवधि की वजह से किसान इसे जलाकर नष्ट करने का कार्य करते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक कीमती संपत्ति की बर्बादी के अतिरिक्त इससे पर्यावरण भी दूषित होता है। कंपोस्टिंग तकनीकें "पूसा डीकंपोजर" (PUSA Decomposer) जैसे कुशल सूक्ष्मजीवी अपघटक का प्रयोग करके अपघटन प्रक्रिया को तीव्र करती हैं। जिससे कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक उर्वरक हासिल होती है। अवशेषों की राख के स्थान पर इससे बने जैविक उर्वरक मिट्टी में कार्बनिक कार्बन एवं अन्य जरूरी पोषक तत्वों को पौधों के लिए प्रदान करवाता है। साथ ही, मिट्टी में सूक्ष्मजीव आधारित गतिविधि को बढ़ावा देता है। फसल के अवशेष एवं अन्य कृषि अपशिष्ट जैसे कि गाय के गोबर एवं रसोई के कचरे आदि के आंशिक रूप से सड़ने के उपरांत इसमें केंचुओं की बेहतर प्रजातियों का उपयोग करके इन्हें कृमि उर्वरक में परिवर्तित किया जा सकता है। कृमि उर्वरक पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की भरपाई करता है, मृदा के गुणकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देता है, एवं मिट्टी के स्वास्थ्य में बेहतरी करता है। साथ ही, इसके अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट को बाजार में बेचकर भी मुनाफा किया जा सकता है।

जिससे कम समय में अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक उर्वरक हासिल होती है। अवशेषों की राख के स्थान पर इससे बने जैविक उर्वरक मिट्टी में कार्बनिक कार्बन एवं अन्य जरूरी पोषक तत्वों को पौधों के लिए प्रदान करवाता है। साथ ही, मिट्टी में सूक्ष्मजीव आधारित गतिविधि को बढ़ावा देता है। फसल के अवशेष एवं अन्य कृषि अपशिष्ट जैसे कि गाय के गोबर एवं रसोई के कचरे आदि के आंशिक रूप से सड़ने के उपरांत इसमें केंचुओं की बेहतर प्रजातियों का उपयोग करके इन्हें कृमि उर्वरक में परिवर्तित किया जा सकता है। कृमि उर्वरक पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की भरपाई करता है, मृदा के गुणकारी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देता है, एवं मिट्टी के स्वास्थ्य में बेहतरी करता है। साथ ही, इसके अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट को बाजार में बेचकर भी मुनाफा किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में किसानों को गुरुकुल में दिया जायेगा प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से करने का प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती यानी नैचुरल फार्मिंग (Natural Farming) करने की बेहतरीन कलाएं सिखाई जायेंगी, जिसमें वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील किसान भी बेहतरीन ढंग से दिशा निर्देशन के साथ गुरुकुल की ओर चलेंगे। भारत में पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी आगे है। राज्य सरकार रबी सीजन के दौरान एक लाख हेक्टेयर भूमि में गौ सम्बंधित खेती करने का संकल्प किया है, जिसको पूर्ण करने हेतु गुरुकुल के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती करने का ज्ञान दिया जायेगा।

गुरुकुल में होगा प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा गौ सम्बंधित खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन भी हो चुका है। इस सन्दर्भ में आगे बढ़ते हुए अब किसानों को गुरुकुलों की सहायता द्वारा ट्रेनिंग देने का भी संकल्प नक्की हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सम्बोधन के दौरान कहा है कि किसान प्राकृतिक खेती के जरिये कम खर्च करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी बेहतर सलाह एवं जानकारी देने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सहायता मिलेगी, जिससे किसान अत्यधिक लागत लगाने की समस्या से छुटकारा पा सके, साथ ही आय को दोगुनी कर सके।

उत्तर प्रदेश के एक लाख हेक्टेयर भूमि में होगी प्राकृतिक खेती

रबी सीजन के दौरान उत्तर प्रदेश में गौ सम्बंधित १ लाख हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती करने का संकल्प किया गया है। प्राकृतिक खेती को अच्छे तरीके व तकनीक से जानने के लिए कुछ समय पहले यूपी के कृषि मंत्री, कृषि से सम्बंधित समस्त बड़े जिम्मेदार अधिकारियों एवं प्रगतिशील किसानों द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जनपद का भ्रमण किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य में मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (Mission on Natural Farming) के चलते किसानों को एकत्रित किया जा रहा है।

गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर प्रदेश राज्य में गौ आधारित खेती करने के लिए २३ जनपदों के ३९ ब्लाकों में २३,५१० हेक्टेयर में ४७० क्लस्टर स्थापित किए जायेंगे। इसी सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के ४ कृषि विश्वविद्यालयों को भी लैब निर्माण करने हेतु आदेश के साथ साथ प्राकृतिक खेती करने का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। 89 कृषि विज्ञान केंद्रों के सहयोग से यह कृषि विश्वविद्यालय सर्टिफिकेशन एवं प्राकृतिक खेती से सम्बंधित उत्पादों के विपणन में भी सहायता करेंगे। साथ ही समस्त मंडियों में भी प्राकृतिक उत्पादों को विशेष स्थान दिया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा बुंदेलखंड की भूमि पर प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की भी पहल शुरू की गयी है। बुंदेलखंड में १२००० हेक्टेयर में खेती के लिए 235 क्लस्टर स्थापित होंगे जिसमें ७ जनपदों के ४७ ब्लॉक में सम्मिलित हैं। प्राकृतिक खेती के लिए सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी।

खाद के दाम हुए कम, फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी को मिली मंजूरी

देश में रबी की फसलों की बुवाई का समय चल रहा है। इस दौरान किसानों के द्वारा खाद की भरपूर मांग की जा रही है। देश के लगभग सभी राज्यों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, जिससे किसानों को इस बार आसानी के खाद उपलब्ध कारवाई जा रही है।

रबी की फसलों की बुवाई के दौरान किसानों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 2 नवंबर को केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि पोषक तत्व आधारित नए उर्वरकों को किसानों को वितरित किया जाएगा। ये उर्वरक किसानों को सस्ती और रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ने फर्टिलाइजर (Fertilizer) पर 51875 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति दी है। यह सब्सिडी किसानों के लिए 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए स्वीकृत की गई है।

इस तरह से खाद के दामों में की गई है कटौती

केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खाद के नए रेट जारी कर दिये हैं। इस दौरान सरकार ने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश समेत कई न्यूट्रिएंड बेस्ड उर्वरकों की दामों में कटौती की है। अगर नए दामों की बात करें तो अब नाइट्रोजन 98.02 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेंचा जाएगा। साथ अब फॉस्फोरस किसानों को 66.93 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में मिलेगा। इसके साथ ही पोटाश की नई कीमत 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है तथा अब सल्फर खेती करने के लिए 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा सकेगा।

सस्ते उर्वरक उपलब्ध करवाने पर किसानों को यह होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बताया कि देश के किसानों को अब रियायती दामों में उर्वरक उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे खेती की लागत में कमी आएगी। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही फर्टिलाइजर निर्माता कंपनियों को भी इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

सरकार के इस फैसले की जानकारी उर्वरक मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से साझा की। ट्विटर में उर्वरक मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर के आयात के मूल्य के आधार पर ही किसानों को सस्ती और रियायती दरों पर उर्वरक उपलब्ध करवाए जाएंगे। उर्वरकों के मूल्य पूरी तरह से फर्टिलाइजर के आयात मूल्य पर निर्भर करेंगे।

प्याज और टमाटर के उत्पादन में 5% कमी और बागवानी में 10 गुना बढ़ोत्तरी, सरकारी आंकड़ा जारी

वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी

भारत में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा हर साल अग्रिम अनुमान जारी किया जाता है, जिसमें फसलों में हो रहे वृद्धि या गिरावट के बारे में बताया जाता है। बता दे कि केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा साल 2021-22 के लिए भी तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है, जिसमें बागवानी, दलहन, तिलहन एवं खाद्यान्न कृषि उत्पादन का आंकड़ा जारी किया गया है।

इस अनुमान के मुताबिक टमाटर का उत्पादन लगभग 5 फीसदी तक कम हुआ है, वहीं आपको बता दें कि पिछले साल टमाटर का पैदावार लगभग सवा दो करोड़ टन थी, वहीं इस साल दो करोड़ के आसपास में ही रह गई।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी इस अग्रिम अनुमान के अनुसार सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि कई अन्य फसलों में काफी गिरावट हुई है, जिसका मुख्य कारण मौसम में बदलाव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस साल होने वाले आलू के उत्पादन में लगभग 5% की कमी रहने की उम्मीद है। यह उम्मीद मौसम में हो रहे बदलाव के कारण जताया जा रहा है, पिछले साल के आंकड़े के अनुसार आलू का उत्पादन 5 करोड़ 61.7 लाख टन था। वहीं इस साल आलू का उत्पादन 5 करोड़ 33.9 लाख टन के आसपास ही रहेगा, इस जारी तीसरा अग्रिम अनुमान में बताया जा रहा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बार धान दलहन और तिलहन के उपज के रंगों में काफी वृद्धि हुई है, वही टमाटर फल व आलू के उत्पादन में लगभग 4 से 5% का गिरावट आया है।

प्याज के उत्पादन में होगा बढ़ोतरी

2021-22 के आंकड़ों के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण प्याज का उत्पादन काफी प्रभावित रहेगा, इसके बावजूद भी प्याज के उत्पादन में पिछले बार की तुलना में इस बार काफी बढ़ोत्तरी का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे यह जाहिर होता है कि पिछले साल प्याज का उत्पादन काफी कम रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस बार प्याज का उत्पादन लगभग तीन करोड़ 12.7 लाख टन की संभावना है, वहीं पिछले साल देखा जाए तो प्याज का उत्पादन लगभग दो करोड़ 66.4 लाख टन था।

गेहूं के उत्पादन से देश पर कोई प्रभाव नहीं

कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी इस अग्रिम अनुमान में अभी देखा जा रहा है कि प्रमुख फसलों के अलावा इस बार बागवानी वाले फसल में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक इस साल प्रमुख खाद्यान्न में जैसे गेहूं के उत्पादन को लेकर कुछ पूर्वानुमान खास अच्छा नहीं लगाया जा रहा है, संभावना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन 31 लाख टन कम होकर 10.64 करोड़ टन रहने की संभावना है।

लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो वह पिछले साल के मुताबिक 37.7 लाख टन ज्यादा है। आपको बता दें कि इस जारी अग्रिम अनुमान में 31.45 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का पूर्वानुमान है, आपको यह भी बता दें कि इतना उत्पादन के साथ भी गेहूं का स्टॉक देश में अच्छा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टॉप पर फल एवम् सब्जी की खेती

देशभर में सरकार बागवानी फसल की खेती को बढ़ावा देने में काफी तत्पर दिख रहा है, जिसका परिणाम भी दिखना शुरू हो गया है। सरकार की तत्परता के साथ-साथ किसानों की तत्परता भी सब्जी की खेती की तरफ काफी बढ़ी है, जिसके कारण इस साल जारी तीसरे अग्रिम अनुमान में सब्जियों का उत्पादन 20 करोड़ 38.4 टन रहने का अनुमान है। यह पिछले साल दो करोड़ 4.5 लाख तक ही सीमित था। पूरा हिसाब देखा जाए तो सब्जी की खेती में लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, जिसके लिए सरकार और किसान दोनों को धन्यवाद देना होगा। गौरतलब हो कि सब्जी की खेती के लिए सरकार भी काफी सब्सिडी एवं ऋण व्यवस्था की हुई है।

इस अग्रिम अनुमान में यह भी देखा जा रहा है कि पिछले साल फलों का उत्पादन के मुताबिक इस साल 10 करोड़ 72.4 लाख तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। जानकारी के अनुसार पिछले साल फलों का उत्पादन 10 करोड़ 24.8 लाख दर्ज किया गया था।

केंद्र ने दिया किसानों को फसल के उचित मूल्य का उपहार

आज सरकार ने किसानों को दिवाली का गिफ्ट देते हुए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के साथ साझा की। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से लेकर 9 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है। नई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी जारी कर दिया गया है।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि गेहूं की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है, जिसके बाद अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार से जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 100 रुपये की वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद अब जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

इन फसलों के साथ ही चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 5335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। चौथी फसल है मसूर, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

इस लिस्ट में पांचवां नाम है सरसों का, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से सरसों 5050 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 5450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा। सरसों के साथ ही सूरजमुखी के दाम में 209 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। अब सूरजमुखी 5,441 रुपये प्रति क्विंटल की जगह पर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा।

औषधीय खेती

पत्थर ही नहीं, किसानों की दुर्दशा भी चाट जाएगी इसकी खेती

आज हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी खेती अगर किसान करें तो उनके जीवन की भी बहुत सारी समस्याओं, ख़ास कर उनकी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को चाट चाट कर ख़त्म कर देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पत्थरचट्टा की। पत्थरचट्टा (पथरचटा या पथरचट्टा (वानस्पतिक नाम – Kalanchoe pinnata या Bryophyllum calycinum या Bryophyllum pinnatum; Pattharchatta)) एक ऐसी औषधि है, जो न सिर्फ मानव स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, यह इतना मुनाफ़ा दे कर जाती है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। इस औषधि की खेती से किसान साल का लाखों रूपये कमा सकते हैं।

पत्थरचट्टा को हम किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरोना काल में जैसे-जैसे आयुर्वेद के महत्व से लोग परिचित हुए, वैसे वैसे पत्थरचट्टा की मांग भी बढ़ने लगी है। ऐसे में किसान इसकी खेती कर के बेहतर मुनाफ़ा कमा सकते हैं।

पत्थरचट्टा की सबसे ख़ास बात यह है, कि इसकी खेती के लिए किसानों को बीज खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। इसकी खेती के लिए बस इसके पत्ते का इस्तेमाल कर के उगाया जा सकता है। यही कारण है कि इसकी खेती बहुत महँगा सौदा भी नहीं रह जाती, इस औषधि पौधे में उगने वाले फूल औषधीय गुण से भरपूर होते हैं।

पत्थरचट्टा की खेती के लिए नम मिट्टी चाहिए, किसान 60 प्रतिशत दोमट मिट्टी, 20 प्रतिशत कोको पीट और 20 प्रतिशत रेत के साथ मिट्टी तैयार कर लें। फिर इस मिट्टी में पत्थरचट्टा लगा सकते हैं। इसकी एक ख़ास बात यह है कि एक पूरी तरह से विकसित पत्थरचट्टा के पत्ते खुद ही खेत में गिरा दिये जाते हैं, जिससे कि आगे वही पत्ते फिर से एक नया पौधा बन जाते हैं, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम।

पत्थरचट्टा को रोज सूर्य प्रकाश की जरूरत होती है। हालांकि, 5 घंटे की धुप भी इसके लिए काफी है। हां, इन्हें अत्याधिक ठण्ड से बचाने की जरूरत होती है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पत्थरचट्टा को अगर फिल्टर पानी मिले तो इसका और अधिक फ़ायदा पौधे के विकास में मिलता है। एक्सपर्ट्स पत्थरचट्टा के लिए हर दो महीने के बाद आधा चम्मच बोन मील देने की भी बात कहते हैं। पत्थरचट्टा में अगर फफूंद लग जाए तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का छिड़काव करना चाहिए।

रामबाण पत्थरचट्टा

पत्थरचट्टा के पत्तों का स्वाद खाने में खट्टा होता है। यह इंसान के मूत्र विकार, सर दर्द, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारियों में कारगर माना जाता है। माना जाता है कि पत्थरचट्टा के इस्तेमाल से (डॉक्टर की देखरेख में) किडनी स्टोन को भी बाहर निकालने में सहायता मिलती है।

आज लगाएं यह पौधा, बारह साल में बन जाएंगे करोड़पति

भारत किसानों का देश है, लेकिन किसानों की हालत को ले कर दशकों से चर्चा चल रही है कि इसे कैसे सुधारा जाए। दूसरी तरफ, किसान भी पारंपरिक खेती से अन्य प्रयोग करने से कतराते हैं। इसकी भी अपनी वजह हैं। लेकिन, किसानों की आर्थिक हालात बदले, इसके लिए आवश्यक है कि किसान पारंपरिक खेती के साथ ही अन्य किस्म की खेती भी करें। आज हम आपको ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आज किसी किसान ने लगा लिया, तो 12 साल बाद वह निश्चित ही करोड़पति हो जाएगा। तो हम बता दें कि उस पेड़ का नाम है, सफेद चंदन (chandan; sandalwood; Santalum album) और सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर भारत के किसान भी सफेद चंदन के पेड़ (safed chandan; white sandalwood) अपने खेतों में लगा सकते हैं।

लाल चन्दन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि वह बहुत महँगा होता है। हाल ही में आई एक दक्षिण भारतीय फिल्म में भी लाल चंदन की चर्चा है। लेकिन हम बता दें कि सफेद चंदन की लकड़ी की कीमत भी कोइ कम नहीं होती और इसके इस्तेमाल भी बहुतायत में होते हैं। हजारों रूपये किलो बिकने वाला सफेद चन्दन का एक पेड़ लाखों रूपये दे कर जाता है।

एक सवाल यह मन में आता है कि क्या सफेद चंदन की खेती नार्थ इंडिया के किसान भी कर सकते हैं ? तो हम बता दें कि इसकी खेती वैसे तो पूरे भारत में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 8.5 के बीच सबसे अच्छा माना गया है। जहां सफेद चंदन के पेड़ लगाए गए हो वहाँ जल जमाव नहीं होना चाहिए। हां, इसे बर्फ से भी बचाया जाना जरूरी है।

गौरतलब है कि सफेद चंदन के एक पेड़ को विकसित होने में 12 से 15 साल का समय लग सकता है। अगर किसी किसान के पास एक एकड़ जमीन है तो उसमें वह सफेद चंदन के 400 पौधे लगा सकता है। हर दो पेड़ के बीच 12 फीट की जगह खाली होनी चाहिए। यानी, बीच की खाली जमीन में किसान सब्जी की भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान चाहें तो चंदन के खेत में हरी सब्जी की भी खेती कर सकते हैं। 12 साल बाद इन चार सौ पेड़ों की कीमत इतनी होगी कि किसान निश्चित ही करोड़पति बन जाएंगे। तो देर किस बात की है, आज ही सफेद चंदन के पेड़ अपनी जमीन में लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दें।

इन पौधों के डर से मच्छर भागें घर से

फिलहाल मच्छर जनित रोग डेंगू- मलेरिया का जोर है। मलेरिया व डेंगू की वजह से उत्तर प्रदेश राज्य का जनपद हाथरस के बहुत सारे लोग भी चपेट में हैं। मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने घरों में विभिन्न प्रकार के मॉस्किटो किलर का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल, इनसे निकलने वाला धुआं व अन्य रसायन सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित होते हैं। लेकिन इस परेशानी से बचने के लिए उद्यान विभाग घर में कुछ खास पौधे यानी की नैचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाने की सलाह दे रहा है। इनकी सुगंध से मच्छर पास नहीं आते और ये काफी अच्छे भी होते हैं। इन पौधों के संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें।

लेमन ग्रास : लेमन ग्रास की सहायता से मच्छर, मकोड़े, कीड़े से बचाया जा सकता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य शारीरिक रोगों से लड़ने में भी अहम् भूमिका निभाती है। लेमन ग्रास को बगीचे व गमले में उगाया जा सकता है। लेमन ग्रास की सुगंध से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं इसलिए यह डेंगू और मलेरिया से बचाने के लिए बेहद जरुरी है। लेमन ग्रास का उपयोग लेमन टी के रूप में भी किया जाता है।

गेंदे का पौधा: गेंदे का पौधा एक नैचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स पौधे (Natural mosquito repellent plants) के साथ ही बेहतरीन फूल भी है। इसमें कई ऐसे गुण विद्यमान हैं, जो इसको एक अलग ही पहचान देते हैं। इस पौधे की पंखुड़ियों एवं फूल से एक अच्छी महक आती है, जो मच्छरों के लिए जानलेवा होती है। इसी कारण से, मच्छर इसके समीप आने से भयभीत होते हैं। मच्छरों से निपटने के लिए गेंदे के पौधों को अपने घर में एवं बालकनी में लगायें, इससे मच्छर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें: गेंदा के फूल की खेती की सम्पूर्ण जानकारी

पुदीने का पौधा: पुदीने की खुशबू मच्छरों के प्रकोप से बचाने में सहायक साबित होती है। इसकी पत्तियों से उत्पन्न महक विभिन्न प्रकार के कीड़ों से बचाती है। पुदीने के उत्पादन को गमलों की सहायता से पैदा किया जा सकता है, एवं इसके लिए मिट्टी में नमी व अच्छे जल की निकासी होती है। इसे घर में सहजता से लगाया जा सकता है।

लैवेंडर का पौधा: मच्छरों को दूर भगाने के लिए जिन मॉस्किटो रिपेलेंट्स का प्रयोग किया जाता है, उनमें लैवेंडर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। लैवेंडर का पौधा मच्छरों से निपटने के लिए बेहद सहायक होता है साथ ही इसको घर पे आसानी से उगाया जा सकता है।

तुलसी का पौधा: तुलसी के पौधे का हिंदू धर्म में बेहद पौराणिक महत्त्व है। तुलसी के पौधे में विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण विघमान होते हैं। बतादें कि तुलसी के पत्तों का अर्क जुकाम, खांसी एवं सर्दी से राहत दिलाने में बेहद सहायक होता है। साथ ही, तुलसी का पौधा मच्छरों से बचाने में बेहद काम आता है। इसे सहजता से घर में उगाया जा सकता है।

रोजमेरी का पौधा: रोजमेरी का पौधा सुंदर पुष्पों सहित दिखने में बेहद आश्चर्यजनक होता है। रोजमेरी के पौधे को लोग घर के सौंदर्यीकरण के लिए उपयोग करते हैं। बतादें कि रोजमेरी का पौधा नैचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स माना जाता है। यह मच्छरों से बचाने में काफी सहायक साबित होता है।

साथ ही, जिला उद्यान अधिकारी अनीता यादव का कहना है कि इस बार २० हेक्टेयर में तुलसी की पैदावार का संकल्प विभाग को दिया गया गया है। इसमें 14 हेक्टेयर लक्ष्य हासिल हो चूका है। उघान विभाग पर जाकर तुलसी के पौधे खरीदने की चाह रखने वाले किसान तुलसी के बीज प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनपदों में डेंगू के मामलों में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी की जा रही है। अब तक जनपद में २२ मामले सामने आए हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी निरंतर नियंत्रण कर रहा है। शहर, गांव, कस्बा एवं मौहल्ला में फॉग उपकरण द्वारा कीटनाशक छिड़काव हो रहा है। साथ ही, डॉक्टर्स की टोली भी दवाई वितरण का कार्य कर रहीं हैं।

पशुपालन-पशुचारा

इस प्रकार बचायें अपने पशुओं को आने वाली शीत लहर से

पराली जलने से देश का बड़ा इलाका प्रदूषित हो रहा है। इसका दुष्प्रभाव लोगों की सेहत पर पड़ने के साथ ही, दुधारु पशुओं को भी इससे कई हानि हैं। देशभर में अधिकतर पशु लंपी रोग से प्रभावित हैं। शीघ्र ही सर्दियां भी आने वाली हैं, ऐसे में पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनकी बेहतर देखभाल भी आवश्यक है। सर्दियों के दिनों में ठंड के कारण ज्यादातर पशुओं को बुखार, झंझनाहट एवं कुछ केसों में मवेशियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस प्रकार की समस्त समस्याओं से पशुओं के संरक्षण के लिए किसानों एवं पशुपालकों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

पशुओं को ठंड से बचाने हेतु इन तरीकों को अपनायें

आमतौर पर शीत लहर के चलते पशुओं की हड्डियों में कंपकंपाहट एवं टांगों में गलन होने लगती है, इससे पशुओं को बचाने के लिए जूट का बोरा पहना सकते हैं। इससे पशुओं में गर्मी बनी रहेगी।

पशुओं की बेहतर रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए हरा चारा एवं सूखा चारा १:३ के अनुपात में मिलाकर खिलाना बेहद आवश्यक है।

वक्त-वक्त पर पशुओं को गर्म पानी पिलायें व दलिया अथवा चरी उपयुक्त मात्रा में खिलायें।

शीत लहर व ठंडी हवाओं से संरक्षण हेतु पशुओं को खुले में रखने की अपेक्षा छप्पर अथवा शेड का प्रयोग करें।

सर्दियों में पशुओं को हानिकारक विषाणु से बचाने के लिए धूप में टहलाना आवश्यक है।

लंपी का कहर पूर्ण रूप से रुका नहीं है, इसी वजह से समस्त दुधारु मवेशियों का टीकाकरण अति आवश्यक है।
पशुओं के आस पास साफ सफाई रखें, सर्दियों के समय विभिन्न कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो मवेशियों को बीमार कर देते हैं।

तबेले, बिछावन और कपड़े को बेहतर ढंग से सूखाने के उपरांत ही प्रयोग करें। थोड़ी सी नमी होने पर पशुओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

पशुओं को चिकने फर्श की बजाय बोरा या बिछावन पर बैठाने की व्यवस्था करें।

पशुओं को सरसों के तेल के साथ अच्छा आहार दें एवं खल, गुड़ के साथ अन्य पौष्टिक व बेहतर आहार खिलायें।

लंपी का कहर पूर्ण रूप से रुका नहीं है, इसी वजह से समस्त दुधारु मवेशियों का टीकाकरण अति आवश्यक है।

सर्दियों में पशुओं को पाचन क्रिया खराब होने से दस्त हो जाते हैं, ऐसे में शीघ्रता बरतते हुए पशु चिकित्सतक से सलाह लें। सर्दी के मौसम में पशुओं को विभिन्न रोगों से ग्रसित होने का खतरा है। खुरपका मुंहपका रोग, निमोनिया, ज़ुकाम एवं अन्य रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में पशु विशेषज्ञ की सलाह अनुसार रोग प्रतिरोधक टीकाकरण करना अति आवश्यक है।

कड़कनाथ पालें, लाखों में खेलें

कड़कनाथ मुर्गी पालन- इस दौर में कड़कनाथ (Kadaknath, also called Kali Masi) पालना आसान हो गया है। आप कड़कनाथ पाल कर अपनी आर्थिक हालत सुधार सकते हैं, महीने में हजारों कमा सकते हैं। कहते हैं, मूंछें हों तो नत्थूलाल की तरह वरना ना हो। इसे थोड़ा बदल लें तो कह सकते हैं कि मुर्गा खाना है, तो कड़कनाथ खाओ, वरना ना खाओ।

दरअसल, कड़कनाथ ने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया है। यह मुर्गे की एक ऐसी प्रजाति है, जिसने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल कर रख दिया है। इसकी कीमत तो ज्यादा है ही, पर जो स्वाद है, उसका क्या कहना। आप कड़कनाथ का मीट खाएं और बकरे का मटन, मुकाबला टक्कर का रहेगा।

कई रोगों में लाभकारी

कड़कनाथ का महत्व इसलिए ज्यादा हो चला है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने भी इसके मीट को अप्रूव किया है। कहा जाता है, कि अगर आपको हाई बीपी है, शुगर है, कमजोरी है और मन मिचलाता है, तो कड़कनाथ का मीट आपको फायदा करेगा। ऐसा कई लोगों का कहना है, कि कड़कनाथ का मीट खाने के बाद उनका बीपी, शुगर आदि कंट्रोल में रहता है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो वही बता सकते हैं जो इसे खाते हैं। लेकिन, इसकी बढ़ती डिमांड यही इंगित करती है कि मुर्गे में दम है।

धोनी भी पाल रहे हैं कड़कनाथ

मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने फार्म हाउस में कड़कनाथ रखा है। पहले 100 चूजे लाए गए थे, अब इनकी संख्या सैकड़ों में हो गई है। कड़कनाथ का स्वाद ऐसा है, कि धोनी के फार्महाउस पर लोग लाइन लगाए रहते हैं कड़कनाथ के लिए और उन्हें पता चलता है माल खत्म हो गया है। दरअसल, इसके मीट का टेस्ट ही ऐसा है।

रेट थोड़ा ज्यादा है

कड़कनाथ का रेट थोड़ा ज्यादा है, यह प्रति मुर्गा 1000 से 1600 रुपये तक बिकता है। अमूमन एक मुर्गा 900 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक का होता है। उसी के हिसाब से इसका रेट वैरी करता है, आम तौर पर अगर आप देसी मुर्गा भी खाते हैं, तो उसका रेट 400 से 500 रुपये प्रति किलो है। वैसे, कॉकरेल आपको 300 रुपये प्रति किलो भी मिल जाएगा और बॉयलर 140 से 150 रुपये प्रति किलो पर, जो टेस्ट कड़कनाथ का है, उसका कोई जवाब नहीं।

कैसे पहचानें कड़कनाथ को

कड़कनाथ का खून, मीट सब काला होता है, इसकी ब्रीड पूरी तरह काली है। अगर कोई कड़कनाथ कह कर आपको लाल खून वाला मुर्गा दे रहा है तो सतर्क रहें।

कैसे करें कड़कनाथ का पालन

कड़कनाथ को पालना थोड़ा कठिन है, पहले तो आप मन बना लें कि कड़कनाथ ही पालना है। जब मन बन जाए तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहां इसके चूजे आपको ठीक रेट पर मिल जाएंगे। चूजों को कैसे 30 दिनों तक रखना है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। उसे बहुत ध्यान से देखें फिर, चूजा लाने के पहले ट्रेनिंग में बताए गए तरीके से ही आप पोल्ट्री फार्म बनाएं।
ध्यान रखें, कड़कनाथ की ब्रीड को खुला पसंद है, इसलिए अगर आप ठीक-ठाक जमीन वाले हैं, आपके पास खुली जमीन है तो उसे ही इस्तेमाल करें। शुरुआती निवेश अगर आप 50000 रुपये से भी करते हैं, तो काम ठीक-ठाक चल निकलेगा। इसमें चूजों का दाना-पानी आ जाएगा, बढ़ते वक्त के साथ आपको ज्यादा निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत कम इंट्रेस्ट रेट पर आपको आसानी से मुर्गापालन के लिए कोई भी बैंक लोन दे देगी।
विभिन्न राज्य सरकारें मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की हैं। इससे किसानों के द्वारा स्थानीय स्तर पर मुर्गी पालन (पोल्ट्री फार्मिंग, Poultry farming)या कुक्कुट पालन (kukkut paalan) का व्यवसाय पिछले एक दशक में काफी तेजी से बढ़ा है।

मुर्गी पालन की जगह कीजिये इस पक्षी का पालन और पाएं बंपर मुनाफा

तीतर पक्षी को पालें और पाएं कम लागत में बंपर मुनाफा

मुर्गी पालन और बत्तख पालन के बारे में हमने बहुत पहले से ही कई तरह की चीजें सुनी हैं और यह दोनों ही व्यवसाय प्रचलन में रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने तीतर पालन के बारे में सुना है?

जी हां वही तीतर (Teetar; Grey Partridge) जिसे आप बचपन में तीतर या फिर कभी कभी बटेर कहकर बुलाते थे, और साथ ही तीतर के नाम पर बचपन में हम सब ने कई मुहावरे सुने हैं, 'आधा तीतर-आधा बटेर ', तीतर लड़ाना ', तीतर बाज़ होना और ना जाने क्या-क्या, उस समय बड़े आश्चर्य से सोचते थे, ये तीतर किस बला का नाम है।

आज हम आपको बताने वाले हैं कि तीतर केवल मुहावरों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी आपके बहुत फायदे का हो सकता है। उस समय हो सकता है कि आपने इस पक्षी के बारे में ज्यादा सोच विचार करने के बारे में ना सोचा हो और ना ही इसके फायदों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी रखी हो। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि कबूतर जैसा दिखने वाला ये पक्षी बाकि सभी पक्षियों से बेहद अलग है और आपके लिए बहुत फायदेमंद भी है।

तीतर पक्षी का रंग भूरा काला और लाल होता है और मादा और नर दोनों ही पक्षियों की बनावट और आकार में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तीतर में नर और मादा दोनों ही व्यवसाय के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जहां पर मादा आपको बहुत ही उत्तम क्वालिटी के अंडे और चूजे दे सकती है, वहीं पर नर तीतर का मांस आजकल बाजार में बहुत प्रचलन में है।

अगर तीतर पक्षी के थोड़े से इतिहास के बारे में बात करें तो विश्व भर में तीतर के लगभग 156 किस्म देखने को मिलते हैं, जिसमें से 46 तरीके के तीतर भारत में देखने को मिल जाते हैं।

तीतर पक्षी की एक खासियत है कि वो अपना घोंसला जमीन पर ही बनाता है और उसे जंगल, झाड़ी और खेतों में रहना पसंद है। यही कारण भी है कि खेतों में कीटनाशक आदि के इस्तेमाल और बहुत ज्यादा शिकार के कारण ये पक्षी विलुप्त होता जा रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकार ने इसके शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया है इसलिए ही अगर आप तीतर का पालन करना चाहते हैं तो आपको बाकायदा सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है।

आपको लग रहा होगा कि तीतर पर इतनी जानकारी ले कर हमें क्या फायदा होने वाला है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप एक नए बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं और आप यह बिज़नेस अगर कम लागत लगाकर करना चाहते हैं, तो आपको ये सब जानकारी होना आवश्यक है।

साथ ही आप अगर मुर्गी और बत्तख पालन से हटकर कुछ करना चाहते हैं तो भी तीतर पालन आपके लिए एकदम सटीक बिज़नेस है। आज के समय में तेज़ी से ये बिज़नेस लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और आप इसे बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो शुरूआत 5-6 तीतर पाल कर ही कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं कि कैसे आप यह बिज़नेस कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं।

कैसे करें व्यावसायिक पालन:

बाकि पक्षी पालन की तरह ही इसके लिए आपको एक जगह लेकर सेटअप करना आवश्यक है। आप इसके लिए जाल बना सकते हैं और उसमें इन पक्षियों को रख सकते हैं। इसके अलावा तीतर को पालते समय एक बात जो ध्यान में रखनी बेहद ज़रूरी है, वो है इनकी फीडिंग मतलब कि इसके खानपान की। इनके भोजन का हमें खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसी आधार पर ही मादा अंडे भी देती है। लगभग 35-40 दिन में मादा अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है और ये लगभग 10-12 अंडे एक साथ दे सकती है। अगर मादा तीतर स्वस्थ है, तो अंडे और आगे चल कर चूजे भी स्वस्थ रहते हैं।

तीतर के आहार में हमें एक बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि, गर्मियों में इन्हें चिकन या बत्तख की अपेक्षा ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही आप सूखे दाने के साथ-साथ इन्हें कुछ ना कुछ हरे पदार्थ भी खिला सकते हैं। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दिन में तीन से चार बार या फिर कम से कम दो से तीन बार इन्हें दाना जरूर खिलाएं।

तीतर के अंडे हैं पोषण से भरपूर:

जैसा कि हमने बताया कि तीतर के लिए भोजन का बहुत महत्व है इसलिए ही अगर तीतर को सही तरह से आहार दिया जाए तो अंडों के उत्पादन और क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अंडे बाकि पक्षियों के मुकाबले ज्यादा सेहतमंद माने जाते हैं और इसका कारण है कि तीतर के अंडों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल काफी मात्रा में पाये जाते हैं। प्रति ग्राम जर्दी में 15-23 मिलीग्राम तक कोलेस्ट्रॉल होता है।

मांस से भी कर सकते हैं कमाई:

हो सकता है, आपने कभी तीतर के मांस के बारे में ना सुना हो लेकिन आप तीतर के मांस से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तीतर के मांस में चिकन के मुकाबले ज्यादा पोषण पाया जाता है क्योंकि इसका मांस चिकन के मुकाबले पतला होता है। इसमें प्रोटीन और बाकी सभी मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो आजकल हेल्थ के लिए सजग लोगों की मांग है, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम जिंक सोडियम और विटामिन B12, B6 मिलता है। औसतन देखा जाए तो 10 से 20 किलो के तीतर को आप लगभग ₹350 में बेच सकते हैं। और यहां पर अगर हम अवधि की बात करें तो लगभग हर एक तीतर पर 25 हफ्ते की अवधि में आप 300 से 350 ₹ बचा सकते हैं।

बाज़ार में है तीतर के चूजों की मांग:

पेपर के मांस और अंडों की तरह ही इसके चीजों की भी मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है। आप चाहें तो स्वस्थ चूजों को आगे चलकर मांस के लिए पाल सकते हैं और उनके पोषण के लिए आप उन्हें दूध और अंडे दे सकते हैं।

तीतर के चूजे प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए बाजार में उनका बहुत ज्यादा प्रचलन है। यहां पर हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, कि तीतर के चूजों में सबसे ज्यादा मौत भुखमरी के कारण होती है। इसीलिए हमें उनके खान-पान का बेहद ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें समय-समय पर दाना और पानी देते रहने की आवश्यकता है।

तीतर करता है खुद ही सफाई

तीतर पक्षी छोटे केंचुए और कीड़े मकोड़े खाने में सक्षम है, इससे तीतर को प्रोटीन भी मिलता है और उनकी सेहत भी बनी रहती है। इसलिए तीतर के पालन में आपको एक फायदा यह है कि इससे आपके आसपास के इलाके की सफाई भी हो जाती है। और साथ ही तीतर की सेहत पर भी इससे कोई असर नहीं पड़ता है।

चिकन पालन से कैसे है यह सस्ता

चिकन या मुर्गी पालन से तीतर का पालन करने का व्यवसाय सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुर्गी पालन में हमें साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन तीतर पक्षी में ऐसा नहीं है, आप कम लागत पर इसका रखरखाव और सफाई कर सकते हैं। इसके पालन के लिए आपको कम जगह की जरूरत पड़ती है, साथ ही इसके पालन में आपको निवेश भी कम करना पड़ता है।

लाइसेंस लेना है ज़रूरी

अगर आपने यह मन बना लिया है कि आप तीतर पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसे मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इसे आप बिना लाइसेंस के शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, भारत सरकार ने तीतर के शिकार को प्रतिबंधित कर रखा है क्योंकि यह एक विलुप्त प्रजाति का पक्षी माना जाता है। बहुत ज्यादा शिकार और अलग-अलग तरह के दवाइयों और केमिकल के इस्तेमाल के कारण यह पक्षी विलुप्त प्रजाति में आ गया था। इसीलिए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने लाइसेंस पद्धति का सहारा लिया है।

अगर आपने तीतर पालन के लिए सेटअप तैयार कर लिया है और अपना मन बना लिया है, तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत है। साथ ही आप यह व्यवसाय करके विलुप्त होते हुए तीतर की प्रजाति को बचाने में भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं।

इस तरह से हम यह समझ सकते हैं कि आजकल मार्केट में जहां आपको हर जगह मुर्गी या बतख पालन करने वाले व्यवसाय मिल जाएंगे, वहीं पर तीतर तीतर पालन एक नया व्यवसाय है। लेकिन इन दोनों ही व्यवधान से ऊपर आप यहां पर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, इसके अलावा यहां पर आपको लागत भी कम लगानी पड़ेगी। आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ने वाली है, जिस तरह से हम आए दिन लोगों का स्वास्थ्य के प्रति ध्यान बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और नई नई चीजों के प्रति लोगों का आकर्षण देख रहे हैं। तो जल्द ही तीतर का यह व्यवसाय शिखर तक पहुंचने वाला है, तो किसी भी तरह से देर ना करें और कम लागत पर ही तीतर का या बिजनेस शुरू करें।

मधुमक्खी पालन में आने वाली समस्याएं और लगने वाले रोग :

वैसे तो मधुमक्खियां खुद ही एक बेहतरीन पोलिनेटर के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए इनमें ज्यादा बीमारियां नहीं होती है, लेकिन बदलते पर्यावरणीय प्रभाव और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से फूलों में पहुंचे दूषित और केमिकल तत्व मधुमक्खियों के शरीर में चले जाते हैं, जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

वरोआ माइट (Varroa mites) :

यह कीट पिछले कई सालों से मधुमक्खी की कॉलोनियों को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। यह बड़ी से बड़ी मधुमक्खियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।

प्रगतिशील किसान

किसान ने बाजरा की खेती करने के लिए तुर्की से मंगवाया बाजरा

महाराष्ट्र राज्य के धुले जनपद में सकरी तालुका के पिंपलनेर निवासी किसान निसार शेख ने तुर्की (Turkey) से बाजरे (Pearl millet; Bajra) के बीज मंगाकर, बाजरे की खेती तैयार की है, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होने की आशा है।

खेती की सारी तैयारी बेहतर तरीके से करने में सफल हुए निसार शेख, तुर्की से मंगाये बाजरे द्वारा तैयार की गयी फसल की ऊंचाई लगभग १२ फीट तक हो चुकी है। साथ ही निसार शेख ने फसल के बारे में बताते हुए कहा कि इस बाजरा की रोटी में अच्छा स्वाद है और इसकी अच्छी रोटी भी बनती है। बाजरा की फसल बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुयी है, इसलिए उनको कम उत्पादन होने की सम्भावना है। बतादें कि तुर्की से बाजरे के बीज के लिए निसार शेख को १००० रुपये प्रति किलो की खरीदी पड़ी है।

किसान नासिर शेख ने फसल के बारे में क्या कहा ?

नासिर शेख ने बाजरे की फसल के बारे में बताते हुए कहा है कि, उन्होंने बाजरे की बुवाई के दौरान प्रति एकड़ डेढ़ किलो बीज बोया है। इसकी भी बुवाई, जुताई एवं सिंचाई भी अन्य बाजरे की तरह ही होती है, इसमें भी समान ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसकी उपज ६० क्विंटल प्रति एकड़ के करीब तक होती है। इस प्रकार तुर्की से बाजरे का बीज मंगाकर बाजरे की खेती किसी ने नहीं की है, साथ ही यह एक अनोखा प्रयोग है।

अन्य क्षेत्रों से भी आ रहे हैं किसान फसल की जानकारी लेने के लिए ?

तुर्की से मंगाए गए बाजरे के बीज की चर्चा आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में है। इस प्रकार से बाजरे की खेती किसी के द्वारा नहीं की जाने के चलते लोग इसको देखने के लिए बहुत दूर से आ रहे हैं। किसानों को इस तरह की फसल के बारे में जानने की बहुत लालसा हो रही है, इसलिए दूर दराज रहने वाले किसान भी नासिर सेख से मिलने आ रहे हैं। किसान बाजरे की १२ फ़ीट ऊंचाई को भी देखने के लिए आतुर हैं।

बाजरा की खेती के लिए कितने राज्य अनुकूल हैं

बाजरा की खेती के लिए उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरयाणा एवं आंध्र प्रदेश सहित देश के २१ राज्य के वातावरण अनुकूल हैं। बाजरा को उगाने के लिए न्यूनतम बारिश (२००-६०० मिमी) की स्तिथि में शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। बाजरा के अंदर काफी मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, साथ ही इसकी फसल हर प्रकार की जलवायु में आसानी से प्रभावित नहीं होती है।

बोनसाई के पेड़ उगा सौमिक दास बने लखपति वातावरण शुद्धि में भी किया योगदान

सौमिक दास (Saumik Das) ने बोनसाई (Bonsai) एवं पेनजिंग (Penjing) के पेड़ उगाकर वातावरण को प्रदुषण और गर्मी से बचाने की सराहनीय पहल शुरू की है। आज वह ३० लाख तक पौधे उगाकर लाखों की आय कर रहे हैं, साथ ही पेंजिंग और बोंजाई की खेती का ३०० से अधिक लोगों को "ग्रो ग्रीन बोनसाई फार्म" (Grow Green Bonsai Farm) के तहत प्रशिक्षण दे उनकी आय का स्त्रोत बनाया है।

दिल्ली का प्रदुषण चरम सीमा पर रहता है, क्योंकि वहां गाँव की अपेक्षा में पेड़ों की संख्या बेहद कम है। इसलिए दिल्ली में प्रदुषण एवं गर्मी देहात से अधिक होती है, इन सब समस्याओं को देखते हुए सौमिक दास ने अपने ही घर में बोन्साई पेनजिंग (Bonsai Penjing) के हजारों पेड़ उगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पेड़ों की बिक्री ३५ लाख रुपये तक की सीमा तक पंहुच चुकी है, जिसमे उन्होंने खुद के घर में २००० के करीब बोनसाई और पेंजिंग के पेड़ उगा रखे हैं। बतादें की बोनसाई के वृक्ष तापमान को १० डिग्री तक कम कर देते हैं, एवं वातावरण को शुद्ध रखने में काफी मददगार साबित होते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन के मुख्य स्त्रोत होते हैं, जो कार्बन डाई ऑक्साइड को खुद संचय करके हमको प्राणवायु देते हैं, इसलिए जनजीवन को स्वस्थ्य बनाने के लिए वृक्षारोपण अधिक मात्रा में करना एवं पेड़ पौधों का संरक्षण करना बेहद आवश्यक है।

सौमिक दास को कैसे बोनसाई के पेड़ों को लगाने का विचार आया ?

बोनसाई का पेड़ घरों की शोभा बढ़ाता है, जिसको विदेशों में ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर लगाते हैं। सौमिक दास ने बोनजाई के पेड़ को सर्वप्रथम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम (Talkatora Indoor Stadium) में एक मैच के दौरान देखा था। बोनजाई के पेड़ ने सौमिक दास को बहुत आकर्षित किया जिससे प्रभावित होकर सौमिक दास ने बोनजाई के पेड़ों को उगाकर तैयार करना शुरू कर दिया। जिसके लिए सौमिक दास ने पेंजिंग विधि की जानकारी विदेश से ली, क्योंकि बोंजाई के पेड़ों का प्रचलन हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं था। बोंजाई के पेड़ का जीवनकाल लगभग ५०० साल तक होता है, साथ ही इसको तैयार करने में काफी समय लगता है। बोंजाई के पेड़ को लगाकर वातावरण शुद्ध एवं ठंडा रख सकते हैं।

बोनजाई के पेड़ की क्या विशेषता है ?

बोनजाई का पेड़ वातावरण को शीतल बनाने और शुद्ध रखने में बेहद सहायक होता है। इसकी शुरुआत जापान से हुई है, जिसकी सुरक्षा पॉलीहाउस के माध्यम से की जाती है। इसके लिए किसी भी अन्य उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यह तैयार होने में काफी समय लगाता है। बोनजाई के पेड़ की कीमत ७०० से लेकर ढ़ाई लाख तक होती है। कई देशों में इसको गुडलक ट्री (Good Luck Tree) भी बोलते हैं। बोनजाई का पेड़ न केवल वातावरण को अच्छा बनाता है, बल्कि घरों के सौंदर्यीकरण में भी इसकी अहम भूमिका होती है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए भी बोनसाई के पेड़ों को लगाते हैं।

रघुपत सिंह जी कृषि जगत से गायब हुई 55 से अधिक सब्जियों को प्रचलन में ला 11 नेशनल अवार्ड हासिल किये

उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद जनपद के बिलारी निवासी किसान रघुपत सिंह जी ५५ से ज्यादा सब्जियों की गायब हो चुकी किस्मों को पुनः खेती की धारा में लाये। साथ ही १०० से अधिक नवीन किस्म की सब्जियां व वनस्पति की प्रजाति विकसित की हैं। इस सराहनीय कार्य को करते हुए उन्होंने ११ अवार्ड हासिल किये हैं, साथ ही केंद्र सरकार भी उनकी आभारी है।

रघुपत ने एक अलग और रचनात्मक सोच को प्रदर्शित किया है, खेती को अलग तरह से करकर उससे अच्छा खासा सम्मान व धन दोनों अर्जित किया जा सकता है। जमीनी तौर पर गायब हो चुकी सब्जियों की प्रजातियों को पुनः अस्तित्व में ला दिया है, साथ ही किसानों के लिए आय के अवसरों की एक नई राह प्रदर्शित की है।

रघुपत जी की दिनचर्या भी अन्य किसानों से बिलकुल भिन्न है व उनकी खेती करने का तरीका व सोच भी, क्योंकि वह असाधारण खेती करके कृषि जगत में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। रघुपत का कहना है कि उन्होंने सामान्य खेती प्रणाली की अपेक्षा गायब हो चुकी सब्जियों की किस्मों को विकसित करने की पहल की जिनका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। रघुपत के इस सकारात्मक एवं सराहनीय कार्य से देशभर में उनको खूब सम्मान मिल रहा है।

रघुपत जी द्वारा विकसित किस्मों से क्या लाभ होगा ?

रघुपत जी द्वारा विकसित किस्मों से उन किसानों को बेहद लाभ होगा जो बड़े किसानों की भाँति पैदावार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लघु किसानों को नए रास्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रघुपत जी लगभग ३ लाख से ज्यादा किसानों को खेती के लाभ भी बता चुके हैं, देशभर में खेती से सम्बंधित समस्त संस्थान रघुपत जी के प्रसंशक हो चुके हैं। रघुपत जी खुद के द्वारा फसल का तैयार बीज आर्थिक रूप से कमजोर एवं छोटे किसानों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि वह किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त करने का जरिया दे सकें। लघु किसान इनके द्वारा विकसित बीजों की सहायता से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।

रघुपत जी को विलुप्त हो चुकी सब्जियों की किस्मों को विकसित करने के लिए कितने अवार्ड मिले हैं ?

रघुपत जी अनेकों किसानों को फसल सम्बंधित प्रशिक्षण दे चुके हैं, साथ ही यह भी बताते हैं, कि किसान किस किस्म की फसल से कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को रघुपत द्वारा विकसित किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, इससे जमीनी तौर पर गायब हो चुकी फसलों को दुबारा से अस्तित्व में आने का अवसर मिलेगा, साथ ही किसानों को भी बेहतर मुनाफा हासिल होगा। रघुपत जी ने कृषि जगत से गायब हो चुकी ५५ से ज्यादा सब्जियों को पुनः अस्तित्व में लाने के साथ साथ १०० से अधिक सब्जियों व वनस्पतियों की किस्म विकसित की हैं। रघुपत जी इस सराहनीय उपलब्धि के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में रघुपत जैसे किसानों की बेहद आवश्यकता है।

बिहार में मशरूम की खेती कर महिलाएं हजारों कमा हो रही हैं आत्मनिर्भर

बिहार राज्य के डॉक्टर दयाराम (Doctor Dayaram) ने लाखों महिलाओं एवं किसानों के जीवन को मशरूम या कुकुरमुत्ता (कवक; Mushroom) की खेती की बेहतर जानकारी देके उनकी आजीविका के लिए आय का स्त्रोत निर्मित किया है। कोरोना जैसी महामारी के चलते लोगों की आजीविका खतरे में आ गयी थी, इस समस्या को देखते हुए डॉक्टर दयाराम जी ने किसानों को मशरूम करके आय करने के लिए प्रेरित किया एवं भरपूर उनकी भरपूर सहायता भी की।

डॉक्टर दयाराम जी को बिहार के मशरूम मैन (Mushroom Man) के नाम से भी जाना जाता है। इनके मशरूम की खेती के बारे में पूर्ण जानकारी एवं सहायता करने की वजह से सभी किसान उनको बेहद सम्मान और प्रेम के भाव से देखते हैं। डॉक्टर दायाराम जी द्वारा गरीबों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मशरूम को ही उनकी आजीविका का साधन बना दिया है। दयाराम जी की मेहनत एवं लगन के जरिये आज हजारों गरीब परिवारों को आय का स्त्रोत प्राप्त हो पाया है, साथ ही उनकी आजीविका में भी बेहद सुधार हुआ है। डॉक्टर दयाराम का कहना है कि उनके इस सराहनीय प्रयास से भूमिहीन मजदूर भी अपनी झुग्गी झोपडी में मशरूम उत्पादित कर, बिना किसी के आश्रित हुए अपना जीवन यापन कर सकते हैं।

मशरूम की खेती को लेकर डॉक्टर दयाराम का क्या कहना है ?

डॉक्टर दयाराम जी ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरे देश की ही अर्थव्यवस्था खतरे में आ गयी थी। सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के लोग हुए थे, इसका कारण यह है कि बिहार में औघोगिक इकाईओं की कमी है। जिसके चलते बिहार के लोगों को अपनी आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है। कोरोना महामारी की वजह से हजारों मजदूरों का रोजगार समाप्त हो गया था,और उनको पुनः अपने राज्य में वापस आना पड़ा। ऐसी स्तिथि में मजदूरों का जीवन यापन बेहद कठिन हो गया था। इसलिए दयाराम जी ने मजदूरों को मशरूम की खेती के फायदे एवं उसे करने की पूरी विधि किसानों एवं मजदूरों से साझा की जिसको किसान व मजदूरों ने अपनाया और मशरूम उगाना शुरू कर दिया।

सर्वप्रथम यहां से की थी मशरूम की खेती

डॉक्टर दयाराम जी ने सर्वप्रथम समस्तीपुर जनपद के एक गांव में ईंट- भट्ठे पर कार्य करने वाले मजदूरों को मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया था, जिसके लिए दयाराम जी ने मजदूरों को अच्छी तरह खेती की विधि एवं बीज भी प्रदान किये। मशरूम की खेती मजदूरों के लिए एक नयी अजीब बात थी। विचित्र बात यह है की मजदूरों द्वारा ओएस्टर का थैला भी उनके पशुओं के रहने वाले स्थान पर ही लटकाया जाता था, जिसकी पूर्ण विधि महिलाओं ने भी जानी और आज महिलायें मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता की राह पर चल रही हैं।

कितना कमा सकते हैं मशरूम की खेती से ?

मशरूम की ओएस्टर वैरायटी की उपज लगभग न्यूनतम २५ और अधिकतम ४० डिग्री पर आसानी से होती है, जिसकी सहायता से एक परिवार प्रति माह १०-२० बैग मशरूम बेचकर ४ से ५ हजार रूपये की आय कर अपना जीवन यापन कर रहा है। इसकी पैदावार में लगभग २० से २५ दिन लग जाते हैं। समस्तीपुर से शंकर का कहना है जो कि खुद एक मशरूम के किसान है, पहले उनको मशरूम की खेती के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। डॉक्टर दयाराम जी द्वारा किये गए प्रयास और अथक मेहनत से आज उनके परिवार की महिलाएं भी मशरूम उगा रही हैं, साथ ही आसपास के सभी लोग भी मशरूम उगाकर फायदा कमा रहे हैं।

सामान्य लेख

हाइड्रोपोनिक्स – अब मृदा की जगह पोषक तत्वों वाले पानी में उगाएँ सब्ज़ी और फ़सलें, उपज जानकर हो जाएंगे हैरान

आप सभी ने बचपन में एक कहावत तो सुनी ही होगी की :
'विज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है'
आज इसी विचारधारा पर आगे बढ़ते हुए कृषि क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक इस स्तर पर पहुँच गए हैं कि अब फसलों को उगाने के लिए मृदा की भी आवश्यकता नहीं है, इससे पहले हमने आपको बिना मिट्टी के एयरोपोनिक्स तकनीक से आलू उगाने की तकनीक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवायी थी।

आज हम आपको बिना मृदा के केवल पानी के एक विलियन (Solution) से किसी भी फसल की छोटी पौध और सब्ज़ी उगाने के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसे जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) तकनीक के नाम से जाना जाता है।

क्या होती है हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) तकनीक और कब हुई थी इसकी शुरुआत ?

इस तकनीक की शुरुआत अमेरिकन आर्मी के कुछ सैनिकों के द्वारा की गई थी, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जब उन्हें प्रशांत महासागर के एक टापू पर कुछ समय के लिए रहना पड़ा था। इसी दौरान उनके पास खाने की कमी हो गई थी, तो उन्होंने उसी टापू पर बिना मिट्टी के ही सब्ज़ी की छोटी पौध उगाने की शुरुआत कर अपने खाने की व्यवस्था की।

इस तकनीक में किसी भी फ़सल की छोटी पौध की जड़ों को ऑक्सीजन और कई मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर पानी में डुबोकर रखा जाता है, इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण कर यह पौधा वृद्धि करता है।

हाइड्रोपोनिक्स (Hydroponics) तकनीक से होने वाले फ़ायदे :

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल कर अब भारत में रहने वाले कुछ युवा किसान भी अच्छा ख़ासा मुनाफ़ा कमा रहे हैं, क्योंकि इस तकनीक की मदद से निम्न प्रकार के फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि :

बिना मृदा के फ़सल का उत्पादन :

इस तकनीक के इस्तेमाल का यह सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसी वजह से भारत में पाई जाने वाली कुछ ऐसी जगहें, जहाँ की मृदा फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, अब उन स्थानों पर भी अच्छी-ख़ासी खेती की जा रही है।

फ़सल की वृद्धि दर पर बेहतर नियंत्रण :

इस तकनीक के इस्तेमाल की वजह से फ़सल की वृद्धि दर को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि फसल की पौध को दिए जाने वाले पानी के विलयन में पोषक तत्वों की मात्रा आसानी से कम या अधिक की जा सकती है। इसी वजह से सही समय पर वृद्धि दर को नाप कर पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर वृद्धि दर को भी बढ़ाया जा सकता है।

अधिक उत्पादन प्राप्त करना और पर्यावरण जनित रोगों का कम प्रभाव :

हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की मदद से फसल और सब्ज़ी की उपज को आसानी से बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा फसल की छोटी पौध में लगने वाले रोगों से भी आसानी से बचा जा सकता है।

केरल के एर्नाकूलम ज़िले में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल करने वाले किसान विजयराज बताते हैं कि पिछले दो वर्षों से इस तकनीक की मदद से उनकी वार्षिक उपज में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अब उर्वरकों पर होने वाले ख़र्चे में भी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा कीटनाशक और दूसरे प्रकार के रोगों के निदान में ख़र्च होने वाली लागत को भी बचाया जा रहा है।

मृदा में उगाई जाने वाली फसलों की तुलना में कम पानी का इस्तेमाल :

कम बारिश और कम भूजल स्तर वाली जगहों पर पानी की उपलब्धता कम होती है, ऐसे स्थानों पर इस तकनीक का इस्तेमाल कर आसानी से बेहतर फसल उत्पादन किया जा सकता है।

पिछले 3 वर्षों से तमिलनाडु के मदुरई क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवा किसान कम पानी के बावजूद भी बेहतर फसल उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हालांकि ऊपर बताए गए फायदों के अलावा, हाइड्रोपोनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसानों पर अधिक आर्थिक दबाव पड़ता है, क्योंकि इसके प्लांट को सेट अप करना काफी महंगा पड़ सकता है।

इसके अलावा वर्तमान में कुछ युवा और डिजिटल तकनीक का ज्ञान रखने वाले किसान भाई ही इस विधि के प्रयोग में सफलता हासिल कर पाए हैं।

इस तकनीक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हर समय इलेक्ट्रिसिटी (Electricity) की आवश्यकता होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान भाइयों के लिए अभी संभव नहीं है।

हाइड्रोपोनिक तकनीक के प्लांट में इस्तेमाल आने वाले उपकरण और अन्य माध्यम :

मुख्यतः इस तकनीक में एक 'सयंत्र' सेटअप किया जाता है, जिसके अंदर ही पौधे को लगाया जाता है और ऑक्सीजन तथा बेहतर पोषक तत्वों से घुलित पानी के मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है, बेहतर प्रवाह के लिए इलेक्ट्रिक पंप तथा एयरस्टोन जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है।

वर्तमान में हाइड्रोपोनिक तकनीक के लिए भारत में इस्तेमाल किए जा रहे 'सयंत्र' :

वर्तमान में केरल और तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय युवा किसान, हाइड्रोपोनिक तकनीक में इस्तेमाल आने वाले दो तरह के संयंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि निम्न प्रकार है :

निरंतर पोषक तत्व प्रवाहित होने वाला सयंत्र (Continuous flow Nutrient Film Technique (NFT)) :

हाइड्रोपोनिक संयंत्र में पानी से भरपूर पोषक तत्व का निरंतर प्रवाह किया जाता है और एक बार प्रवाहित होने के बाद पानी को वापस इलेक्ट्रिक पंप की सहायता से दोबारा से पाइप लाइन से गुजारा जाता है।

इस तकनीक की मदद से पौधे की जड़ों को आसानी से ऑक्सीजन और पानी की आपूर्ति की जाती है और पोषक तत्व का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

हाल ही में केरल के अर्नाकुलम और कोच्चि क्षेत्र के किसान भाई इस तकनीक की मदद से टमाटर उगाने में सफल हुए हैं।

गहरे पानी में लगाया जाने वाला संयंत्र (Deep Water Culture (DWC) system) : इस प्रकार के संयंत्र की मदद से आसानी से फसल की अधिक मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है और आसानी से बड़े प्लांट को सेटअप किया जा सकता है।

गहरे पानी में होने की वजह से तापमान का बेहतर नियंत्रण किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक वाल्व की मदद से पानी के प्रभाव को भी कम या अधिक किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश और केरल राज्य के तटीय इलाकों में रहने वाले कई किसान भाई इस संयंत्र की मदद से अच्छा खासा उत्पादन कर पा रहे हैं।वर्तमान में हाइड्रोपोनिक तकनीक की मदद से टमाटर, कुकुंबर और स्ट्रॉबेरी तथा कई आयुर्वेदिक उत्पाद प्राप्त किए जा रहे हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल में प्रत्येक फसल के लिए अलग तरह के पोषक तत्वों का प्रयोग करना पड़ता है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई भारतीय स्टार्टअप कम्पनियाँ और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हाइड्रोपोनिक तकनीक के लिए इस्तेमाल आने वाले पोषक तत्वों को बाजार में उपलब्ध करवा रही है।

आशा करते हैं कि किसान भाइयों को बिना मृदा के फसल उत्पादन करने की इस नई 'हाइड्रोपोनिक तकनीक' के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली मर्दा की उर्वरा शक्ति कमजोर है तो इस तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर वैज्ञानिक विधि से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

हवा में आलू उगाने की ऐरोपोनिक्स विधि की सफलता के लिए सरकार ने कमर कसी, जल्द ही शुरू होगी कई योजनाएं

सन 2015 से 2022 तक भारत में आलू (Potato) का उत्पादन लगभग 45 मिलियन मैट्रिक टन से 55 मिलीयन मेट्रिक टन के बीच में रहा है। भारत में उगने वाले कुल आलू में उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक रहता है और वर्तमान में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है।

बढ़ती मांग के मद्देनजर आलू उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए कई नए वैज्ञानिक तरीके बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं, जिनमें हाइड्रोपोनिक (Hydroponics method) अथार्त पानी की मदद से आलू उगाना और परंपरागत तरीके से उत्पादन की पुरानी हो चुकी तकनीकों से हटकर एक काफी लोकप्रिय हो रही है, जिसे एयरोपोनिक्स आलू फार्मिंग (Aeroponics Potato Farming) के नाम से जाना जाता है।

एयरोपोनिक्स आलू फार्मिंग

इस तकनीक में आलू उगाने के लिए जमीन की आवश्यकता नहीं होती है और केवल हवा की मदद से ही आलू की पौध का उत्पादन किया जा सकता है।

भारत में एयरोपोनिक्स तकनीक का सबसे पहले इस्तेमाल करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र (Potato Technology Centre) के द्वारा किया गया था। एयरोपोनिक्स तकनीक से मिल रहे परिणामों से यह सामने आया है कि परंपरागत आलू उत्पादन विधि की तुलना में इस नई वैज्ञानिक विधि की मदद से 6 गुना तक अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, कृषि अनुसंधान केंद्र से जुड़े कई वैज्ञानिक उत्पादन की इस क्षमता का समर्थन भी कर चुके हैं।

पूसा कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि कई बार नए किसान भाइयों को इस तकनीक को समझाने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आखिर कैसे बिना मिट्टी और जमीन के भी आलू का उत्पादन किया जा सकता है।

भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के तहत बनी एक समिति ने भी इस तकनीक से पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों की जांच कर इसे मंजूरी प्रदान कर दी है।

क्या है एयरोपोनिक्स तकनीक और इससे जुड़ी वैज्ञानिक समझ ?

वर्तमान में लोकप्रिय एयरोपोनिक्स तकनीक में पौधे को ठंडे इलाकों में स्थित वातावरण में उगाया जाता है। इस तकनीक में आलू को उगाने के लिए मिट्टी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सबसे पहले बड़े-बड़े बॉक्स में पौधे को लटका दिया जाता है और ऊपर के क्षेत्र को पूरी तरह ढक दिया जाता है इसके बाद प्रत्येक बॉक्स में सूक्ष्म पोषक तत्व डाले जाते हैं, एक बार पोषक तत्वों की मात्रा पूरी हो जाने के बाद थोड़ा बहुत पानी का स्त्राव भी किया जाता है, हालांकि पानी के छिड़काव के दौरान ध्यान रखें कि केवल इतना ही पानी डालें, जिससे कि पौधे की जड़ों में थोड़ी बहुत नमी बनी रहे। एयरोपोनिक्स आलू फार्मिंग (Seed Potato Crop in Aerophonics at PTC Shamgarh Karnal; Source: Potato Technology Centre, Shamgarh, Karnal) मिट्टी और भूमि की कमी होने वाले इलाकों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सकता है, इसके अलावा शहरों में रहने वाले लोग भी इस तकनीक से किसानी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

नियंत्रित तापमान और आद्रता की स्थिति में इस्तेमाल आने वाली एयरोपोनिक्स तकनीक, किसानों को परंपरागत विधि से तैयार तकनीक से भी अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करवा सकती है। कम पोषक तत्व और पानी के कम इस्तेमाल के बाद भी इस विधि से उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही उर्वरक और मजदूरी जैसे दूसरे प्रकार के खर्चों में अच्छी खासी कमी देखने को मिलती है।

वैज्ञानिक शोध के अनुसार परंपरागत तरीके से एक किलो आलू उत्पादन करने के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि एयरोपोनिक्स तकनीक में एक किलोग्राम आलू उत्पादन के लिए केवल 7 से 10 लीटर पानी पर्याप्त रहता है।

इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि आलू के उत्पादन के दौरान पॉलीघर या पॉलीहाउस (Polyhouse) का इस्तेमाल जरूर करें। पोली हाउस आपके प्लांट को ऊपर से ढकने के लिए इस्तेमाल में आने वाली पॉलीथिन से बनाया गया एक ढांचा होता है, जो मुख्यतः तापमान नियंत्रण का काम करता है।

वर्तमान में भारत के किन क्षेत्रों में हो रहा है एयरोपोनिक्स आलू उत्पादन ?

प्लास्टिक शीट में छेद करके एयरोपोनिक्स विधि से उत्पादन की तकनीक का इस्तेमाल भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हरियाणा और पंजाब के राज्य में पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में पूसा के वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्रों के अलावा हिमालय पर्वत से जुड़े हुए बर्फीले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर अच्छा खासा उत्पादन किया है।

हिमालयी राज्यों में एक बॉक्स बनाकर पौधे की जड़ लटका दी जाती है और पोषक तत्वों का छिड़काव करते हुए तब तक पानी दिया जाता है, जब तक इन जड़ों में आलू लगना शुरू नहीं हो जाता है। एक बार आलू की वृद्धि हो जाने पर बॉक्स को खोल कर तैयार आलू को अलग कर लिया जाता है।

एयरोपोनिक्स तकनीक से आलू से होने वाला उत्पादन :

कृषि वैज्ञानिकों की राय में कम समय में ही एक यूनिट क्षेत्र में केवल 20 हज़ार आलू के पौधे लगाकर 6 लाख बीज तैयार किए जा सकते हैं। इस तकनीक की मदद से किसान आसानी से परंपरागत खेती की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र (International Potato Centre) के अनुसार भारत में इस तकनीकी का भविष्य काफी उज्ज्वल दिखाई दे रहा है।

हाल ही में कृषि मंत्रालय भी स्थानीय राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस तकनीक के प्रसार की नीतियां बना रहा है।

वैज्ञानिकों की राय में एक बार इसका सेटअप किए जाने के बाद तो मुनाफा कमाना आसान है, हालांकि इसकी शुरुआत करना काफी खर्चीली साबित हो सकती है। गार्डनिंग का अनुभव रखने वाले किसान भाई इस तकनीक का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पोली हाउस का इस्तेमाल कर गार्डनिंग करने का अनुभव पहले से ही हासिल है।

हाल ही में पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ जिले के कुछ इलाकों में पानी की कमी होने की वजह से किसानों को एयरोपोनिक्स तकनीक के इस्तेमाल के लिए आलू के अच्छे बीज प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार तथा स्थानीय राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के अपने प्रयास में इस तकनीक का सहारा लेकर जल्द ही कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी बेहतर उत्पादन करने के लिए कमर कस चुकी है।

सामान्यतः पूछे जाने वाले सवाल (FaQs) :

सवाल – क्या राज्य या केंद्र सरकार एयरोपोनिक्स फार्मिंग के लिए किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाती है ?

जवाब :- हाल ही में कृषि मंत्रालय ने एयरोपोनिक्स प्रोजेक्ट के लिए 'कमर्शियल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम' (Commercial Horticulture Development Scheme) के तहत किसानों को प्रोजेक्ट शुरु करने के लिए लगे सम्पूर्ण खर्चे की 20% तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाने की घोषणा की है।

हालांकि इस विधि से उगाई जा रही अलग-अलग फसलों के लिए सब्सिडी की मात्रा अलग-अलग होती है, इसकी अधिक जानकारी आप अपने राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय की वेबसाइट या अपने आसपास स्थित किसी कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

सवाल – क्या एयरोपोनिक्स फार्मिंग करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है ?

जवाब – वैसे तो किसानों को एयरोपोनिक्स विधि से किसी भी प्रकार की फसल उगाने के लिए किसी विशेष लाइसेंस की आवश्यकता तो नहीं होती है, परंतु फिर भी पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल जैसी बातों को ध्यान रखते हुए कुछ विशेष प्रकार के लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपनी अलग गाइडलाइंस जारी की हुई है।

वर्तमान में लोकप्रिय एयरोपोनिक्स तकनीक में पौधे को ठंडे इलाकों में स्थित वातावरण में उगाया जाता है। इस तकनीक में आलू को उगाने के लिए मिट्टी और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सबसे पहले बड़े-बड़े बॉक्स में पौधे को लटका दिया जाता है और ऊपर के क्षेत्र को पूरी तरह ढक दिया जाता है इसके बाद प्रत्येक बॉक्स में सूक्ष्म पोषक तत्व डाले जाते हैं, एक बार पोषक तत्वों की मात्रा पूरी हो जाने के बाद थोड़ा बहुत पानी का स्त्राव भी किया जाता है, हालांकि पानी के छिड़काव के दौरान ध्यान रखें कि केवल इतना ही पानी डालें, जिससे कि पौधे की जड़ों में थोड़ी बहुत नमी बनी रहे। एयरोपोनिक्स आलू फार्मिंग (Seed Potato Crop in Aerophonics at PTC Shamgarh Karnal; Source: Potato Technology Centre, Shamgarh, Karnal) मिट्टी और भूमि की कमी होने वाले इलाकों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सकता है, इसके अलावा शहरों में रहने वाले लोग भी इस तकनीक से किसानी का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

नियंत्रित तापमान और आद्रता की स्थिति में इस्तेमाल आने वाली एयरोपोनिक्स तकनीक, किसानों को परंपरागत विधि से तैयार तकनीक से भी अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध करवा सकती है। कम पोषक तत्व और पानी के कम इस्तेमाल के बाद भी इस विधि से उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही उर्वरक और मजदूरी जैसे दूसरे प्रकार के खर्चों में अच्छी खासी कमी देखने को मिलती है।

वैज्ञानिक शोध के अनुसार परंपरागत तरीके से एक किलो आलू उत्पादन करने के लिए लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि एयरोपोनिक्स तकनीक में एक किलोग्राम आलू उत्पादन के लिए केवल 7 से 10 लीटर पानी पर्याप्त रहता है।

इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि आलू के उत्पादन के दौरान पॉलीघर या पॉलीहाउस (Polyhouse) का इस्तेमाल जरूर करें। पोली हाउस आपके प्लांट को ऊपर से ढकने के लिए इस्तेमाल में आने वाली पॉलीथिन से बनाया गया एक ढांचा होता है, जो मुख्यतः तापमान नियंत्रण का काम करता है।

स्मार्ट कृषि प्रणाली : किसानों की भविष्यकारी नीति और चुनौतियां

बदलते वैश्विक परिदृश्य में अब भारत सरकार भी डिजिटलीकरण के माध्यम से संचालित कृषि नीतियों को प्राथमिक उद्देश्य में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

साल 2022-23 के बजट में सरकार ने नई कृषि तकनीकों को डिजिटलीकरण के क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप तथा किसान उत्पादक संस्थान (Food Processing Organisation) के साथ मिलकर स्मार्ट कृषि की राह पर चलने का फैसला किया है।

कोविड-19 जैसी महामारी और कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुए खाद्य संकट को कम करने में भी स्मार्ट खेती का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है।

क्या होती है स्मार्ट कृषि ?

किसी भी खेती प्रणाली में अपशिष्ट उत्पादों की मात्रा को कम करते हुए, खेत से प्राप्त होने वाली उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को ही स्मार्ट कृषि (Smart Farming) कहा जा सकता है।

स्मार्ट कृषि एक बड़े परिदृश्य को परिभाषित करती है, इसके तहत बेहतरीन तकनीक की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट (remote sensing satellite) और दूसरे वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से संसाधनों के कुशल प्रबंधन को भी शामिल किया जा सकता है।

साल 2015 से विश्व के लगभग सभी देश समुचित विकास (Sustainable development) की राह पर चलते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए विश्व में खाद्य संकट के निदान के लिए प्रयासरत हैं।

विज्ञान की नई तकनीक जैसे रिमोट सेंसिंग, रोबोटिक्स तथा बिग डाटा एनालिटिक्स (Big Data Analytics) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) जैसी कई प्रौद्योगिकियों परंपरागत खेती को स्मार्ट कृषि में बदल सकती है।

स्मार्ट कृषि से किसानों को होने वाले फायदे :

किसी भी नई प्रौद्योगिकी और उत्पाद को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों से सोचा जाना चाहिए।

स्मार्ट खेती के लिए भी नई वैज्ञानिक तकनीक प्रभावी नीति निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जैसे कि :-

कृषि प्रणाली की दक्षता में बढ़ोतरी :-
किसी भी किसान के लिए खेत से अधिक उपज प्राप्त करना सपने के सच होने जैसा होता है। स्मार्ट कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही कृषि प्रणाली की दक्षता को सुदृढ़ करने में सक्षम है।

इसके लिए विभिन्न तरीके के उत्पाद, जैसे कि 'किसान ड्रोन' (Kisan Drone) का उपयोग पानी में घुलनशील उर्वरकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के अलावा कीटनाशक के सीमित इस्तेमाल के लिए भी किया जा सकता है।
श्रम संकट को ध्यान में रखते हुए किसान ड्रोन शारीरिक श्रम के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध हुआ है।
भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण: वर्तमान में ब्लॉकचेन तकनीक (Block-chain Technique) की मदद से विकसित देशों में सेंसर आधारित उपकरणों का सहयोग लेकर भूमि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी को डिजिटल माध्यमों की मदद से उपलब्ध करवाया जा रहा है।

नई तकनीकों के प्रसार की वजह से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और अलग-अलग योजनाओं के लिए लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना काफी आसान हो गया है, इस पारदर्शिता की मदद से सही लाभार्थी लोगों तक आर्थिक मदद को आसानी से पहुंचा जा सकता है।
कम्युनिटी विकास पर फोकस : छोटे किसानों के लिए स्मार्ट कृषि का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल हो जाता है, वर्तमान में स्मार्ट कृषि से अलग अलग क्षेत्रों के किसानों के मध्य जागरूकता बढ़ाने और भाईचारे का स्वभाव भी पैदा किया जा रहा है।

साल 2018 में बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी वी-ड्रोन ने आसपास के एरिया से छोटे किसानों को एक पैनल के जरिए जोड़ने का प्रयास किया और ऐसे किसानों के खेत की रोबोटिक्स और मेपिंग तकनीक की मदद से केवल पांचसौ रुपए के शुल्क पर एक एकड़ से अधिक भूमि का डाटा उपलब्ध करवाया।
बाजारू मांग की सही पहचान और बदलते मौसम की सही जानकारी : वेदर फोरकास्टिंग और सीधे मंडियों से जुड़े कई डिजिटल सॉफ्टवेयर की मदद से किसान भाइयों को उनके मोबाइल फोन पर ही वर्तमान में फसल की मांग के अनुसार बाजार में चल रही कीमत का पता लग जाता है।

इसके साथ ही भविष्य में स्टॉक की मात्रा का अंदाजा लगाकर किसान भाई फसल को कुछ समय तक स्टोरेज करके भी बेच सकता है।

मौसम से जुड़ी जानकारियां किसान भाइयों के खेत में होने वाले नुकसान को कम करने में सहयोग प्रदान करने के साथ ही शारीरिक श्रम में कमी और उर्वरकों के कम इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित करती है।

स्मार्ट कृषि प्रणाली में आने वाली चुनौतियां :

स्मार्ट कृषि की विकास प्रक्रिया में बाधित नकारात्मक प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:-
बजटीय सहायता की कमी : साल 2022 में कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास और अनुसंधान कार्यों के लिए बहुत ही सीमित राशि उपलब्ध करवाई गई है।
बदलते समय के साथ सरकार को भी समझना होगा कि अब केवल डिजिटलीकरण और स्मार्ट कृषि की मदद से ही उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।

लघु और सीमांत किसान जोत : भारतीय कृषि में किसानों की लघु और सीमांत आकार की जोत को एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है।

छोटे और सीमांत जोत में 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के खेत को शामिल किया जाता है।

वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 85 प्रतिशत से भी अधिक है, वहीं 10 हेक्टेयर से बड़ी खेत की जोत रखने वाले किसान केवल 0.5 प्रतिशत है।

किसानों के लिए स्मार्ट तकनीक से होने वाले आर्थिक लाभ को सीमित करने में जोत का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है।
कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों का कम विकास : टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेक्टर में बनने वाली नई स्टार्टअप कंपनियां की तुलना में कृषि क्षेत्र में काम करने वाली स्टार्टअप दो प्रतिशत से भी कम है।

अधिक जनसंख्या वाले देश में खाद्य संकट को सीमित करने के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीकों की विकास को मध्य नजर रखते हुए स्टार्टअप कंपनी की को बढ़ाने के लिए सरकार को भी प्रोत्साहन देना चाहिए।

विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत में खाद्य संकट बढ़ने की संभावनाएं 25% से अधिक हो जाएगी।

स्मार्ट कृषि में आने वाली समस्याओं का बिग डाटा एनालिटिक्स और बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज को बेहतर बना कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से समाधान किया जा सकता है।

आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को merikheti.com के द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्मार्ट कृषि से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी।भविष्य में आप भी डिजिटल माध्यमों का सदुपयोग करते हुए बेहतर कृषि उत्पादन के लिए नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सफल हो रही है भारतीय कृषि : नई उन्नति की राह बढ़ता किसान

आधुनिकता की राह पर चल रही नई विकसित दुनिया में भी भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 58% हिस्सा, कृषि क्षेत्र को जीवन यापन के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021 (Economic survey 2021-22) के अनुसार भारतीय कृषि ने पिछले 5 सालों में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर सीमित विकास प्रदर्शित किया है। हालांकि, आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमता (artificial intelligence), मशीन लर्निंग (Machine learning) और डाटा एनालिटिक्स (Data analytics) की मदद से भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता, लोगों के लिए सीमित मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाने के अलावा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उठाया गया एक सुदृढ़ कदम साबित हो सकता है।

बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के लिए सही समय पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर कई देशों के कृषि वैज्ञानिक, कृषि क्षेत्र में नए आविष्कार कर रहे हैं और इससे बढ़ी उपज की मदद से किसान भाई भी काफी मुनाफा कमा रहे हैं।

क्या है कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) ?

कृत्रिम बुद्धिमता मानव मस्तिष्क की तरह ही काम करने वाली एक नई तकनीक है, जोकि इंसानों के दिमाग के द्वारा किए जाने वाले काम की हूबहू नकल कर सकती हैं और जिस प्रकार मनुष्य किसी काम को करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और रोबोटिक्स की मदद से उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमता को सेल्फ ड्राइविंग कार के उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है, वर्तमान में कई डिजिटल ऑटोमोबाइल कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमता की मदद से बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां बनाने में सफल रही है।

परंपरागत तकनीक से कृषि करने वाले किसानों के सामने आने वाली समस्याएं :

पुराने समय से चली आ रही कृषि की परंपरागत तकनीक अब किसानों को पूर्व में होने वाले उत्पादन की तुलना में कम उत्पादन प्रदान करने के अलावा अब खेती करना किसान भाइयों के लिए आर्थिक रूप से काफी बोझिल साबित हो रहा है।

पर्यावरण में हुए परिवर्तन की वजह से बारिश और तापमान में आए अंतर और नमी में आई कमी या अधिकता की वजह से कृषि की पूरी चक्र प्रभावित हो रही है।

इसके अलावा बढ़ते औद्योगीकरण की वजह से हुई वनों की कटाई के कारण प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो किसानों की मिट्टी और बीजों की उपज को कम करने के साथ ही उनके उत्पाद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

इसके अलावा फ़र्टिलाइज़र पर मिलने वाली सब्सिडी का दुरुपयोग होने की वजह से, बदलते वक्त के साथ भारत की मृदा में पाए जाने वाले तीन मुख्य पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा में भी कमी देखी गई है, जोकि फसल के उत्पाद को कम करने के अलावा किसानों की आय को भी कम कर रहे हैं।

कई विकसित देशों के द्वारा अपनाए गए नए आविष्कारों की वजह से उनके यहां प्रति क्षेत्र में होने वाली कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है, जिससे विश्व के कुल निर्यात में भारतीय कृषि का निर्यात निरंतर घट रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भारतीय कृषि में इस्तेमाल :

पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल आविष्कारों की मदद से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बढ़ा है। अब बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त होने के अलावा, कीटनाशकों पर बेहतर नियंत्रण और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के साथ ही किसी भी फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक पारिस्थितिक आवश्यकताओं की जानकारी जैसे फायदों के साथ ही, खेत के लिए तैयार किए गए डाटा का एक जगह पर संकलन, किसान भाइयों पर आने वाले दबाव को कम करके, भोजन की सप्लाई चैन को सुचारू रूप से बनाए रखने में मददगार साबित हो रहा है।

मौसम / तापमान / बुवाई के लिए सही समय की जानकारी : अलग-अलग फसल के लिए आवश्यक पर्यावरणीय परिस्थितियां एक समान रहती है, लेकिन पर्यावरण में आए परिवर्तन की वजह से किसान भाइयों को किसी भी बीज को उगाने के लिए सही समय को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है।

इसी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता का इस्तेमाल कर अब भारतीय कृषि से जुड़े किसानों के लिए मौसम विभाग के द्वारा पर्याप्त डाटा उपलब्ध करवाया जा रहा है और अब इस डाटा के आधार पर किसान भाई बीज की बुवाई का सही समय का निर्धारण कर सकते हैं, जिससे बेहतर उत्पाद प्राप्त होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है।

ड्रोन की मदद से फसल की सम्पूर्ण जानकारी : कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल निरंतर बढ़ता जा रहा है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की मदद से अब किसान भाई सब्सिडी पर खेती में इस्तेमाल के लिए ड्रोन खरीद सकते हैं।

इस प्रकार के कृषि ड्रोन का इस्तेमाल फसल की वृद्धि दर को जांचने के अलावा कीटनाशक के छिड़काव और सीमित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए किया जा सकता है।

इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई स्टार्टअप कंपनियां अब ड्रोन की मदद से किसी भी खेत से प्राप्त होने वाले उत्पाद का आकलन करने में भी सफल हो रही हैं और फसल की वृद्धि दर को डाटा के रूप में इस्तेमाल करते हुए किसानों को खेत से प्राप्त होने वाले कुल उत्पाद की जानकारी पहले ही दे दी जाती है।

नई तकनीकों से लैस कई ड्रोन अब किसानों की फसल में लगे अलग-अलग प्रकार के कीट की तस्वीर खींच कर, उन्हें वैज्ञानिकों तक पहुंचा रही है और डिजिटल माध्यमों से ही किसानों को इस प्रकार के कीटनाशकों से फसल को बचाने के उपाय भी सुझा रही है।

कृषि रोबोटिक्स : कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में काम कर रही कई स्टार्टअप कंपनियां अब नए प्रकार के रोबोट बनाने की तरफ अग्रसर है, जो खेत में कई प्रकार के काम कर सकता है। विकसित देशों के किसान भाई इस प्रकार के रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू भी कर चुके हैं।

इस प्रकार की कृषि रोबोटिक तकनीक की मदद से अब खेत में कीटनाशक के छिड़काव के अलावा फसल की कटाई और बुवाई करने के लिए इंसानों की जगह मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह रोबोट आसानी से खेत में घूमते हुए फसल की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं और फसल के किसी भी हिस्से में लगे कीट को डिजिटल तकनीक से स्कैन करके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले कुछ समय से कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की बढ़ती मांग की वजह से अब कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले रोबोट को एक विकल्प के रूप में देखा किया जा रहा है।

मृदा और फसल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग : यह बात तो सभी किसान भाई जानते ही हैं कि बीज की बेहतर गुणवत्ता और पर्याप्त पोषक तत्वों वाली बेहतर मृदा ही फसल उत्पादन में अच्छा योगदान कर सकती है। अब कृत्रिम बुद्धिमता की मदद से मृदा की गुणवत्ता की जांच घर बैठे ही किया जा सकता है।

हाल ही में जर्मनी की एक स्टार्टअप कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमता पर आधारित एक एप्लीकेशन बनाई है जोकि मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा को किसान भाइयों के मोबाइल फोन में डाटा के रूप में उपलब्ध करवा देती है और उन्हें प्रति एकड़ क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों की मात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करवा रही है। इससे उर्वरकों का दुरुपयोग कम होने के साथ ही बेहतर उत्पादन प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी।

इसी एप्लीकेशन की मदद से अब किसान भाई अपने फोन से ही किसी भी छोटी पौध की तस्वीर खींचकर कृषि वैज्ञानिकों तक पहुंचा सकते हैं, जो कि उन्हें फसल में लगी बीमारियों की जानकारी देने के साथ ही उपचार भी उपलब्ध करवाते हैं।

कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता इस्तेमाल को सुदृढ़ करने के लिए किए गए सरकारी प्रयास :

भारत सरकार के द्वारा खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए ब्लॉकचेन तकनीक (Block-chain Technique) पर आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (Internet of Things) की मदद व आधुनिक डिजिटल माध्यमों के सहयोग से कई सरकारी प्रयास किए गए हैं, जो कि निम्न प्रकार है :

किसान सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन : इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से किसानों को भविष्य में समय में होने वाले मौसम की जानकारी के साथ ही फसल और उर्वरक की बाजार कीमत की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा फसल की छोटे पौध के बेहतर वृद्धि के लिए बताए गए कुछ उपाय शामिल किए गए हैं।

इन सुविधाओं के साथ ही खेती में इस्तेमाल आने वाली मशीनों और मौसम से होने वाले नुकसान की घटनाओं की जानकारी भी अलर्ट के माध्यम से दी जाती है।

सोयल हेल्थ कार्ड और कोल्ड स्टोरेज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कृषि क्षेत्र से जुड़ी लैब की लोकेशन भी उपलब्ध करवाई जाती है।

एम किसान पोर्टल (M-KISAN Portal) : इस पोर्टल पर किसान भाइयों को SMS की मदद से अलग-अलग फसलों से जुड़े डाटा को भेजा जाता है और किसानों को किसी भी फसल के बीज की बुवाई का सही समय भी बताया जाता है।

अलग-अलग लोकेशन और मौसम की वर्तमान स्थिति को ध्यान रखते हुए डाटा को अपडेट कर किसान भाइयों के मोबाइल फोन तक पहुंचाया जाता है।

किसान ड्रोन : कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन के बेहतर उपयोग के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है।

इसके अलावा 'किसान ड्रोन मिल' जैसे सरकारी सेवकों के माध्यम से डिजिटल माध्यमों से अनजान किसान भाइयों के लिए ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

इन सभी सरकारी योगदानों के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा कई अलग प्रकार की मोबाइल एप तैयार की गई है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट से जुड़ी नई तकनीक और किसी नए उत्पाद से जुड़ी जानकारियां किसानों तक पहुंचाती है।

वर्तमान में भारत सरकार 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र और 600 से अधिक कृषि से जुड़ी मैनेजमेंट संस्थानों की मदद से ग्रास रूट स्तर पर जाकर किसानों के मध्य कृत्रिम बुद्धिमता के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को लेकर प्रयासरत है।

आशा करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को Merikheti.com के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमता और इसके कृषि क्षेत्र में होने वाले प्रयोगों के संबंध में संपूर्ण जानकारियां मिल गई होगी। भविष्य में आप भी ऐसे ही नई तकनीक का इस्तेमाल कर उत्पादन को बेहतर बनाने के डिजिटल तकनीक के इस दौर में नए आविष्कारों की मदद से बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे।

पॉलीहाउस की मदद से हाईटेक कृषि की राह पर चलता भारतीय किसान

अपने जीवन में अपने कभी ना कभी हरित गृह प्रभाव या ग्रीनहाउस प्रभाव (green-house effect) के बारे में तो अवश्य सुना होगा, लेकिन इसी हरित ग्रह प्रभाव की मदद से कई भारतीय किसान अब पॉलीघर या पॉलीहाउस (Polyhouse) तकनीक का इस्तेमाल कर हाईटेक फार्मिंग या संरक्षित खेती करने में सफल हो रहे हैं।

क्या होता है पॉलीहाउस ?

पोली-हाउस हरित गृह प्रभाव पर काम करने वाली एक तकनीक होती है, जिसमें विशेष प्रकार की पॉलीथिन का इस्तेमाल फसलों को ढकने के लिए एक आवरण बनाकर किया जाता है। इस पोली हाउस की मदद से किसी भी जगह की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाता है।

कृषि में आई नई तकनीकों के शुरुआती दौर में हरित गृह प्रभाव के लिए लकड़ी के चेंबर बनाकर उसे कांच से ढका जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पॉलीथिन और प्लास्टिक के निर्माण में आए सुधारों की वजह से अब प्लास्टिक अथार्त पॉलीथिन (Poly-ethylene या Polythene) का इस्तेमाल भी हरित गृह प्रभाव के लिए किया जा रहा है।

पॉलीहाउस में किस फसल का हो सकता है सर्वश्रेष्ठ उत्पादन ?

वैसे तो पॉलीहाउस का इस्तेमाल दैनिक दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली सब्जी के उत्पादन और पौधे की छोटी नर्सरी तैयार करने में किया जाता है। वर्तमान में भारत के उत्तरी पूर्वी और हिमालय पर्वत से जुड़े राज्यों में कुकुम्बर (cucumber) और गुच्ची मशरूम (Gucchi Mushroom) के अलावा कई फसलें इसी विधि से तैयार की जा रही है। इसके अलावा सजावट और स्वास्थ्यवर्धक फायदे वाले कई प्रकार के फूल जैसे कि जरबेरा, गुलाब और ऑर्किड की खेती भी की जा रही है।

कैसे लगाएं पॉलीहाउस ?

पॉलीहाउस की शुरुआत करने के लिए आपको लगभग 1000 स्क्वायर मीटर की जगह की आवश्यकता होगी।

किसान भाई ध्यान रखें कि किसी भी पॉलीहाउस की संरचना बनाने से पहले उस जगह पर पानी की उपलब्धता और मार्केट की दूरी के बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेवें। इसके अलावा पॉलीहाउस को हमेशा समतल धरातल पर ही बनाना चाहिए और पॉलीहाउस का स्थान अपने आसपास के समतल धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। इसके लिए या तो आप कोई ऐसी जगह निश्चित कर सकते हैं जो ऊपर उठी हुई हो, या फिर अपने खेत की ही समतल जगह पर मिट्टी का जमाव कर स्थान को ऊपर उठा सकते है।

क्या है पॉलीहाउस फार्मिंग के फायदे ?

भारतीय किसानों के लिए मुख्यतः मौसम की मार कई बार उनके खेतों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसी मौसम के बदलते स्वरूप से होने वाले नुकसान से बचने के लिए, कठोर वातावरण वाले जगहों पर कृषि करने वाले किसान भाई, धीरे-धीरे पॉलीहाउस फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं।

जलवायुवीय बदलाव जैसे की हवा की तेजी और बारिश का कम या ज्यादा होना जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों से पोली हाउस की मदद से बचा जा सकता है।

पॉलीहाउस का एक और सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसके इसके अंदर उगाई जाने वाली कोई भी फसल को उसकी आवश्यकता अनुसार तापमान और नमी की मात्रा उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिससे उसकी वृद्धि दर तेज हो जाती है और उत्पाद जल्दी तथा अधिक प्राप्त होता है।

क्या है पॉलीहाउस फार्मिंग के फायदे ?

कृषि वैज्ञानिकों की राय में पोली हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक सांद्रण की वजह से उत्पाद अधिक तैयार होते हैं और परंपरागत तरीके से की जाने वाली खुली खेती की तुलना में पॉलीहाउस में लगभग 2 गुना तक उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं।

वर्तमान में पॉलीहाउस में मशीनीकरण के बेहतर इस्तेमाल की वजह से फर्टिलाइजर का छिड़काव और पानी की नियमित सिंचाई स्वचालित रूप से ही हो रही है, इसी वजह से किसान भाइयों की मजदूरी में लगने वाली लागत कम खर्च होती है।

हालांकि इन सभी फायदों के अलावा पॉलीहाउस फार्मिंग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि पॉलीहाउस को बनाना और पूरी तरह सेट अप करना काफी खर्चीला होता है। इसके अलावा पॉलीहाउस विधि से होने वाली कृषि की निरंतर निगरानी रखनी होती है और तापमान या नमी में थोड़े से बदलाव होने की वजह से ही फसल का नुकसान हो सकता है। पॉलीहाउस को चलाने के लिए किसी स्किल्ड सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है और किसान भाइयों को कई प्रकार का तकनीकी ज्ञान हासिल करना होता है।

खुले पर्यावरण से मिलने वाले कई पोषक तत्व और हवा में उपलब्ध कई सूक्ष्म पोषक तत्व पॉलीहाउस फार्मिंग में पौधे तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए इस विधि में उर्वरक और कीटनाशक का अधिक इस्तेमाल किया जाता है जो कि जैविक खेती की तरफ बढ़ते भारतीय किसानों की सोच के लिए नकारात्मक असर देता है।

सामान्यतः पूछे जाने वाले सवाल (FaQs) :

सवाल :- क्या पॉलीहाउस फार्मिंग के लिए सरकार किसी तरह की कोई सहायता उपलब्ध करवाती है ?

जवाब :- वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कई स्थानीय पंचायती सरकारें भी किसान भाइयों के लिए कई प्रकार की सब्सिडी और तकनीकी ज्ञान के लिए ट्रेनर की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपनी हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग स्कीम के तहत अलग-अलग जगह पर सेंटर खोल कर पॉलीहाउस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है।

सवाल :- क्या किसी भी पॉलीहाउस को बनाने से पहले पूरी प्लानिंग करना आवश्यक है ?

जवाब :- जी हां, किसी भी अन्य व्यवसाय की तरह ही पॉलीहाउस फार्मिंग के लिए भी पहले से पूरी प्लानिंग बनाएं और इसके लिए किसान भाई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप अपने पॉलीहाउस को संचालित करने के लिए काम में आने वाले तकनीकी ज्ञान और वित्तीय सहायता के अलावा बाजार से जुड़ी संबंधित जानकारियों के बारे में लिस्ट तैयार करके ही फार्मिंग की शुरुआत करें।

सवाल :- क्या पॉलीहाउस फार्मिंग के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता होती है ?

जवाब :- वर्तमान में कृषि मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार पॉलीहाउस फार्मिंग के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, हालांकि किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि पॉलीहाउस बनाने के दौरान बची हुई पॉलीथिन को खुले में ना फेंके।

आशा करते हैं कि हमारे सभी किसान भाइयों को Merikheti.com के द्वारा पॉलीहाउस फार्मिंग से जुड़ी यह जानकारी पसंद आई होगी और भविष्य में बदलती जलवायुवीय परिस्थितियों से बचने के लिए आप भी कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन की राह पर चलते हुए पॉलीहाउस फार्मिंग में जरूर हाथ आजमाना चाहेंगे।

किसान समाचार

आज सरकार ने किसानों को दिवाली का गिफ्ट देते हुए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया के साथ साझा की। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से लेकर 9 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है। नई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी जारी कर दिया गया है।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि गेहूं की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है, जिसके बाद अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार से जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 100 रुपये की वृद्धि की गई है। वृद्धि के बाद अब जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 1735 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

इन फसलों के साथ ही चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 5335 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। चौथी फसल है मसूर, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिसके बाद अब मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

इस लिस्ट में पांचवां नाम है सरसों का, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से सरसों 5050 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 5450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा। सरसों के साथ ही सूरजमुखी के दाम में 209 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। अब सूरजमुखी 5,441 रुपये प्रति क्विंटल की जगह पर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा।

मेरी खेती

MERIKHETI.COM